भलाई करना मानव का सबसे शानदार कर्तव्य है

पाकिस्तान का पागलपन

आतंक का समर्थक कोई देश कितना निर्लज्ज हो सकता है, यह पहलगाम के भीषण आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के सैन्य अफसरों, नौकरशाहों और नेताओं की प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है। पहले तो पाकिस्तान आतंकी घटनाओं में अपना हाथ मिलने पर तरह-तरह की सफाई देता था, खुद को आतंकवाद से पीड़ित होने की बात करता था और आतंकी देश की अपनी छवि सुधारने का दिखावा करता था, लेकिन अब तो वह पूरी बेशर्मी पर उतर आया है। इसका पता वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान से मिलता है कि हम 30 वर्षों से आतंकी तैयार करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने यह गंदा काम अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के कहने पर किया, लेकिन क्या इन देशों ने जिहादी आतंक की फैक्ट्रियां तैयार करने के लिए उसे बंधक बना लिया था? सब जानते हैं कि वह डालरों के लालच में और इस्लामी जगत का अगुआ बनने के लिए यह सब कर रहा था। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से भी गंदा काम लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक ने तब किया, जब पहलगाम हमले को लेकर वहां रह रहे भारतीय अपना रोष प्रकट कर रहे थे। इस राजनयिक ने अपने उच्चायोग की बालकानी पर आकर भारतीयों का गला काटने की धमकी दी। गनीमत है कि उसने अपने हाथ में चाकू नहीं थामा। उसने इस्लामिक स्टेट के खूंखार जिहादियों जैसा इशारा कर पाकिस्तान को तो शर्मसार किया ही, यह भी बताया कि वहां के शासन के उच्चस्तर पर कैसी घृणित मानसिकता वाले लोग प्रवेश कर गए हैं। इस पर हैरानी नहीं कि भारतीयों का गला रेतने का इशारा करने वाला राजनयिक मूलतः पाकिस्तान का कर्नल है, जो लंदन में रक्षा सलाहकार के रूप में तैनात है। पाकिस्तान को तो उसकी इस हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, लेकिन ब्रिटेन को इस पर सोचना चाहिए कि क्या वह अपनी धरती पर ऐसे राजनयिक को सहन कर सकता है? इस राजनयिक की हरकत से यह और अच्छे से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तानी सेना किस तरह किसी जिहादी संगठन में तब्दील हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ही हैं, जो जिहादी मौलाना की तरह नफरत भरे भाषण करते हैं। एक ऐसा ही भाषण उन्होंने पहलगाम हमले के सप्ताह भर पहले ही दिया था। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनके जवाब में उसकी ओर से जैसे बयान आए, वे भी यही बताते हैं कि वह भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। कोई परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है तो कोई सिंधु जल समझौता रोकने के फैसले को युद्ध की घोषणा जैसा बता रहा है।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

धार्मिक पर्यटन के मामले में बिहार किसी भी दूसरे राज्य से पीछे नहीं है। यह एक पंथ ही नहीं, बल्कि कई पंथों के प्रवर्तकों की ज्ञान, कर्म व निर्वाण स्थली रही है। बुद्ध ने बिहार आकर ही ज्ञान प्राप्त किया था। दशमेश गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली भी यहीं है। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल पावापुरी में है। देश ही नहीं, विदेश से भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। बोधगया, वैशाली, पटना साहिब एवं राजगीर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु आते हैं और अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा निवेदित करते हैं। प्रदेश में बुद्ध, जैन व सिख सर्किट के साथ ही रामायण सर्किट पर काम हो रहा है। रामायण सर्किट सरकार की प्राथमिकता में है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर बन गया है। इसी तरह सीतामढ़ी में माता जानकी की जन्मभूमि पुनौराधाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी है। माता जानकी का मंदिर भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही भव्य बनेगा। जो रामायण सर्किट का हिस्सा होगा। सरकार ने तय किया है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाली एजेंसी ही पुनौराधाम मंदिर और यहां के विकास के लिए नक्शा तैयार करेगी। सरकार पहले ही 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को 120 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुकी है। इसके अलावा पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु 23.66 करोड़ की योजना भी स्वीकृत की जा चुकी है।

मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण से बड़ी संख्या में देश-विदेश से श्रद्धालु आएंगे और धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

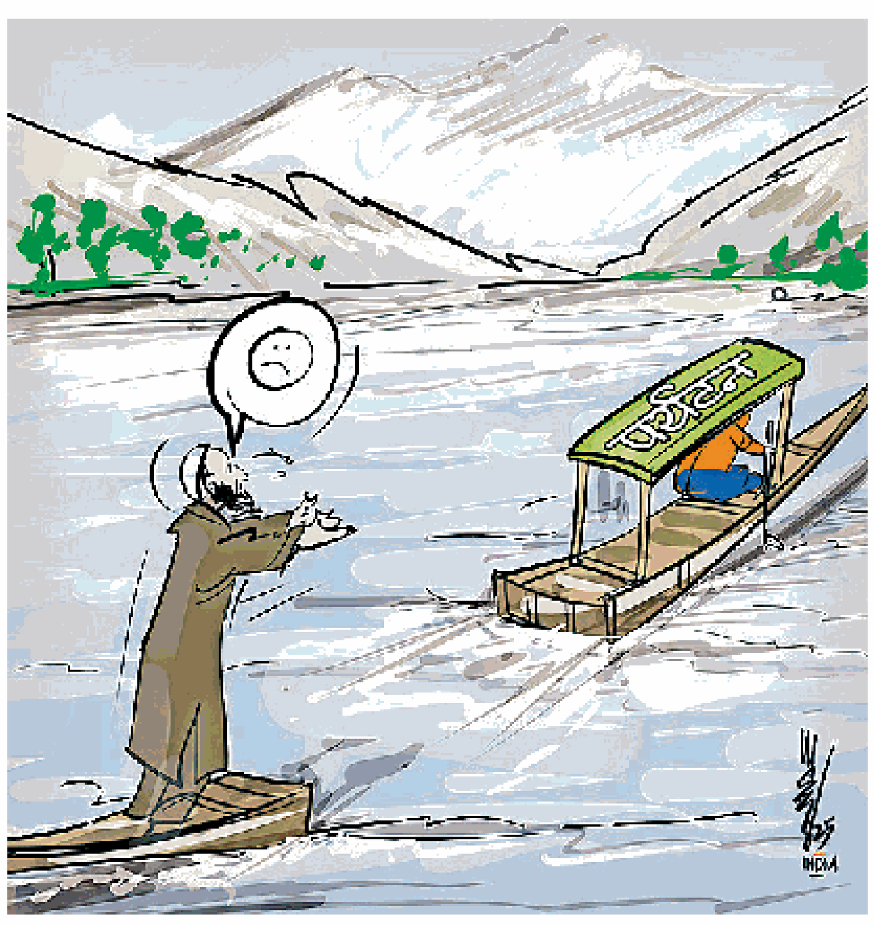

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या शिमला समझौता रद करना पाकिस्तान के लिए ही आत्मघाती सिद्ध होगा?

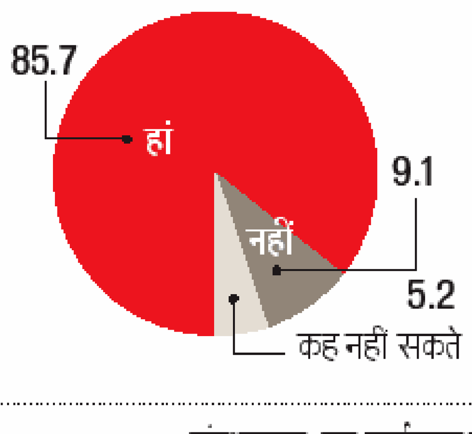

आज का सवाल
क्या राहुल गांधी को कोर्ट की फटकार के बाद अन्य नेता भी गैर जिम्मेदार टिप्पणियां करने से बाज आएंगे?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

न भूलें और न ही माफ करें

संजय गुप्त

पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के जनरलों, नौकरशाहों और नेताओं की प्रतिक्रिया बहुत ही भोंडी, उकसावे, आतंक का महिमामंडन करने और उसके साथ बेशर्मी से खुलकर खड़े होने वाली है

पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकियों की ओर से जिस तरह पर्यटकों से उनका मजहब पूछकर हत्या की गई, वह मानवता को कलंकित करने वाली ऐसी बर्बर घटना है, जिसकी मिसाल मुश्किल से मिलती है। जिहादी आतंकियों ने पहले भी तमाम घटनाओं को अंजाम दिया है, पर कम से कम भारत में यह पहली बार है, जब लोगों का मजहब पता कर हत्या की गई हो। साफ है आतंकी मजहबी उन्माद से प्रेरित थे। आतंकियों की ओर से इस तरह हत्या करने का एक मकसद भारत में हिंदू-मुस्लिम खाई पैदा करना भी था। यह अच्छा है कि उनके और पाकिस्तान के इस मकसद को पूरा न होने देने के लिए भारत के लोगों ने कमर कस ली है। मुस्लिम समाज ने पहलगाम की घटना का जिस तरह विरोध किया, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और कहा कि इस घटना ने इस्लाम को बदनाम किया है, वह स्वागतयोग्य है। देश में आगे भी सद्भाव बना रहे, यह देखना सभी समुदायों की जिम्मेदारी है।

पहलगाम की घटना उन चुनिंदा आतंकी घटनाओं जैसी है, जिसने दुनिया का आतंक के प्रति सोच बदला। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने स्थानीय आतंकियों से मिलकर इस घटना को अंजाम इसलिए भी दिया, ताकि यह दिखा सकें कि कश्मीर का माहौल बदला नहीं और वहां शांति नहीं लौट रही है। पाकिस्तान को कश्मीर में सामान्य होती स्थितियां रास नहीं आईं और उसने पहलगाम हमले की साजिश रची। पाकिस्तान से आतंकी कश्मीर में घुसने की कोशिश करते ही रहते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं और कुछ कश्मीर के आतंकियों से मिलकर आतंक को बढ़ावा देते हैं। यह सिलसिला इसलिए रुक नहीं रहा, क्योंकि कश्मीर में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो जिहादी मानसिकता से ग्रस्त हैं और इस मुगालते में हैं कि वे पाकिस्तान की मदद से आतंक के सहारे कश्मीर को मजहब के नाम पर आजाद करा लेंगे। इसीलिए वे आतंक की राह पर चलते रहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान उन्हें उकसाता ही नहीं है, हथियार और प्रशिक्षण देने के साथ हर तरह की मदद भी देता है। इन मुट्ठी भर लोगों की पहचान तब संभव है, जब कश्मीर की जनता उनके खिलाफ खुलकर खड़ी हो। पहलगाम की घटना के बाद अनेक लोग खड़े हुए, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि पर्यटकों पर कहर बरपाने वाले आतंकी छिपने में सफल रहे। आखिर किसी ने तो उनकी मदद की होगी।

कश्मीर में स्थितियां सामान्य हो रही हैं, यह संदेश भारत सरकार लगातार देश-दुनिया को दे रही थी। इसके लिए वहां जी-20 सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम और विधानसभा चुनाव कराए गए, पर कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं था। वहां आतंकियों और उनके समर्थकों की गतिविधियां जारी थीं। इसी कारण वहां आतंकी घटनाएं हो रही थीं, जिनमें सेना को भी निशाना बनाया जा रहा था। इन घटनाओं की तह तक जाने की जरूरत थी। पहलगाम की घटना इस ओर संकेत करती है कि कश्मीर में कुछ ऐसे आतंकी तत्व भी शांति के पक्ष में होने का दिखावा करने लगे थे, जिन्हें आर्थिक लाभ के चलते पर्यटकों के आने से तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वे भारत से बैर करना और आतंकियों का साथ देना नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे सभी तत्वों की पहचान और धरपकड़ पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना आवश्यक था। आतंकी घटनाओं में कमी के बाद भी आतंक के प्रत्येक समर्थक की चुन-चुन कर कमर तोड़ी जानी चाहिए थी, ताकि वे पाकिस्तानी आतंकियों से मिलकर कोई कारनामा न कर पाते।

पहलगाम की घटना के बाद इस प्रश्न का जवाब भी मिलना चाहिए कि आखिर पहलगाम में जहां पर रोज दो-ढाई हजार पर्यटक पहुंच रहे थे, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? पहलगाम के पहले कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकी घटनाएं हुईं, उनके लिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। उड़ी में हमले के बाद सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इसके बाद पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान ने भारत की इन सैन्य कार्रवाइयों से सबक नहीं सीखा। वह सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर के नेतृत्व में फिर से पुरानी राह पर आ गया।

भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के साथ अन्य फैसले लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। भारत के फैसले पर पाकिस्तान ने कहा है कि इस समझौते से पीछे हटने का मतलब युद्ध के एलान जैसा है। फिलहाल जो मौजूदा ढांचा है, उसमें पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोकना तत्काल संभव नहीं, लेकिन भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है और तैयारी भी कर रहा है। पाकिस्तान जब तक सुधरने का नाम नहीं लेता, भारत को उस पर दबाव बनाए रखना होगा। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि आगे हालात जैसे भी हों, उसे भारत से पहले जितना पानी नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान ने उस शिमला समझौते को भी रद करने की धमकी दी है, जिसका कभी उसने सम्मान किया ही नहीं। वह इस समझौते के खिलाफ जाकर कश्मीर मसले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहा, नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता रहा और आतंकियों की घुसपैठ कराता रहा। शिमला समझौते के बाद भी कारगिल में घुसपैठ हुई और न जाने कितने आतंकी हमले। यदि पाकिस्तान शिमला समझौता रद करता है तो भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को नियंत्रण रेखा से पीछे धकेलकर पुरानी अंतरराष्ट्रीय सीमा तक खदेड़ सकती है। ध्यान रहे कि भारत की संसद का यह प्रस्ताव है कि गुलाम कश्मीर को वापस लिया जाएगा।

पहलगाम की घटना इतनी भयानक है कि इसका प्रतिकार होना तय है। यह वक्त बताएगा कि यह सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में सामने आएगा या पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाली किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई के रूप में या अन्य किसी रूप में, पर पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, उसे न तो भूला जा सकता है, न ही पाकिस्तान को माफ किया जा सकता है। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के जनरलों, नौकरशाहों और नेताओं की प्रतिक्रिया बहुत ही भोंडी, उकसावे, आतंक का महिमामंडन करने और उसके साथ बेशर्मी से खुलकर खड़े होने वाली है।

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

एक जैसे भूकंप और ट्रंप

हास्य-व्यंग्य

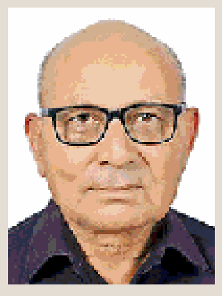

सूर्यकुमार पांडेय

अब तो ज्योतिषी भी कहने लगे हैं कि न तो ट्रंप का कुछ ठिकाना है, न भूकंप का। दोनों की ही भविष्यवाणी करना असंभव सा है

आज बहुत दिनों बाद मेरे कवि मित्र लतीफा लखनवी नमूदार हुए। वह जबसे 'अमेरिका रिटर्न' हुए हैं, 'ट्रंप' का तुक 'भूकंप' से मिलाते घूम रहे हैं। यूं भी आजकल इन दोनों से दुनिया में खलबली मची हुई है। वह उधर मुंह खोलते हैं, इधर भूकंप आने लगता है। मैंने उनसे पूछा, 'आप तो अमेरिका से लौटे हैं। अब तक तो आयात-निर्यात का अर्थ भी बखूबी समझ ही चुके होंगे। भैया बताओ, यह टैरिफ क्या बला है?'' लतीफा ने हंसते हुए कहा, ''दद्दू, आपको सच्ची बात बताता हूं। ट्रंप की जबान कमजोर है। वास्तव में वह 'टैरिफ' नहीं, 'तारीफ' बोलते हैं। वह जितना भी हो पा रहा है, टैरिफ, मेरा मतलब है, तारीफ झोंके पड़े हैं। तारीफ वह चीज है, जिसके दम पर दुकानदार ग्राहक को कैसा भी माल टिका देता है। ट्रंप भी इसी कोशिश में हैं। इसीलिए वह तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। सबको तारीफ बांट रहे हैं, पर अचरज है कि वह किसी और यहां तक कि उनके दोस्तों को भी रास नहीं आ रही है। इससे वह कंफ्यूज हैं और दोस्त-दुश्मन भी। वह कभी खूब तारीफ बांटते हैं और कभी इसमें कटौती करते हैं। इससे लोग चक्कर में पड़ जाते हैं और उनके चक्कर में शेयर बाजार घनचक्कर बन जाता है। आप बाजार और व्यापार के चक्कर में पड़ेंगे, तो शेयर मार्केट की मानिंद कभी ऊपर और कभी नीचे गोते ही लगाते रह जाएंगे। अभी शनि वक्री है। आप अपनी कुंडली की राशि की अंतर्दशा और जेब की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित कीजिए।''

मैंने कहा, ''वैसे तो अब तक कुल जमा एक दर्जन राशियां ही हैं। हर कोई इन्हीं में से एक न एक होता है, मगर मेरी जन्म की राशि कौन-सी है, यह आज तक साबित नहीं हो सका। हिंदी जन्मतिथि और समयानुसार मैं मीन राशि का हूं। मेरी मीन मेंटालिटी को देखकर इस पर एकबारगी विश्वास भी किया जा सकता है। मगर चूंकि मेरा घरेलू नाम 'स' से आरंभ होता है और मेरी थोड़ी-बहुत लोकप्रियता भी इसी नाम से है, इसलिए कुछ पंडितों के विचार से मैं कुंभ राशि का हूं। मेरी मटके जैसी तोंद से भी इसकी सेंट-परसेंट तस्दीक होती है। तीसरी और हाईस्कूल सर्टिफिकेट वाली जन्मतिथि के अनुसार मेरी राशि लिब्रा यानी तुला है। अंग्रेजी गणना को देखने पर मैं धनु राशि का कहा जाऊंगा। भारी भ्रम है।''

लतीफा ने कहा, ''दद्दू, संशय विनाश का कारक है। आप तो उन ज्योतिषियों से मिलिए, जो ट्रंप से लेकर भूकंप की भविष्यवाणी करते हैं।'' मैंने कहा, ''भैया, वह भी कर के देख लिया है। ऐसे ज्योतिषी कहते हैं कि अब न तो ट्रंप का कुछ ठिकाना है, न भूकंप का और न आप का। कुछ बताना असंभव है। इस पर अपनी इस प्राब्लम को लेकर मैं एक प्रोफेशनल ज्योतिषी से मिला। उसने मेरी जन्मराशि में पांचवां आयाम जोड़ते हुए विचारा कि मुझे शर्तिया कन्या राशि का होना चाहिए। उसने अपने लैपटाप पर मुझे दिखलाया कि देखिए, एक घड़ी का डिफरेंस होने पर किस तरह ग्रह-नक्षत्र बदल जाया करते हैं और उसी के अनुसार जन्मराशि निर्धारित होती है।'' अब मैं पांच राशियों का स्वामी हूं। हर रोज सुबह उठकर पांच राशियों का भविष्यफल एक साथ बांचता हूं। उस रोज शाम तक जिस राशि का फलित सटीक बैठता है, मैं यह मान लेता हूं कि वही मेरी जन्म की सच्ची राशि है। फिर एक नई सुबह होती है। मेरी यह धारणा चेंज हो जाती है। तब मैं किसी और राशि का होता हूं। इस तरह मेरी जिंदगी में राशि का निर्धारण मेरे बर्थ टाइम से न होकर अखबार में प्रकाशित भविष्यफल से हो रहा है।''

लतीफा लखनवी ने ठहाका लगाया और कहा, ''दद्दू, लौट कर मिलूंगा। अभी अमेरिका की एक और ट्रिप पर निकलना है और वहां ट्रंप के साथ भूकंप को भी समझना है।'' फिर आकर आपको भी समझूंगा।

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

तथ्य-कथ्य | कश्मीर जाने वाले पर्यटक

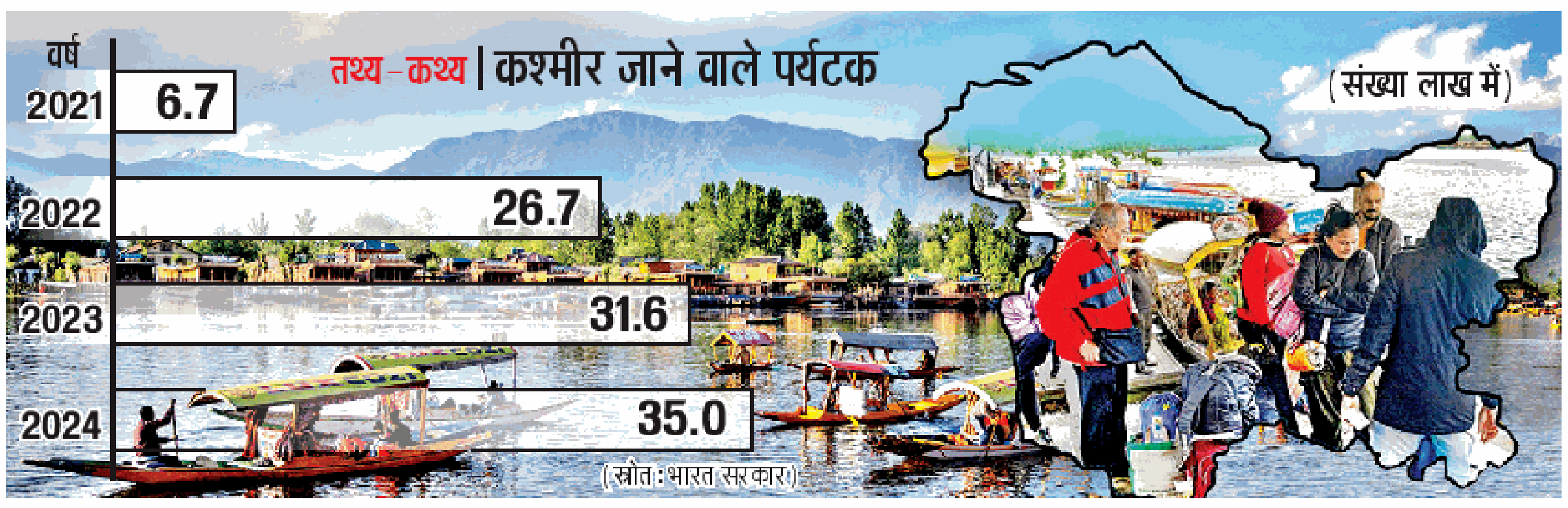

ऊर्जा

सत्य दर्शन

अद्वैत वेदांत दर्शन जगत को मिथ्या और ब्रह्म को सत्य मानता है। संसार और जीवात्मा (व्यक्तिगत आत्मा) भी ब्रह्म के ही भाग हैं। ब्रह्म परम सत्य है, जो सभी का स्रोत और आधार है। भ्रम संसार को एक अलग वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करता है। ब्रह्म के सत्य होने का अर्थ है कि जो भी है जड़ या चेतन, सब उस एक परमसत्ता से ही अभिव्यक्त हुए हैं। अंत में उसी में ही विलीन होंगे। संपूर्ण साकार जगत उसकी ही अभिव्यक्ति है, पर जगत मिथ्या है यानी जगत जैसा दिखता है वह वास्तविकता में है नहीं। यहां जगत को 'असत्य' नहीं कहा गया है, परंतु 'मिथ्या' कहा गया है। असत्य वह है जो कभी था ही नहीं, पर मिथ्या वह है जो सिर्फ आंखों से दिख रहा है, लेकिन उसका मूल रूप कुछ और ही है।

सत्य के अनुभव भी सबके अलग-अलग होते हैं। इसलिए सत्य भी तीन प्रकार से प्रकट होता है- प्रतिभासिक सत्य, व्यावहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। प्रतिभासिक सत्य, जो व्यक्ति के निजी अनुभव का परिणाम होता है। जैसे स्वप्न में देखी गई घटना हर व्यक्ति का निजी अनुभव है, जो किसी और ने नहीं देखा, पर स्वप्न टूटने पर समझ आ जाता है कि स्वप्न में देखी गई घटना एक मिथ्या अनुभव है। यहां व्यक्ति कहता है, 'जगत है, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं'। व्यावहारिक सत्य में एक ही घटना का सबका अलग या एक समान अनुभव हो सकता है, पर घटना घटी है यह अनुभव तो सब करते हैं। यहां व्यक्ति कहता है, 'जगत है इसलिए मैं अनुभव कर रहा हूं', परंतु ये दोनों ही प्रकार के सत्य मिथ्या होते हैं, क्योंकि दोनों ही देश, काल एवं परिस्थिति के सापेक्ष हैं। अतः सत्य वही एक पारमार्थिक सत्य होता है जिस पर जगत निर्भर है, जो देश, काल एवं परिस्थिति की परिधि के नियंत्रण से परे है और जो सभी कालों में शाश्वत तथा सर्वव्यापी है। वेदांत हमें उस पारमार्थिक सत्य से एकाकार करने का ही मार्ग है।

आदित्य नारायण अवस्थी

हम सब सक्रिय हैं

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर इन दिनों विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय मुख्य रूप से सक्रिय हैं। इन मंत्रालयों के मंत्री ही सुर्खियों में छाए हुए हैं। ऐसे में अन्य मंत्रालय भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सक्रिय दिखने के प्रयास में पीछे नहीं रहना चाहते, ताकि लोगों को उनकी भी सक्रियता नजर आए। एक केंद्रीय मंत्री ने तो कुछ नहीं सुझा तो एक्स प्लेटफार्म पर पाकिस्तान को लेकर वर्षों पुराने अपने एक इंटरव्यू को ही पोस्ट कर दिया, ताकि पाकिस्तान के मामले में उनकी भी चर्चा हो। इसी तरह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पाकिस्तान के खिलाफ व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश में जुट गया है कि कैसे पाकिस्तान जाने वाले सामान को रोका जा सके। जाहिर तौर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी पाकिस्तान पर प्रहारों की पहल में पीछे नहीं रहना चाहता है।

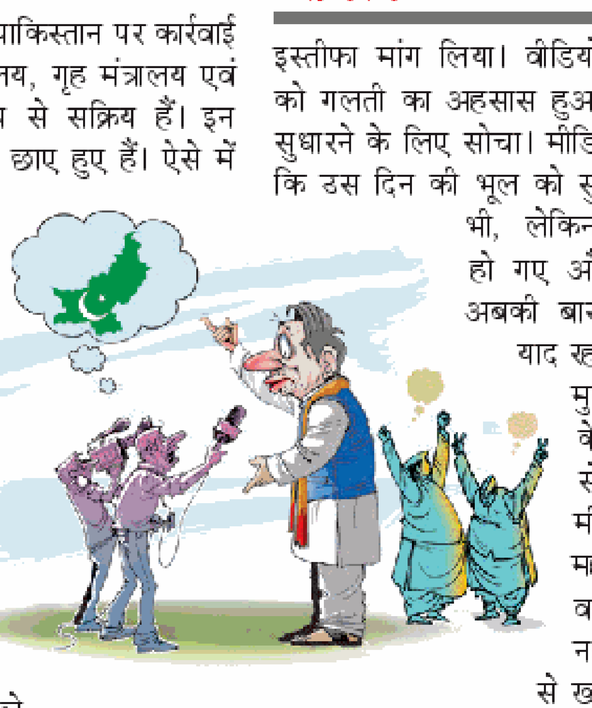

भूल सुधार में भी भूल

झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री से गलती हो गई। उन्होंने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के लिए केंद्र या जम्मू-कश्मीर सरकार को नहीं, बल्कि हिमाचल सरकार को जिम्मेदार बता दिया। वहां के सीएम से इस्तीफा मांग लिया। वीडियो वायरल हुआ तो मंत्री को गलती का अहसास हुआ। तो मंत्री ने गलती को सुधारने के लिए सोचा। मीडिया को बुलाया और कहा कि उस दिन की भूल को सुधारना चाहता हूं। सुधारा भी, लेकिन इसमें भी मंत्री फेल हो गए और नई गलती कर बैठे। अबकी बार उन्हें जम्मू-कश्मीर तो याद रहा, लेकिन वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बदले महबूबा मुफ्ती से इस्तीफा मांग लिया। मीडिया फिर हैरान कि महबूबा क्यों इस्तीफा दें, वह तो विपक्ष की नेता भी नहीं। खैर मीडिया को मंत्री से खबर चाहिए थी, जो मिल गई थी। सुना है कि मंत्री अब तीसरी बार भूल सुधार का प्रयास कर रहे हैं।

राजरंग

तो नड्डा ही रहेंगे अध्यक्ष

मई के पहले हफ्ते में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया फिलहाल टल गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भाजपा के बाकी बचे प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव रुक गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अभी पांच राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी है। साफ है कि तब तक जेपी नड्डा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। नड्डा का तीन साल का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही पूरा हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए 30 जून, 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। उसके बाद से अब लगभग एक साल होने वाला है, पर नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जेपी नड्डा की अध्यक्षीय पारी अभी जारी रहेगी।

वाह रे संवाद

अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बूथ स्तर तक अपना मजबूत ढांचा बनाने के लिए जिला संगठन में व्यापक बदलाव से लेकर कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की जोर-शोर से एक बार फिर घोषणा की। ऐसी पहल की उम्मीद से पार्टी के जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक रूप से आस जगती है, पर दिलचस्प यह है कि एक ओर जुड़ाव और संवाद बढ़ाने की घोषणा की जाती है तो दूसरी तरफ ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं का पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से मिलने-जुलने का मौका विरले ही मिलता है। ऐसे में जमीन से जुड़े कांग्रेसी अपने क्षेत्र-प्रदेश में पार्टी की मजबूती के लिए शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिख कर कई अहम सुझाव देते हैं, मगर उनके पत्रों संज्ञान तक नहीं लिया जाता। अधिवेशन के चंद दिन बाद ही चार दशक से अधिक से कांग्रेस का झंडा उठा रहे बिहार के एक वरिष्ठ कांग्रेसी से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में अपने इस दर्द को साझा करते मिले। उनमें से एक ने तो कहा कि हिंदी में पत्र लिखने के बाद वह अपने जानकारों से उसका अंग्रेजी में अनुवाद करा कर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को कई बार भेजे, मगर आज तक उनका जवाब नहीं आया। ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने की घोषणा जमीन पर कितनी उतर पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

X पोस्ट

'पहलगाम में चुन-चुनकर 26 हिंदू मारे गए। यह एक भयंकर इस्लामिक आतंकी हमला था।' अमेरिका की यह टिप्पणी सबसे दो टूक है। न कोई पाखंड और न ही शब्दों के जरिये कोई बौद्धिक धूर्तता की गई है।
अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

देश के आत्मा पर हमला करने वाले आतंकी चाहते थे कि हमारे घर में हिंसा हो। इसलिए उन्होंने धर्म पूछकर मारने, मोदी को बता देने, कलमा पढ़ाने जैसी हरकतें कीं, लेकिन भारत की पंथनिरपेक्षता के आगे वे हार गए। हमें बांट नहीं पाए। आदेश रावल@AadeshRawal

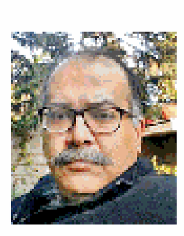

पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर का कहना सही है कि भारत और पाकिस्तान के सपने और आकांक्षाएं समान नहीं हैं। भारतीयों का सपना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, जीवन में आगे बढ़ना है, जबकि पाकिस्तानियों का सपना अपने बच्चों को जिहादी बनाकर दुनिया में आतंक फैलाना है। भारतीयों की आकांक्षा एलन मस्क या मुकेश अंबानी जैसे उद्यमी बनने की है, जबकि पाकिस्तानियों की इच्छा हाफिज सईद जैसे आतंकी बनने की है। सुशांत सरीन@sushantsareen

जनपथ

खोले पाकिस्तान खुद अब अपनी ही पोल,
दुनिया के आतंक में माने अपना रोल।
माने अपना रोल झोल जो करता आया,
जब मरते निर्दोष उसी की रहती माया।
करते 'गंदा काम' वहां के मंत्री बोले,
अनजाने सच बोल पोल अपनी ही खोले!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 16

****

एक्स से
वाद-विवाद अहं और अहंकार को खत्म करता है। यह अहंकार व्यक्ति को ही नहीं, संस्था को भी धूमिल कर देता है, इसीलिए प्रजातंत्र के लिए जरूरी है अभिव्यक्ति और संवाद- जगदीप धनखड़/ उप-राष्ट्रपति, भारत

कश्मीर में अनुच्छेद 370 की विदाई के बाद से जिस तेजी से विकास हुआ है, उससे वहां के नौजवानों में उम्मीद जग पड़ी है कि वे भी समूचे देश के साथ कदमताल कर सकते हैं। पहलगाम के हमले ने उनकी नेक उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यही वजह है कि पूरे देश के साथ कश्मीर घाटी भी गुस्से से तप रही है। वे आम कश्मीरी थे, जिन्होंने अगले दिन कश्मीर बंद का आह्वान किया। हमें कश्मीरियों की इस राष्ट्रभावना का सम्मान करना चाहिए।

आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

भरोसा कायम रखने का वक्त

शशि शेखर

आजकल

'पहलगाम में हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने यह हमला किया है, उन आतंकियों और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये शब्द मधुबनी की धरती पर बोल रहे थे, तब उनके चेहरे पर गुस्से की गहन छाया साफ देखी जा सकती थी। यह पहला मौका था, जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सभा में ऐसे कठोर शब्द बोले। ये ताकतवर वाक्य उन लोगों के जख्मों पर मरहम की तरह थे, जिन्होंने अपने घर के लोग खोए हैं। ये अल्फाज आहत देशवासियों को भी भरोसा दिला रहे थे कि हम सिर्फ कूटनीतिक कार्रवाई तक नहीं रुकेंगे।

मोदी क्या करने जा रहे हैं?

इस सवाल का जवाब देना नामुमकिन है, लेकिन इतना तय है कि जो होगा, वह अप्रत्याशित और अकल्पनीय होगा। भरोसा न हो, तो 15 फरवरी, 2019 की ओर लौटें। समूचा देश उस वक्त पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या से आहत था। उस दिन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए उन्होंने कहा था- आतंक के दोषियों और उन्हें मदद देने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षाबलों को कार्रवाई की पूरी छूट दे दी गई है। पाकिस्तान इस भ्रम में न रहे कि वह भारत को अस्थिर कर सकता है। पाकिस्तान सहित कुछ सियासतदां इसे महज चुनावी भाषण मानने की भूल कर बैठे थे। अगले दस दिन के भीतर बालाकोट में जो हुआ, उसे पूरी दुनिया ने अचरज से देखा।

इससे पहले भारत आतंकवाद से आहत होने के बाद बस गाल बजाकर रह जाता था। इस बार हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर न केवल निर्धारित ऑपरेशन को अंजाम दिया, बल्कि सरकार ने उसे दुनिया को बताने और जताने में कोई संकोच नहीं किया था। यह भारतीय रणनीति में सार्थक बदलाव का लम्हा था। तय हो चुका था कि अब भारत-भूमि को रक्त-स्नान कराने वाले कहीं भी हों, बख्शे नहीं जाएंगे। जरूरी हुआ, तो इसके लिए हम सीमा पार करने से कतई नहीं हिचकेंगे।

पुलवामा को छह बरस बीत चुके हैं। इस दौरान दुनिया और उसके तौर-तरीकों में जमीन-आसमान का फर्क आ चुका है। यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई और इजरायल के गाजा सैन्य अभियान ने विश्व राजनय के सिद्धांतों को नया चोला पहना दिया है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बेहद दबाव के बावजूद न पुतिन झुके और न ही नेतन्याहू। उनकी फौजें आज भी अपने 'दुश्मनों' का सफाया करने में जुटी हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड और कनाडा को हथियाने का दंभ खुल्लमखुल्ला भरते हैं। क्या भारत ऐसा कर सकेगा?

इस पर अभी कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं होगी, मगर यह जान लीजिए कि पाकिस्तानी परमाणु बम और उसके दुरुपयोग की धमकियां मोदी की राह नहीं रोक सकतीं। वह पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के जरिये इसकी मुनादी कर चुके हैं। दुनिया के अन्य देश भी पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी से आजिज आ चुके हैं। यह अकारण नहीं है कि पहलगाम नरसंहार के बाद विश्व के सभी प्रमुख देशों ने भारत और भारतीयों के साथ एकजुटता दिखाई है। इस साथ का बदली हुई परिस्थितियों में बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है।

देश के अंदर भी प्रमुख विपक्षी नेताओं ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद करते हुए एकजुटता दिखाई है। मैं कभी युद्ध का समर्थन नहीं करता और यह भी मानता हूं कि मीडिया के दबाव या जन-इच्छाओं से लड़ाइयां नहीं लड़ी जानी चाहिए, लेकिन जब पानी नाक तक चढ़ आए, तो फिर हाथ-पैर हिलाने ही पड़ते हैं। यह समय सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े होने का है। पहलगाम में जान गंवाने वालों को इससे बेहतर कोई और श्रद्धांजलि नहीं हो सकती।

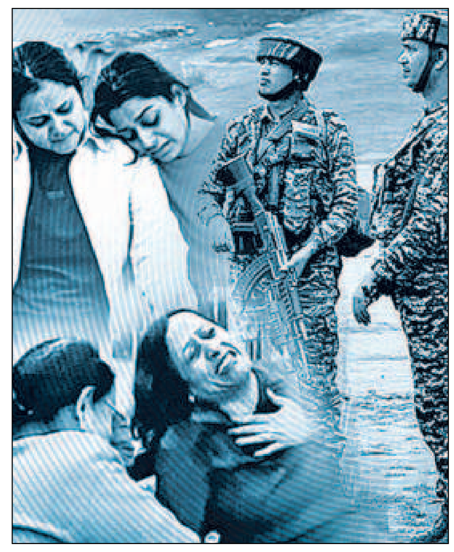

यहां उन खलनायकों का जिक्र जरूरी है, जो इस नेक काम में रोड़े अटकाने की बचकानी कोशिशें कर रहे हैं।

मधुबनी में प्रधानमंत्री की गर्जना से ऐन पहले की रात आगरा में कुछ लोगों ने बिरयानी बेचने वाले एक कारोबारी की हत्या कर दी। उसका सहायक भी गोली लगने से घायल हो गया। इस घटना के तत्काल बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। इसके जरिये खुद को एक कल्पित हिंदूवादी संगठन का ताबेदार बताते हुए दो सशस्त्र युवक इस हत्याकांड को पहलगाम नरमेध से जोड़ते हुए, सांप्रदायिक विषवमन कर रहे थे। उसी दिन नोएडा के तमाम लोगों को एक रिकॉर्डेड कॉल मिली थी। उसमें भी एक धर्म विशेष के लिए जहर बोला गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हो सकता है कि जब तक ये पंक्तियां आप तक पहुंचें, दोषी धरे जा चुके हों, पर वे अकेले नहीं हैं।

सोशल मीडिया के जरिये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले सैकड़ों हैंडल इस समय सक्रिय हैं। ये लोग जाने-अनजाने उन दहशतगर्दों का काम आसान कर रहे हैं, जो कश्मीर को सिर्फ देश की मुख्यधारा से अलग नहीं करना चाहते, बल्कि समूचे मुल्क को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। पहलगाम की बैसरन घाटी में जिस अपमानजनक तरीके से धार्मिक पहचान पता कर गोलियों से भूना गया, उससे नाराजगी स्वाभाविक है। इसके बावजूद हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सैलानियों की रक्षा के लिए भिड़ पड़े एक कश्मीरी युवक को उस दौरान जान गंवानी पड़ी। पीड़ितों को फौरी मदद भी स्थानीय लोगों से मिली। वे सभी मुसलमान थे।

इससे पहले ऐसा कम देखने को मिलता था।

कश्मीर में अनुच्छेद 370 की विदाई के बाद से जिस तेजी से विकास हुआ है, उससे वहां के नौजवानों में उम्मीद जग पड़ी है कि वे भी समूचे देश के साथ कदमताल कर सकते हैं। पहलगाम के हमले ने उनकी इन नेक उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यही वजह है कि पूरे देश के साथ कश्मीर घाटी भी गुस्से से तप रही है। हमले के दिन ही लोग सड़कों पर 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारों के साथ उतर पड़े थे। वे आम कश्मीरी थे, जिन्होंने अगले दिन कश्मीर बंद का आह्वान किया। उन्हें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते देख मुझे वे दिन याद आ गए, जब घाटी में सरेआम पाकिस्तानी झंडे लहराया करते थे। हमें कश्मीरियों की इस राष्ट्रभावना का सम्मान करना चाहिए।

इस बीच कुछ खबरें यह भी आईं कि अन्य प्रदेशों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी करने की कोशिश की। इस तरह की हर हरकत को कड़ाई से रोकना होगा। हमें पीड़ित परिवारों के साथ कश्मीर के लोगों का भी भाईचारे की भावना से साथ देना होगा, क्योंकि उन्होंने शेष भारत से अधिक 'अपने' खोए हैं और हर किस्म का नुकसान उठाया है।

ध्यान रहे, यह समय एकजुटता का है, अलगाव का नहीं।

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

जीने की राह

अमात अल-सलाम अल-हज
मानवाधिकार कार्यकर्ता

अमन के लिए तरसते यमन की एक बेमिसाल महिला

पिछले नौ सालों में अमात के संगठन ने 9,500 अपहृतों के मामलों का दस्तावेजीकरण किया है, उनके मुकदमे लड़े हैं। 950 से अधिक अगवा लोगों को रिहा कराने में उनको कामयाबी मिली है। अब वह यमन व अरब में एक-दूसरे के यहां कैद बेगुनाहों की रिहाई की राह आसान बना रही हैं।

एक ऐसे वक्त में, जब पूरा भारत पहलगाम की पीड़ादायक घटना से मर्माहत है और दहशतगर्दों की करतूत को लेकर इस उलझन में है कि क्या यह वाकई आतंकी कार्रवाई थी या मजहबी जेहाद, तब अमात अल-सलाम अल-हज की चर्चा मुनासिब जान पड़ती है। अमात ने मजहब के नाम पर दहशत फैलाने और जुल्म करने वालों के खिलाफ यमन की हजारों माओं को एकजुट करके उनकी पीड़ा को एक ऐसी बुलंद आवाज में तब्दील कर दिया, जिसकी अनुगूंज दुनिया के कोने-कोने में सुनी गई। एक अस्थिर मुल्क में अमात की यह कोशिश किसी हिमाकत से कम न थी। मगर तारीख उन्हें इंसानियत की इसी खिदमत के लिए याद भी रखेगी। ट्रंप प्रशासन ने अमात को दुनिया की आठ सबसे बहादुर औरतों में शुमार करते हुए हाल ही में सम्मानित किया है।

यमन दक्षिण-पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। करीब साढ़े तीन करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क की शत-प्रतिशत आबादी मुस्लिम है। इसी के 'तेज' नामक शहर में 59 साल पहले अमात पैदा हुईं, मगर उनकी परवरिश राजधानी 'सना' में हुई। अमात ने जब होश संभाला, तब वहां वाम रुझान वाले सलीम रुबाया अली की हुकूमत थी। अमात ने शुरू में दीन की पढ़ाई की और फिर स्कूल-कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ती हुई वह यमन यूनिवर्सिटी तक पहुंचीं, जहां से उन्होंने इस्लामिक स्टडीज में मास्टर की डिग्री हासिल की।

सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऊंची तालीम ने अमात को वह मुकाम दिला दिया था, जो शायद परदेदारी वाले समाज की हर औरत की हसरत हुआ करती है। साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर अमात को मर्द बिरादरी में भी भरपूर सम्मान मिलता था। उन दिनों यमन में कमोबेश स्थिरता थी, हालांकि राजनीति व नागरिक अधिकार के क्षेत्र में सत्ता का रवैया दमनात्मक ही था। ऐसे में, साल 2011 में उठी अरब क्रांति की आग ने यमन को भी अपनी चपेट में लिया। राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह की निजामत को वर्षों बाद गंभीर चुनौती मिली थी। भारी संख्या में लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। सालेह की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अमात ने भी विरोध-प्रदर्शनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था।

नागरिक अधिकारों की हिमायत वाली अमात की तकरीरें तब लोगों को खूब पसंद आईं। उसी वक्त सना के पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनेताओं से उनका राब्ता कायम हुआ और वह सुर्खियों में आईं। मगर सालेह की विदाई के बाद जब कट्टरपंथी हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना और दूसरे खित्तों पर कब्जा किया, तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। सबसे पहले तो उन्होंने पत्रकारों की धरपकड़ शुरू की, फिर नागरिक अधिकारों, राजनीतिक आजादी, स्कूलों, औरतों के अकेले आने-जाने पर तमाम तरह के पहरे बिठा दिए। बड़ी

संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। जो लोग उठाए जाते, उनमें से ज्यादातर मासूम शहरी होते, फिर भी उन्हें राजधानी के अपराध जांच विभाग के सामने ले जाया जाता। उनमें से कई किशोर दोबारा लौटकर नहीं आए। उनकी माओं और बहनों के चीत्कार को सुनने वाला कोई न था।

बेबसी का आलम यह था कि जब ये महिलाएं जांच विभाग के दफ्तर अपने पति, बेटे या भाई का पता लगाने किसी मर्द रिश्तेदार के साथ पहुंचतीं, तो उस पुरुष सहयोगी को ही हिरासत में ले लिया जाता। उनकी यह तकलीफ अमात से देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि लोगों को अगवा करने में हूती गुट अकेला नहीं है, यमन में ऐसे कई हथियारबंद समूह हैं, जो नौजवानों को अगवा कर रहे हैं। ठीक उसी समय उनके भीतर 'ऐब्डक्टीज मदर्स एसोसिएशन' (एएमए) के गठन का ख्याल आया। अमात ने साल 2016 में इस गैर-लाभकारी संगठन की शुरुआत की। हालांकि, तब उनके पास न कोई जगह थी, न पैसे थे और न ही किसी का समर्थन था, लेकिन जज्बा था कि इन बेबस स्त्रियों की मदद करनी है। उन्होंने कुछ पीड़ित महिलाओं को इकट्ठा किया। उन्हीं में से एक ने सबके मिलने-जुलने के लिए अपना मकान मुहैया कराया। अमात के नेतृत्व में इन औरतों ने फैसला किया कि वे मिलकर अपने पति, पुत्र या भाई की रिहाई की कोशिश करेंगी।

रेडक्रॉस की मदद से उन्होंने जबरन लापता किए गए लोगों के दस्तावेजीकरण, सुबूत जुटाने और उनको शासन के सामने ठीक तरह से पेश करने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद तमाम सुबूतों के साथ बड़ी संख्या में ये महिलाएं अमात की सदारत में संबंधित विभागों या बागी समूहों के आगे प्रदर्शन करने लगीं। जाहिर है, इन औरतों को बांटा नहीं जा सकता था। इनका दुख साझा था। इनमें शिया समुदाय के लापता किशोर की मां का गम किसी सुन्नी पीड़ित मां-बेटी से कम या ज्यादा न था। उनके प्रदर्शनों का असर दिखने लगा। कई अपहृतों की रिहाई ने अमात और एएमए को नए हौसले दिए। आज इस संगठन से 60 से अधिक वकील, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता जुड़े हैं, जो जबरिया लापता किए गए लोगों का पता लगाने और फिर उनकी रिहाई में जी जान से सक्रिय हैं।

पिछले नौ सालों में अमात के इस संगठन ने 9,500 से अधिक अपहृतों के मामलों का दस्तावेजीकरण किया है, उन्हें उचित मंचों पर उठाया है, उनके मुकदमे लड़े हैं। 950 से अधिक अगवा लोगों को रिहा कराने में उनको अब तक कामयाबी मिली है। अब वह यमन और पड़ोसी मुल्क अरब में एक-दूसरे के यहां कैद बेगुनाह लोगों की रिहाई की राह आसान बना रही हैं। अमात अल-सलाम अल-हज चाहतीं, तो एक आरामदेह व सुकून भरी जिंदगी जी सकती थीं। मगर क्या तब वह इस कदर सुर्खरू हो पातीं? बकौल अमात, इन हजारों लोगों का अपहरण करने वाले, अपहृत होने वाले और उनकी रिहाई के लिए रात-दिन संघर्ष करने वाले, सब के सब हम-मजहब हैं। मगर कोई शैतान बन गया है, तो कोई फरिश्ता!

तमाम सुबूतों के साथ बड़ी संख्या में ये महिलाएं अमात की सदारत में संबंधित विभागों या बागी समूहों के आगे प्रदर्शन करने लगीं। जाहिर है, इन औरतों को बांटा नहीं जा सकता था। इनका दुख साझा था। इनमें शिया समुदाय के लापता किशोर की मां का गम किसी पीड़ित सुन्नी मां-बेटी से कम या ज्यादा न था।

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा

सावित्री बाई खानोलकर
विख्यात शिल्पी, डिजाइनर

जेनेवा से भागकर भारत आना पड़ा

ईश्वर की इच्छा नहीं थी या मेरे पुण्य में कमी रह गई कि मैं भारत-भूमि पर जन्म न ले सकी, किंतु अब मुझे भारत-भूमि पर रहने से कौन रोक रहा है? अब जिधर देखती हूं, भारत है और उसके सिवा कुछ सूझता नहीं। यदि मैं भारत न गई, तो यह जन्म बेकार चला जाएगा?

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः ... अर्थात सभी दिशाओं से अच्छे विचार मेरी ओर आएं। *ऋग्वेद* का यह संदेश वास्तव में भारतीय चेतना की एक पहचान है और ऐसी ही चेतना में जेनेवा की वह स्विस युवती डूबी रहती थीं। एक से बढ़कर एक सुंदर श्लोक भारत भूमि से गूंजते थे और वह भाव-विभोर हो जाती थीं। भारत के पास अनगिनत संत हैं और उनकी अनुपम चमत्कारी गाथाएं हैं। भारत पग-पग पर अद्भुत है, उसके ज्ञान की महिमा का अंत नहीं है। अहिंसा का विचार, शाकाहार का व्यवहार और संतोष का ऐसा प्रसार संसार में कहीं नहीं है। अंग्रेजों की दासता में भी भारत ने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं है, तो क्या ऐसे भारत से जुड़ने के अवसर को मैं छोड़ दूं? ईश्वर की इच्छा नहीं थी या मेरे पुण्य में कमी रह गई थी कि मैं भारत-भूमि पर जन्म न ले सकी, किंतु अब मुझे भारत-भूमि पर रहने से कौन रोक रहा है? अब तो जिधर देखती हूं, भारत है और भारत के सिवा कुछ सूझता नहीं। यदि मैं भारत न गई, तो यह जन्म बेकार चला जाएगा?

वह 19 साल की हो चली हैं और उन्हें लगता है कि पल-पल हाथ से फिसल रहा है, कहीं भारत जाने-रहने का अवसर भी न निकल जाए। जब वह भारत जाने की बात कहती हैं, तो रसियन मां शांत हो जाती हैं और हंगेरियन पिता साफ मना कर देते हैं। कहते हैं, 'पराए देश न जाओ। जिस भारतीय लड़के से तुमने संपर्क साधा, वह भारत चला गया। दो वर्ष बीतने को आए, वह पलटकर नहीं आया और तुम बेचैन हो कि तुम्हें भारत जाना है?'

युवती ने कहा, 'पिता जी, वह सीधे-सज्जन सैन्य अधिकारी हैं, वह अनुशासन नहीं तोड़ सकते। उन्हें भी मेरा इंतजार है, पर कब तक इंतजार करेंगे? उन्हें अपने देश में भी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन मुझे उन जैसा कोई कहां मिलेगा?'

फिर भी पिता ने सख्ती से इनकार कर दिया। युवती की चिंता चरम पर पहुंच गई। भारत में पुनर्जन्म की चर्चा है, पर हर किसी का पुनर्जन्म नहीं होता। पता नहीं, मेरा पुनर्जन्म न हो पाए और मैं कभी भारत-भूमि को देख न सकूं। अर्थात जो भी संभावना है, इसी जन्म में है, अभी नहीं, तो कभी नहीं। युवती ने दृढ़ता से फैसला लिया। तत्काल कुछ सामान समेटा, कुछ धन साथ लेकर घर से निकल पड़ीं भारत की ओर, और फिर पलटकर नहीं देखा।

पानी जहाज से उन्होंने पहले अटलांटिक महासागर पार किया और उसके बाद हिंद महासागर, करीब तीन सप्ताह की यात्रा के बाद वह भारत पहुंचीं। अपने प्रिय साथी सैन्य मेजर विक्रम रामजी खानोलकर से विवाह किया और उनका अपना नाम ईव यवोन मैडे डे मारोस से बदलकर सावित्री बाई खानोलकर हो गया।

उन्हें भारतीयता में उतर जाने की बहुत जल्दी थी। युद्ध स्तर पर उन्होंने हिंदी, संस्कृत, मराठी, भारतीय संगीत और कथकली नृत्य का ज्ञान हासिल किया। वह पहले से ही शाकाहारी थीं, उन्होंने अपने प्रमुख परिधान के रूप में साड़ी को अपना लिया। सिर पर पल्लू रखकर उन्होंने अपनी गृहस्थी को संभाल लिया। पति और उनके परिवार की सेवा का संकल्प भी उन्होंने बखूबी निभाया। उन्हें पति के साथ खूब यात्राएं करने और भारत को देखने-समझने का अवसर मिला। भारत के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया। कामकाज के बीच भी वह निरंतर पढ़ती रहती थीं। अवसर मिलते ही समाजसेवा में समर्पित हो जाती थीं। कुछ न कुछ रेखांकन या डिजाइन करती रहती थीं। कुछ न कुछ लिखती भी रहती थीं। भारतीय और खासकर मराठी संतों के जीवन का न केवल उन्होंने अध्ययन किया, बल्कि उन पर एक ऐतिहासिक पुस्तक *सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र* की रचना भी की। जल्दी ही उनकी गिनती भारतीय ज्ञान के सच्चे विद्वानों में होने लगी।

भारत जब आजाद हुआ, तब मेजर जनरल हीरा लाल अटल ने सावित्री बाई खानोलकर (1913-1990) को भारतीय सैन्य पदक डिजाइन करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। सावित्री बाई ने विचार किया कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप सैन्य पदक कैसे होने चाहिए और तब सोचते-विचारते उन्हें ऋषि दधीचि याद आए। वही ऋषि, जिन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान किया था, ताकि देवता उनकी रीढ़ से एक अमोघ अस्त्र वज्र का निर्माण कर सकें। भारतीय सेना के परमवीरों को दिए जाने वाले पदक के बीच में इंद्र का वज्र है और उसके दोनों ओर छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार भवानी विराजमान है। ऋषि दधीचि के त्याग और शिवाजी की वीरता को मिलाकर बना परमवीर चक्र का अतुलनीय पदक। सावित्री बाई ने ही महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र भी डिजाइन किया। इस कार्य के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। बाद के दिनों में वह अध्यात्म व साधना में लीन हो गई थीं। वह अक्सर कहती थीं, 'मैं आत्मा से भारतीय ही हूं। गलती से विदेश में पैदा हो गई थी।'

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

हिंदी साहित्य के हमारे हरक्यूलिस

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

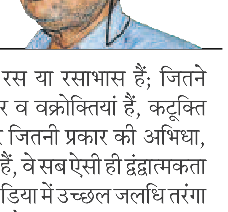

साथ-साथ काम किए। फिर साहित्य के सागर में एक साथ कूदे और एक साथ तैरे। हिंदी साहित्य के कुछ उस्तादों के चेले बने। उनके सत्संग से साहित्यिक तिकड़में सीखीं कि साहित्यिक कर्म से अधिक साहित्यिक फल-फूल की चिंता करना, उचित संपर्क बनाना, जुगत भिड़ाना, अपनी पैरवी करना-कराना, आचार्यों-उपाचार्यों की सेवा करना, उनकी मालिश-चंपी (सचमुच वाली) करना, सही प्रकाशक तक सही टाइम पर पहुंचना, फिर अपने लिए सम्मान की घोषणा कराना और फिर फेसबुक पर संकोच सहित खबर देना या किसी चेले से दिलवाना। जो ले उड़ा, उसका खल बनना। फिर जिसे मिला और जिनको न मिला, उनके बीच जेनुइन किस्म के सर्वमुखी संघर्ष का छिड़ना, फिर धार्मिक-जाति संघर्ष का छिड़ना, फिर इस संघर्ष का चर्चा में रहना और इसका भी इतिहास बनना- ये सब हिंदी की दैनिक संस्कृति है।

इस प्रक्रिया में हर सम्मान के अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, जातिशास्त्र और गाली-गलौजशास्त्र आदि सारे शास्त्र एक-एक कदम विकसित होते रहते हैं और अंत में ये पांच हजार का सम्मान देने व लेने वाले, दोनों की इससे अधिक की पब्लिसिटी कराकर ही साहित्य का पीछा छोड़ते हैं। हिंदी में कोई सम्मान छोटा नहीं होता। कई तो एक हजार एक रुपये वाले के लिए भी जान की बाजी लगाते देखे गए। हिंदी साहित्य की सारी गति-अगति, कुगति-सुगति-प्रगति इसी प्रकार की बहुस्तरीय 'डाइलेक्टिक्स' से तय होती है; सारी विचारधारा, आचारधारा, लाचारधारा, प्रचारधारा क्रमशः गालीधारा, गैंगधारा और माफियाधारा में बदल जाती है। हिंदी साहित्य इसी तरह के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकतावाद के जरिये आगे बढ़ा है।

साहित्य में अब तक अभिव्यक्त जितने भी आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, स्थायी व व्यभिचारी भाव, रस या रसाभास हैं; जितने प्रकार के अलंकार व वक्रोक्तियां हैं, कटूक्ति रीति-नीति हैं और जितनी प्रकार की अभिधा, लक्षणा, व्यजनाएं हैं, वे सब ऐसी ही द्वंद्वात्मकता के साथ सोशल मीडिया में उच्छल जलधि तरंगा होकर सामने आती हैं।

ऐसे रचनात्मक संघर्षों को देख मुझे कविवर बिहारी का यह दोहा याद आता है : *दृग उरझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर-चित प्रीति!/ परत गांठि दुर्जन हिये, दई नई यह रीति!!* यह दोहा जो बात प्रेमियों के लिए कहता है, वही आज के लेखकों पर भी हूबहू चिपकती है। जैसे प्रेमियों को नैन-मटक्का करते देख पुरानी फिल्मों का 'प्राण' दुर्जन बन जाता है, उसी तरह से जिसे सम्मान नहीं मिलता, वह छोटा-मोटा 'मोगैंबो' तो बन ही जाता है, क्योंकि जिसे मिल जाता है, वह अपने को मिस्टर इंडिया से कम नहीं समझता!

आज हिंदी साहित्य में संघर्ष का मतलब पढ़ना, गुनना, समाज का अवलोकन करना, फिर सोचकर लिखना और शिल्प-शैली की साधना नहीं है, बल्कि सही 'कॉन्टैक्ट' साधना है और सही वक्त पर सही तरीके से 'कनेक्ट' करना है। जिसे यह हुनर आ गया, साहित्य में छा गया, सबको भा गया और सब कुछ पा गया। इसलिए मैं जब-जब नव्य-नवेले लेखकों के फोटोज के साथ संक्षिप्त परिचय पढ़ता हूं, तो यह देखकर चकित नहीं होता कि कइयों ने साहित्य में आंख खोलते ही अपनी नई उम्र की सारी फसलें काट ली हैं। उनकी हर कृति सम्मानित होकर, देने वालों को भी सम्मानित कर, ग्रुप फोटो बनकर किसी दुकान में टंग चुकी है!

इन दिनों मैं सिर्फ गिनता रहता हूं कि किसने कितने सम्मान लिए और उसी हिसाब से उनकी लिस्ट बनाता हूं और हर लेख में उनके नाम भजता हूं और उनकी प्रतिभा का कायल होता रहता हूं कि जो काम बड़े-बड़े न कर सके, ये छोटे-छोटे अपने बाल सुलभ कर-कमलों से संभव कर रहे हैं। इसीलिए मैं मानता हूं कि आज का नया हिंदी लेखक हिंदी का हरक्यूलिस है, जो आए दिन सबको हैरान करता है!

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

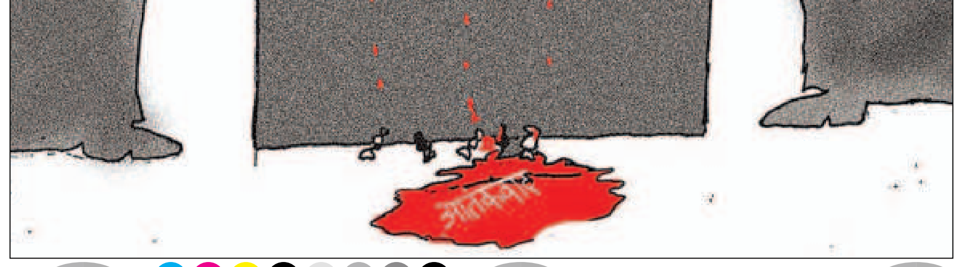

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

आतंकवादी देश 'पाकिस्तान'

पाकिस्तान के रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफ के इस कबूलनामें के बाद कि उनका देश 80 के दशक से आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षित करके पालता-पोसता रहा है, कोई शक नहीं बचता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी विदेशीनीति का अभिन्न अंग बनाने वाला देश है। इससे यह तो सिद्ध होता ही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को सब प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। 2008 के मुम्बई हमले के बाद पाकिस्तान पर आतंकवादी देश होने की जो तलवार लटक गई थी वह 2025 में जाकर साबित हुई है। विगत 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद पाकिस्तान की यह स्वीकारोक्ति बताती है कि यह कार्य पाकिस्तान के ही दहशतगर्दों द्वारा किया गया है। इससे पूर्व 2011 के करीब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ ने भी यह कबूल किया था कि ऐसी तंजीमों के सरपराह उनके देश के नायक हैं। अत: पहलगाम हमले के बाद विश्व के देशों की बिरादरी को अब पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश मान लेना चाहिए। ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद इसमें शक की गुंजाइश कहां बचती है। हालांकि आसिफ कह रहे हैं कि यह गन्दा काम उन्होंने अमेरिका व ब्रिटेन समेत पश्चिमी यूरोपीय देशों की मदद के लिए किया। उनके बयान से यह भी सिद्ध होता है कि अमेरिका ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान से रूस का प्रभाव खत्म करने के लिए चलाई गई मुहीम में पाकिस्तान को शामिल करके अंजाम दिया।

जाहिर है कि अमेरिका से मिली आर्थिक मदद का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पालने-पोसने के लिए किया। ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि 80 के दशक में इन्हीं दहशतगर्द तंजीमों के सरपराहों का स्वागत अमेरिकी सरकार किया करती थी। जाहिर है कि उस समय पड़ोसी अफगानिस्तान में रूस समर्थित सरकारें बनती थीं जिन्हें हटाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जमीन को उनके लिए जरखेज बना डाला। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन रेजिस्टैंस फ्रंट ने ली है जो लश्करे तैयबा का उप संगठन समझा जाता है। ख्वाजा साहब का कहना है कि पाकिस्तान में जब लश्करे तैयबा पर प्रतिबंध लगाकर उसे खत्म किया जा चुका है तो उसके उप-संगठन का सवाल ही पैदा नहीं होता।

> **जाहिर है कि अमेरिका से मिली आर्थिक मदद का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पालने-पोसने के लिए किया। ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि 80 के दशक में इन्हीं दहशतगर्द तंजीमों के सरपराहों का स्वागत अमेरिकी सरकार करती थी। जाहिर है कि उस समय पड़ोसी अफगानिस्तान में रूस समर्थित सरकारें बनती थीं जिन्हें हटाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जमीन को उनके लिए जरखेज बना डाला। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन रेजिस्टैंस फ्रंट ने ली है जो लश्करे तैयबा का उप संगठन समझा जाता है। ख्वाजा साहब का कहना है कि पाकिस्तान में जब लश्करे तैयबा पर प्रतिबंध लगाकर उसे खत्म किया जा चुका है तो उसके उप-संगठन का सवाल ही पैदा नहीं होता।**

लश्करे तैयबा को 2008 में ही राष्ट्रसंघ द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। पाक के रक्षामन्त्री ने यह भी स्वीकार किया है कि आतंकवादी तंजीमों को पनपाने की गलती तत्कालीन सरकारों ने की थी और यह गन्दा काम किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले अफगानिस्तान में रूस के विरुद्ध और बाद में अमेरिका में आतंकवादी घटना के बाद पाकिस्तान यह कार्य बदस्तूर करता रहा और आतंकवाद को समाप्त करने के नाम पर अमेरिका से आर्थिक मदद प्राप्त करता रहा। जाहिर है कि ये आतंकवादी संगठन अब उसके लिए भी नासूर साबित हो रहे हैं। मगर ख्वाजा साहब को यह भी पता होना चाहिए कि उनकी ही सेना के मुखिया जनरल आसिम मुनीर क्या कह रहे हैं? मुनीर फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानियों को हिन्दुओं से घृणा करना कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा द्विराष्ट्र के सिद्धान्त को याद रखना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि पाकिस्तान का वजूद तभी तक कायम है जब तक कि इसके लोगों में हिन्दुओं के प्रति नफरत का भाव है।

हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान का निर्माण इसी भावना के तहत 76 साल पहले हुआ था। जाहिर है कि जनरल मुनीर इस एहसास को पाकिस्तान का राष्ट्रधर्म बनाना चाहते हैं। अगर हम और पीछे जाएं तो पायेंगे कि पाकिस्तान की पूरी सियासत ही हिन्दू विरोध पर टिकी हुई है जबकि भारत ने शुरू से ही पाकिस्तान को बिगड़ैल पड़ोसी समझा। पहलगाम हमले के बाद जिस शिमला समझौते को पाकिस्तान ने मुल्तवी किया है, उसे करने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो 1972 में भारत आये थे और उन्होंने पैरों पर पड़ कर यह समझौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. इन्दिरा गांधी से किया था। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जब वह वापस पाकिस्तान लौटे तो करांची में उन्होंने बहुत विशाल जनसभा को सम्बोधित किया और कहा कि मैं मानता हूं कि 1971 के बंगलादेश युद्ध में हमारी करारी शिकस्त हुई है। पिछले एक हजार साल के इतिहास में हमें हिन्दुओं ने कभी इतनी बड़ी शिकस्त नहीं दी। भुट्टो ने पाकिस्तान की इस हार को भारत की जीत नहीं बल्कि हिन्दुओं की जीत कहा था। इससे यही साबित हुआ कि भुट्टो भी जनरल मुनीर जैसी ही मानसिकता के शिकार थे। वर्तमान सन्दर्भों में पाकिस्तान में पाले-पोसे जा रहे आतंकवादी अब भारत के खिलाफ इसी मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं और पहलगाम में पर्यटकों का धर्म पूछ-पूछ कर हत्या कर रहे हैं। अत: ऐसे पड़ोसी पाकिस्तान पर किस तरह यकीन किया जा सकता है जिसका ईमान ही इस्लामी जेहाद चलाना हो। जबकि इस्लाम मासूम लोगों की हत्या करने की इजाजत नहीं देता है लेकिन दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि ये जेहादी अब पाकिस्तान को भी भीतर से रक्त रंजित कर रहे हैं कभी शिया-सुन्नी के नाम पर तो कभी सूबों की खुद मुख्तारी के नाम पर। इसी वजह से मैं शुरू से लिखता आ रहा हूं कि पाकिस्तान एक नाजायज मुल्क है जिसकी नामुराद फौज हिन्दू विरोध के नाम पर ऐश करती है। वरना कोई बताये कि क्या कभी फौजी जनरल भी लोगों में धर्म के नाम पर बंटवारा करते हैं। दुनिया को इससे बड़ा सबूत पाक को एक आतंकवादी देश घोषित करने के लिए क्या चाहिए?

सरजमीं पर साजिश...

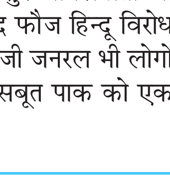
गीता पाढा

"सोचती हूं कैसे उन परिवारों के गम का अजाला होगा,
क्या आतंक को मिटा कर कभी घाटी में उजाला होगा,
अगर इस बार भी तुमने युद्ध के शंखनाद को
अहिंसा के मार्ग पर टाला होगा,
तो उम्र भर जो दर्द दे ऐसा यह छाला होगा,
देशवासियों के आश्वासन और इस वादे पर,
उस पत्नी ने खुद को संभाला होगा,
अगर हैं यह संकल्प तुम्हारा,
कि जिस सरजमीं पर रची गई यह साजिश
पूरे विश्व में उस मुल्क का मुंह काला होगा...।"

सुप्रीम कोर्ट से तकरार नहीं चाहता केंद्र

मिर्च मसाला
त्रिदीब रमण
gossipguru.in

'है अगर तेरे पास तो अपनी रूह पहन कर चल यहां
आइनों का क्या सब दिखा पाना इसके वश में कहां'

पिछले कुछ समय में सरकार के एक चहेते भगवा सांसद और यूपी के एक पूर्व उपमुख्यमंत्री ने सुर में सुर मिलाते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जिस तरह सीधे निशाने पर लिया है, यह बात केंद्र सरकार को रास नहीं आई है। सूत्र बताते हैं कि संघ नेतृत्व ने भी इस बात पर अपनी नाखुशी जाहिर की है। समझा जाता है कि भाजपा शीर्ष ने भी अपने चहेते सांसद दुबे जी को समझा दिया है कि 'उनकी ऐसी ये नादानियां ठीक नहीं हैं, सर्वोच्च कोर्ट से रार लेना सरकार व पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं।'

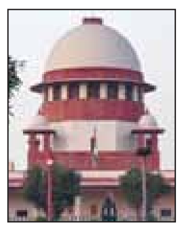

जब से सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार और वहां के राज्यपाल आर.एन.रवि के बीच चल रही तनातनी को लेकर 8 अप्रैल 2025 को एक अहम फैसला सुनाया है, इस मामले में न जाने किस के कहने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कूद गए हैं और वे लगातार अलग-अलग मंचों पर कोर्ट की अति सक्रियता को लेकर चिंता जता रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले की देशभर में गूंज है जिसमें साफ कहा गया है कि 'राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास विधेयकों पर 'पॉकेट वीटो' का कोई अधिकार नहीं है।' दुबे जी ने भले ही अपना निशाना सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर साधा हो जो इसी 14 मई को रिटायर हो रहे हैं, पर कहते हैं इस बात की गूंज दूर तक सुनी जा सकती है। आने वाले चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के बारे में माना जाता है कि वे नागरिक अधिकारों की पुरजोर वकालत करने वाले ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्हें हाशिए पर खड़े लोगों की सबसे ज्यादा फिक्र है। वहीं 8 अप्रैल का ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज यानी जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की भी एक निर्विवाद छवि है और सबसे अहम बात तो यह कि जस्टिस पारदीवाला मई 2028 से लेकर 11 अगस्त 2030 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने वाले हैं, केंद्र सरकार ऐसे में उन्हें क्यों छेड़ना चाहेगी?

भाजपा सांसद की 25वीं सालगिरह की धूम: निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा से चौथी बार निर्वाचित भाजपा के प्रो-एक्टिव सांसद हैं, वे समय-समय पर अलग-अलग कारणों से सदैव चर्चा में बने रहते हैं। कभी महुआ मोइत्रा प्रकरण की वजह से तो कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी पर निजी हमलों की वजह से।

विवादों से भले उनका चोली-दामन का साथ रहा हो, पर पार्टी लाइन से इतर अलग-अलग राजनीतिक दलों में उनके मित्रों की तादाद भी काफी बड़ी है। सो, जब पिछले दिनों उन्होंने अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर गुलमर्ग के आलीशान खैबर होटल में शानदार जश्न मनाया तो तीन दिनों तक चले इस जश्न की खबर ने सुर्खियां भी उतनी ही बटोरी। कहते हैं उनकी इस पार्टी के सारे इंतजाम खैबर होटल के मालिक उमर तरांबू ने व्यक्तिगत तौर पर किए। सूत्रों का दावा है कि उनके इस जश्न में शामिल होने वाले हाई प्रोफाइल मेहमानों की सूची आपको दंग कर सकती है। इस सूची में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर कई बड़े नाम शामिल हैं। दुबे जी की खास मित्रों में शुमार होने वाली सुप्रिया सुले की उपस्थिति भी वहां देखी गई, इसके अलावा इस पार्टी में शामिल होने वालों की सूची में कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह, भाजपा सांसद कमलेश पासवान के अलावा कई नामी-गिरामी बिजनेसमैन के नाम भी गिनाए जा सकते हैं। नोएडा के एक चर्चित बिल्डर जिन पर हाल के दिनों में ही आयकर विभाग का जोरदार छापा पड़ा है वे भी वहां मंडराते दिखे। सबसे खास बात कि यह पार्टी पहलगाम हादसे से बमुश्किल 10 दिन पहले हुई थी, पर उस वक्त वहां सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई थी।

राहुल से खफा अमेरिकी शिक्षाविद : राहुल गांधी पिछले दिनों एक बार फिर से अमेरिकी दौरे पर थे, जहां वे पुन: रोड आइलैंड के ब्राउन यूनिवर्सिटी में पहुंचे। वैसे भी राहुल को अमेरिकी विश्वविद्यालय के छात्रों व उनके प्रोफेसरों के संग संवाद स्थापित करना हमेशा से पसंद रहा है। इससे पहले भी वे वहां के हार्वड, मिशिगन व ब्राउन यूनिवर्सिटी जा चुके हैं। राजनीति विज्ञान के नामचीन अमेरिकी प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय राहुल के खास सलाहकारों में शुमार होते हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय इससे पहले मिशिगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, बाद में वे ब्राउन यूनिवर्सिटी आ गए। 2021 में प्रोफेसर वार्ष्णेय के साथ राहुल की वर्चुअल चर्चा ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। कहते हैं राहुल के इस बार का भी ब्राउन यूनिवर्सिटी का दौरा प्रोफेसर वार्ष्णेय और सैम पित्रोदा ने मिल कर तय किया था। इस दफे जब राहुल ब्राउन यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहां के कुछ प्रोफेसर व बुद्धिजीवियों के साथ राहुल की वन-टू-वन सारगर्भित चर्चा हुई।

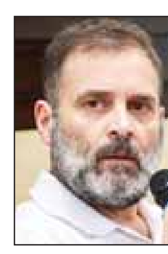

वहां मौजूद एक अमेरिकी प्रोफेसर ने राहुल से कहा कि हम आपके राजनीतिक विचारों का स्वागत करते हैं, पर आप मोदी की तरह चुनावी रणनीति बनाने में हमेशा असफल रहे हैं, क्या आप जानते नहीं कि चुनाव कैसे जीता जाता है? इस पर राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया- 'मैं एक लॉग डिस्टेंस रनर हूं, मैं आज भी रोजाना 5 से 10 किलोमीटर दौड़ लेता हूं। मैं सत्ता के लिए नहीं, विचारधारा के लिए राजनीति करता हूं, हम 2029 नहीं तो 34 का लोकसभा चुनाव तो जरूर जीतेंगे, मैं इतना इंतजार करने के लिए तैयार हूं।' राहुल की ये बातें सुन कर बैठक में एक असहज़ सन्नाटा पसर गया। बैठक से बाहर निकल कर सैम पित्रोदा ने राहुल को समझाया कि 'सार्वजनिक मंचों पर ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में लोग सिर्फ जीतने वाले घोड़े पर ही दांव लगाना चाहते हैं।'

नायब का नायाब अंदाज : हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार को दुबारा सत्ता में आए छह महीनों से ज्यादा का वक्त गुज़र गया है, पर राज्य में विपक्ष की भूमिका में तैनात कांग्रेस अभी तक अपने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ही नहीं कर पाई है। कांग्रेसी इसका ठीकरा राहुल गांधी के मत्थे फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके यहां से ही कोई निर्णय अबतलक हो नहीं पाया है। सूत्रों की मानें तो हरियाणा कांग्रेस पार्टी की आपसी सिर फुटौव्वल को देखते हुए राहुल किसी नए चेहरे को वहां नेता विपक्ष की अहम जिम्मेदारी देना चाहते हैं, पर पार्टी के सीनियर नेता नए नेता के नाम पर मान ही नहीं रहे। उल्टे वे तर्क दे रहे हैं कि अगर पार्टी के सीनियर नेताओं को अलग-थलग किया जाएगा तो यहां गुटबाजी और बढ़ जाएगी। पार्टी के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी राहुल खफा-खफा दिख रहे हैं, यही वज़ह है कि कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में हुड्डा को कोई खास भाव नहीं मिला। वे बस अशोक गहलोत के आसपास ही नज़र आए। वहीं सैनी ने इस मौके को अवसर में तब्दील करना शुरू कर दिया है। विपक्ष का नेता नहीं होने की वज़ह से वे राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त समेत छह अन्य आयुक्तों की नियुक्तियां नहीं कर पा रहे थे सो उन्होंने संवैधानिक नियुक्तियों के इस मामले को कानूनी सलाह के लिए भेज दिया है।

कांग्रेस ने इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में अग्निवीर, पहलवान व किसानों के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था। सीएम सैनी ने इसकी काट के लिए अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में 20 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया है, यानी 2026 में जब अग्निवीर सेना से रिटायर होकर आएंगे तो उनके लिए पुलिस की नौकरी का एक बड़ा मौका होगा। इसी तरह सैनी पहलवानों व किसानों के लिए कुछ बड़ी योजना लाने पर काम कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस बस हाथ मलती रह जाएगी। क्योंकि जिन संवैधानिक नियुक्तियों में सरकार को सीएम, नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों के पैनल की जरूरत होती है, सैनी साहब ने इसकी नायाब काट ढूंढ निकाली है।

...और अंत में : पिछले सप्ताह 18-20 अप्रैल तक बेंगलुरु में आहूत होने वाली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को अंत समय पर टालना पड़ा। संघ चाहता था कि पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के उपरांत यह बैठक हो। हालांकि भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को 30 जून तक विस्तार दे दिया गया है। सो, अब यह माना जाता है कि पार्टी अपना नया अध्यक्ष 10 मई से पहले चुन लेगी। तब तक शायद 18 बचे हुए प्रदेशों के अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाए। संघ इस बात से भी खुश नहीं बताया जाता है कि भाजपा नड्डा को 20 जनवरी 2023 के बाद से ही लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जा रही है।

शिवराज सिंह चौहान के अलग अंदाज

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): इन्होंने पहले अपने दोनों पुत्रों की धूमधाम से शादी संपन्न करवाई, उसमें खूब झूम कर थिरके, फिर अपनी पत्नी समेत केंद्रीय कृषि मंत्री ब्राजील के दौरे पर निकल गए, जहां उन्होंने भारतीय किसानों के लिए टमाटर व आलू की बंपर पैदावार के गुर सीखें।

शिवराज का यह अंदाज सोशल मीडिया पर भी खूब छाया रहा। स्वदेश वापसी के बाद उन्हें ऐसा लगा कि इतनी शिद्दत से जो वे ब्राजील से सीख कर आए हैं, उन्हें देश के किसानों के संग भी तो बांटना चाहिए। सो, आनन-फानन में उनके ऑफिस ने हरियाणा, पश्चिमी यूपी से अलग-अलग किसानों को इकट्ठा किया और किसानों के इस प्रतिनिधिमंडल से कहा गया कि कृषि मंत्री उनसे खेती के कुछ गुर शेयर करेंगे। किसानों का जत्था जब शिवराज के आवास पर पहुंचा तो सादगी की प्रतिमूर्ति बने वे खुद बाहर दरवाजे तक गए उन्हें रिसीव करने, रिसीव कर अंदर लेकर लाए, अपने ड्राईंग रूम में आवभगत से बिठाया और फिर बेहद विनम्रता से पूछा- 'आप लोग क्या लेंगे, चाय या ठंडा?' पिछली पांत में बैठे हरियाणा के एक किसान ने उठ कर कहा- 'यह सब तो होता रहेगा, पहले मंत्री जी को तो बुला लो, हम से मिलवा तो दो।' अब शिवराज का चेहरा देखने लायक था।

पाकिस्तान जाने वाले सिंधु के पानी के उपयोग का योजना बना रही है सरकार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) केंद्र सरकार उन तीन नदियों के पानी की मात्रा का अधिकतम उपयोग करने के तरीकों पर अध्ययन करने की योजना बना रही है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान सिंधु जल संधि के तहत कर रहा था। सिंधु समझौते को अब निलंबित कर दिया गया है।

यह प्रस्ताव शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में रखा गया, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि पर भविष्य की कार्रवाई के संबंध में चर्चा की गई। पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाते हुए भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया।

विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों- सतलुज, ब्यास और रावी के पानी पर विशेष अधिकार दिए गए थे, जिसका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 33 मिलियन एकड़ फुट (एमएएफ) है। पश्चिमी नदियों-सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, जिसका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 135 एमएएफ है। संधि के स्थगित होने के बाद सरकार सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का उपयोग करने के तरीकों पर विचार कर रही है। शुक्रवार की उच्च स्तरीय बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम कर रही है कि पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान में न जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई निर्देश जारी किए हैं और उन पर अमल के लिए यह बैठक आयोजित की गई। शाह ने बैठक में उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई सुझाव दिए। बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री ने कहा, ''हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत से पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान में न जाए।'' सूत्रों ने कहा कि सरकार अपने निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है।

एक अधिकारी के अनुसार, मंत्रालय को तीन पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग करने के तरीकों पर अध्ययन करने के लिए कहा गया है। विशेषज्ञों ने बुनियादी ढांचे की कमी के बारे में बात की है जो संधि को निलंबित करने के फैसले से मिलने वाले पानी का पूरी तरह से उपयोग करने की भारत की क्षमता को सीमित कर सकती है।'

साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल' (एसएएनडीआरपी) के हिमांशु ठक्कर ने कहा, ''वास्तविक समस्या पश्चिमी नदियों से संबंधित है, जहां बुनियादी ढांचे की सीमाएं हमें पानी के प्रवाह को तत्काल रोकने से रोकती हैं।''

तै की दर्द न आया...

श्रीमती किरण चोपड़ा
डायरेक्टर- पंजाब केसरी दैनिक समाचार लि.
चेयरपर्सन- वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब
मुख्य संरक्षिका- चौपाल
सदस्या- राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल, एकल
संरक्षिका- भारतीय लोक विकास परिषद
f /kiranchopra01
kiranchopra@punjabkesari.com
kiranchopradesk@gmail.com

मुझे आज फिर वह मंजर याद आ गया जब अमर शहीद रमेश जी ने लिखा था जब बुजुर्ग निहत्थे लाला जी को आतंकवादियों ने गोली मारी थी और बसों से हिन्दुओं को चुन-चुन कर हत्या कर रहे थे कि तै की दर्द न आया। आज फिर दिल रो रहा है और इतना गुस्सा है कि एक-एक कश्मीरी आतंकवादी को पूछें कि तै की दर्द न आया। जब तुम किसी के पति को उसकी पत्नी के सामने, पिता को उसके बच्चों के सामने, उस नई ब्याहता के सामने जिसकी मेहंदी का रंग नहीं सुखा, लाल चूड़ा पहना है, उसके सामने उसके पति को गोलियां मार दीं और हंस रहे हों, फोटो खींच रहे हों। तुम इंसान नहीं हैवान हो जो चंद पैसों की खातिर इंसानियत का खून कर दिया। उन मासूम लोगों का जो अपने परिवार के साथ चंद खुशी के पल बिताने आए थे, उनके उन पलों की कल्पना करके ही रूह कांप जाती है। तुम हैवानों ने मासूम निहत्थे लोगों का कत्ल तो किया, तुमने कश्मीरियों की रोजी-रोटी भी छीन ली। कुछ महीने पहले मैं भी कश्मीर जाकर आई। भारत की जन्नत जिसे गवर्नर मनोज सिन्हा और मोदी जी ने आर्मी और स्थानीय लोगों के सहयोग से सींच-सींच कर शांति बहाल की, खुशहाली दी। स्थानीय लोग पर्यटकों के आने से खुश थे। नए-नए बिजनेस खुल रहे थे। युवाओं को रोजगार मिल रहा था। 90 के दशक में बंद हुए सिनेमा हाल खुल गए। पिछले साल 2.35 करोड़ टूरिस्ट जम्मू-कश्मीर और लद्दख पहंचे। इससे यह तो समझ आता है कि स्थानीय लोग नहीं पाकिस्तान या दूर बैठे लोग फैसला ले रहे हैं, योजना बनाते हैं और आतंक के आका आतंकवादियों को उनकी दिल दहला देने वाली परफोरमेंस पर पैसे देते होंगे, जो ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी।

कोई भी मजहब ऐसी दरिन्दगी नहीं सिखाता तो कश्मीर और इस्लाम के नाम पर यह सब नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि वो लोग जिन्होंने

यह कांड किया न तो वह मुसलमान हैं, न इंसान, न उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है। वह किसी जानवर के बच्चे हैं। जानवर भी उन्हें अपना बच्चा कहने से पहले हजार बार सोचेंगे। असली मुसलमान तो आदिल हुसैन है जो खच्चर पर पर्यटकों को ले जा रहा था और उनको बचाने के लिए अपनी जान दे दी, जो घर का इकलौता बेटा था।

जिस पहलगाम घाटी में जिसे कश्मीर का स्विट्जरलैंड कहा जाता हो और वहां चारों तरफ से पहाड़ों की तलहटी में सुंदर कुदरती नजारें हों वहां छुट्टियां मनाने गए देशभर के 26 लोगों से खून की होली खेली जाए तो इसे क्या कहेंगे? सब जानते हैं कि कश्मीर घाटी में चार दिन पहले जो आतंकवादी हमला हुआ वह देश के लिए एक ऐसा मंजर है कि हर कोई गुस्से में है और आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग पूरे देश और दुनिया से उठ रही है। जो 26 लोग आतंकियों द्वारा मारे उनके परिजनों का एक ही सवाल है कि हमारे रिश्तेदार को तो मार दिया लेकिन हमें भी जीते जी मार डाला है। कहीं बच्चे पिता को तो कहीं पत्नी अपने सुहाग, कहीं बेटी अपने पिता को आंसुओं से अंतिम विदाई दे रहे हैं। यह राष्ट्रीय शोक है। मां-बेटी व बहन विधवा हो गई। बच्चे अनाथ हो गए, इन हत्यारों को जमीन में दफनाने की मांग पूरा देश कर रहा है।

करनाल के जिस नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की हत्या की गयी उसकी पत्नी हिमांशी ने तिरंगे में लिपटे पति के शव को गले लगाकर कहा कि तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। विनय नरवाल और पत्नी हिमांशी की शादी 6 दिन पहले ही हुई थीं और वह हनीमून मनाने गए थे लेकिन आतंकियों ने खून की होली खेली। इसी कड़ी में देशभर से विशेष रूप से कानपुर के जिस शुभम की हत्या की गयी वह भी पहलगाम गया था और उसकी शादी को महज चार महीने ही हुए थे। उसकी पत्नी आशिना के सामने उनकी हत्या कर दी गयी। इसी कड़ी में बैंगलुरू के कारोबारी मंजूनाथ राव और उनकी पत्नी पल्लवी ने इस हत्या से एक घंटा पहले जो वीडियो बनाया उसमें पहलगाम जाने की खुशी को शब्दों में बयान किया था लेकिन एक घंटे बाद ही दृश्य बदल गया। आतंकियों ने उसकी आंखों के सामने ही उनके पति मंजूनाथ की हत्या कर दी तो पल्लवी ने कहा मेरा पति का क्या कसूर था मुझे भी मार डालो तो आतंकवादी ने कहा - जाओ जाकर सरकार से कह दो हम क्या कर सकते हैं? ये शब्द मंजूनाथ की पत्नी ने सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में बताए हैं। इसी तरह कनार्टक के ही दो परिवारों के घरों में सन्नाटा पसर गया है। भारतभूषण को पत्नी सुजाता और तीन साल के बेटे के सामने आतंकवादियों ने गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया।

पहलगाम घाटी में जो कुछ हुआ वह अमानवीय है। हम हर किसी के दर्द में शामिल हैं। मृतकों की सूची लम्बी है। उड़ीसा के भुवनेश्वर के प्रशांत सतपथी की हत्या उनकी पत्नी और नौ साल के बेटे के सामने कर दी गयी। पहलगाम जाकर छुट्टियां मनाना उनके लिए मौत का संदेशा लेकर आया। प्रशांत का भाई सुशांत आतंकवादियों के खात्मे का इंतजार कर रहा है। अमरीका के फलोरिडा से छुट्टियां बिताने आए बितान अपनी पत्नी के साथ पहलगाम पहुंचे और इस आईटी अधिकारी की हत्या उनकी पत्नी के सामने कर दी गयी। छत्तीसगढ़ में रायपुर के कारोाबारी दिनेश मिरानिया की हत्या आतंकवादियों ने पहलगाम में उस दिन की जब वह पत्नी के साथ सालगिराह मना रहा था। बिहार के मनीष रंजन की हत्या उनकी पत्नी और बच्चों की आंखों के सामने कर दी गयी। सूरत के सैलेश कालठिया अपना 44वां जन्मदिन मना रहे थे और उनकी हत्या आतंकियों ने कर डाली। केरल के रामचंद्रन जो सीनियर सीटीजन थे, भी पहलगाम में आतंकियों की गोली का शिकार हुए। इसी तरह मुंबई के संजय लेले, हेमंत जोशी और अतुल मोने पहलगाम पहुंचे लेकिन वापिस नहीं आये। सबके घरों में लाशें पहुंची।

दु:ख की बात यह है कि आतंकवादियों ने पहले धर्म पूछा और कलमा पढ़ने को कहा और फिर चुन-चुन कर वही काला इतिहास लिखा जो पंजाब में आतंकवाद के दिनों में हिंदूओं को चुन-चुनकर मारे जाने के काले पन्नों से जुड़ा है। हर किसी का सवाल यही है कि अब जल्दी से जल्दी इन आतंकियों को जमीन में दफनाकर हिसाब-किताब लिया जाये। इसका हर किसी को इंतजार है। पूरा देश आंसुओं से भरा पड़ा है और गुस्से के गुब्बार फूट रहे हैं। कलम निहत्थों के खून बहने को लेकर थमी जा रही है और आंखों में आंसू बह रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी से एक ही अपील है कि आपने इन आतंकवादियों को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। हमें इन आतंकवादियों को बहुत जल्द ही कफन में देखने का इंतजार रहेगा। पहलगाम के इन सभी 26 लोगों को नमन है। प्रभु से कामना है और सरकार से उम्मीद है कि मानवता के नाम पर इस खूनी खेल पर लगाम कसी जाए वरना देश कब तक हिसाब-किताब और न्याय मांगता रहेगा।

मेरा कश्मीर से बहुत स्नेह है। अश्विनी जी के साथ बिताए हुए शादी के बाद के पल और अमरनाथ यात्रा पर अपने सास-ससुर, देवर के साथ, अपने माता-पिता के साथ हर गर्मी की छुट्टियां। अभी कुछ महीने पहले अपने मित्रों के साथ और वहां की बैस्ट प्रोपर्टी ललित पैलेस में ठहरने का मौका, एक-एक पल याद आता है। यह हादसा फिर न किसी के साथ हो। मोदी से पूरे देश को उम्मीदें हैं।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में एक सांसद ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जो देश में सांप्रदायिक विभाजन करने पर आमादा हैं ताकि पाकिस्तान और आतंकी संगठनों को अपने कुत्सित मंसूबे पूरे करने में मदद मिले।
—विजेयता सिंह, पत्रकार @vijaita

लोकतंत्र

भारत डोगरा

सत्ता संघर्ष से अलग भी है राजनीति

विडंबना ही है कि राजनीति को मुख्य रूप से सत्ता की राजनीति और चुनावी राजनीति के रूप में ही देखा जाता है। राजनीति का अधिक व्यापक अर्थ है कि किसी उद्देश्य के लिए लोगों को प्रेरित और संगठित करना। ये उद्देश्य जितने जन-हित, पर्यावरण रक्षा से जुड़े होंगे उतना ही सार्थक राजनीतिक प्रयास होगा। उन उद्देश्यों को जितनी ईमानदारी से जो आगे बढ़ाएंगे, उतनी ही ईमानदार उनकी राजनीति मानी जाएगी।

इस दृष्टि से देखें तो सबसे सार्थक राजनीति का पहला अनिवार्य कदम यह है कि दुनिया और देश के बारे में सही समझ बनाई जाए-क्या बड़ी समस्याएं और दुख-दर्द हैं, इनके क्या कारण हैं, और इनके कौन से समाधान सब से उचित और असरदार हो सकते हैं। यह काम पूरी ईमानदारी और अच्छाई से होना चाहिए। यदि यह सोचा गया कि अपने या अपने को धन देने वालों का स्वार्थ क्या है, या जिस मुद्दे पर ज्यादा वोट मिल सके उसे उछाल दिया जाए तो सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति का प्रयास इस पहले कदम पर ही भटक जाएगा। अतः देश और दुनिया की जो भी समझ तैयार करनी है, यह सावधानी से एकत्र किए गए तथ्यों के साथ पूरी तरह सच्चाई को प्रस्तुत करने के प्रयास से ही प्रेरित होनी चाहिए। अब इस तरह के विश्लेषण से जो समाधान निकलेंगे वे तो आगे देखने की बात है, पर यदि अभी तक के अनुभवों से सीखा जाए तो मोटे तौर पर समाधानों की यह राह इन सिद्धांतों पर आधारित होगी-न्याय व समता, अमन-शांति और अहिंसा, पर्यावरण और जैव-विविधता की रक्षा, लोकतंत्र और पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण और आपसी सहयोग। इसके साथ ही इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों को सीखना है कि इन सिद्धांतों का उपयोग विभिन्न विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए और विभिन्न पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए कैसे किया जाए। इनके लिए प्रशिक्षण और परामर्श चाहिए, चिंतन-मनन और अभ्यास चाहिए। इन समाधानों, सिद्धांतों, ऐसी समझ का प्रसार करना होगा और यही सार्थक राजनीतिक शिक्षा है।

जहां एक ओर यह प्रयास व्यवस्था में बदलाव का है जिससे व्यवस्था विभिन्न समस्याओं के समाधान के अनुकूल बने, वहीं दूसरी ओर सार्थक बदलाव का यह प्रयास लोगों के जीवन में बेहतरी के लिए भी सक्रिय होता है, विशेषकर अपने सदस्यों और समर्थकों में सार्थक बदलाव के लिए। अपने जीवन में लोग विभिन्न समस्याओं से त्रस्त हो सकते हैं, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं जैसे जीवन में विभिन्न स्तरों पर हिंसक सोच की उपस्थिति, किसी तरह का नशा, सामाजिक संबंधों में टूटन, अकेलापन, विलासिता के प्रति मोह, आलस्य, अनिश्चय आदि। सार्थक बदलाव का आंदोलन ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है,

अपने जीवन में लोग विभिन्न समस्याओं से त्रस्त हो सकते हैं, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं जैसे जीवन में विभिन्न स्तरों पर हिंसक सोच की उपस्थिति, किसी तरह का नशा, सामाजिक संबंधों में टूटन, अकेलापन, विलासिता के प्रति मोह, आलस्य, अनिश्चय आदि। सार्थक बदलाव का आंदोलन ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है, जिनमें ये समस्याएं कम होने या दूर होने के अवसर बढ़ जाते हैं और साथ ही मिल-जुल कर अधिक प्रेरक कार्य करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इस तरह व्यवस्था के बड़े बदलाव में चाहे देरी हो, पर इस आंदोलन के साथ चलने वाले लोग अपने और आसपास के जीवन में दुख-दर्द कम होने, अपनी क्षमताओं के विकसित होने और प्रेरक कार्यों के माहौल में आगे बढ़ते हैं। इस राह पर चलते हुए सार्थक बदलावों के ये प्रयास राजनीतिक दल भी बना सकते हैं, जो चुनाव भी लड़ सकते हैं

जिनमें ये समस्याएं कम होने या दूर होने के अवसर बढ़ जाते हैं और साथ ही मिल-जुल कर अधिक प्रेरक कार्य करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इस तरह व्यवस्था के बड़े बदलाव में चाहे देरी हो, पर इस आंदोलन के साथ चलने वाले लोग अपने और आसपास के जीवन में दुख-दर्द कम होने, अपनी क्षमताओं के विकसित होने और प्रेरक कार्यों के माहौल में आगे बढ़ते हैं। इस राह पर चलते हुए सार्थक बदलावों के ये प्रयास राजनीतिक दल भी बना सकते हैं, जो चुनाव भी लड़ सकते हैं, या स्थानीय या अन्य स्तर के चुनावों में स्वतंत्र या अन्य उम्मीदवारों को अपना समर्थन दे सकते हैं पर चुनावों में यह भागेदारी अपने मूल्यों और विचारों के आधार पर ही होती है और चुनावों में जितनी भी सफलता मिले, कम या अधिक, सार्थक बदलाव की राह पहले जैसे चलती रहती है। सिद्धांत आधारित बदलाव की राह इस तरह चुनावों से सशक्त तो हो सकती है, पर भटक नहीं सकती।

इस तरह के सार्थक बदलाव को किसी एक देश के स्तर पर देखने के स्थान पर सभी देशों के संदर्भ में देखना-समझना चाहिए और एक देश के सार्थक बदलाव के प्रयासों को अन्य देशों से भी समर्थन मिलना चाहिए। अपनी विशेष स्थानीय स्थितियों के नजदीक रहते हुए भी उन्हें एक-दूसरे के अनुभवों से यथासंभव सीखना चाहिए। ऐसे प्रयासों की दृष्टि विश्व की होनी चाहिए और उन्हें पूरे विश्व की बेहतरी, भलाई और रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। इन प्रयासों और आंदोलनों को आगे ले जाते समय दूसरों की आलोचना में अपनी ताकत खपाने के स्थान पर मुख्य ध्यान सार्थक विकल्प आगे लाने पर देना चाहिए। आलोचना जरूरी हो जाए तो भी विनम्रता से करनी चाहिए और अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना चाहिए। समाधानों को, विकल्पों को, सुलझे हुए विमर्श को आगे ले जाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विकल्पों की केवल बातें ही नहीं करनी चाहिए अपितु बेहतर सहयोग आधारित सामुदायिक जीवन, प्राकृतिक खेती, ऊर्जा, पर्यावरण रक्षा आधारित ग्रामीण जीवन, स्वराज और आत्म-निर्भरता आधारित गांवों के रूप में महत्त्वपूर्ण विकल्प वास्तविक जीवन में तैयार कर, जी कर भी दिखाने चाहिए। ये प्रयास और आंदोलन अहिंसक, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और पारदर्शी होने चाहिए। धन जुटाने और खर्च करने के मामलों में पूरा हिसाब-किताब पारदर्शी होना चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी मुद्दे पर आंदोलन की सोच से अलग सोच रखता है, तो उसे यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि किसी मुद्दे पर अलग सोच रखते और प्रसारित करते हुए भी वह आंदोलन से व्यापक स्तर पर प्रतिबद्धता बनाए रखे।

यदि ऐसे प्रयासों में फूट डलवाने या अन्य क्षति पहुंचाने के बाहरी प्रयास किए जाते हैं तो इसका सामना भी लोकतांत्रिक तौर-तरीकों और अपनी एकता की मजबूती से करना चाहिए। अहिंसक बने रहने और अमन-शांति के लिए प्रतिबद्धता के बावजूद यदि ऐसे प्रयासों या उनसे जुड़े सदस्यों को किसी देश में उत्पीड़न सहना पड़ता है, तो उसका सामना आपसी सहयोग से और उत्पीड़न सहने वालों को शीघ्र से शीघ्र सहायता पहुंचा कर करना चाहिए। वैसे भी कठिनाइयों में पड़े विभिन्न सदस्यों और समर्थकों को सहायता पंहुचाने की व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। इस तरह सत्ता की राजनीति से हट कर एक अलग तरह की लोकतांत्रिक राजनीति भी संभव है, जो जन-हित और सच्चाई से अधिक नजदीकी तौर पर जुड़ने में कहीं अधिक सक्षम है। इस तरह की राजनीति से बेहतर दुनिया बनाने में अवश्य सहायता मिलेगी। ऐसे अहिंसक जन-आंदोलन और उन पर आधारित राजनीति की विश्व स्तर पर जरूरत है जो वास्तविक स्थिति की सच्चाई आधारित समझ बनाए और ऐसे समाधानों की राह निकालें जो लोगों में एक ओर गहरा विश्वास उत्पन्न करती हों तथा साथ-साथ अपने समर्थकों के जीवन के सुधार में भी सहायक हों। यह ऐसी राजनीति है जिससे दुनिया में बड़े सार्थक बदलाव आने की उम्मीद उत्पन्न होती है, और इस राह पर चलते हुए लोगों के दुख-दर्द कम होते जाने की और उनकी क्षमताएं बढ़ते जाने की संभावनाएं भी उत्पन्न होती हैं।

मीडिया ने बनाया हमें पेटू

मीडिया

सुधीश पचौरी

मीडिया सिर्फ मेसेज या खबर नहीं देता, विचार, संस्कृति या राजनीतिक नजरिया ही नहीं देता, बल्कि हमें अंदर-बाहर से भी बदलता है। अपनी जरूरत के अनुसार ढालता है। हमें लालची बना कर बदलता है। 'पेटू' बना कर बदलता है। 'निर्भर' बना कर बदलता है, और इन दिनों तो बड़े-बड़े खिलाड़ी, सेलीब्रिटी हमें 'जुआ' खेलना यानी 'गेंमिग खेलना'...

मीडिया के विज्ञापन हमारी जरूरतों और हमारी कामनाओं का इतिहास कहते हैं। 'मीडिया' को इसलिए 'संदेश' (मेसेज) भी कहा जाता है। मीडिया और मेसेज एक दूसरे के 'अन्योन्याश्रित' हैं। इसीलिए माना जाता है कि मीडिया हमें बदलता है। हम मीडिया को बदलते हैं, और यह सिर्फ आज का सच नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए सच है।

उदाहरण के लिए, जब अपने यहां 'टीवी क्रांति' की शुरुआत हो रही थी तब टीवी सब के लिए एक अनिवार्य मीडियम की तरह था। वो 'ब्लैक एंड व्हाइट' टीवी सेटों का जमाना था। यह आपातकाल से पहले की बात है। तब हर मीडिया में सबसे ज्यादा विज्ञापन 'ब्लैक एंड व्हाइट' टीवी सेटों के हुआ करते थे। 1982 के एशियाड खेलों के साथ कलर टीवी के साथ लाइव प्रयारण शुरू हुआ और वीडियो प्लेयर क्रांति भी शुरू हुई। टीवी एक 'पर्सनल' और 'फैमिली मीडियम' माध्यम बन कर हमारे बीच आया। तभी टीवी की 'सीरियल क्रांति' शुरू हुई। 'हम लोग', 'बुनियाद' जैसे सीरियल प्रसारित होने लगे और 'अमूल' सबसे बड़ा प्रायोजक बना। उसकी कैचलाइन 'स्वाद इंडिया का' हिट हुई। तभी 'रसना' नामक घरेलू ठंडे पेय के विज्ञापन आए और लिरिल सोप की झरने में बिकनी ड्रेस्ड युवती के नहाने की क्रांति भी इसी दौर में हुई। कपड़े धोने वाले निरमा सोप पाउडर और गोरा बनाने वाली ब्यूटी क्रीमों के ब्रांड भी आने शुरू हुए। हम 'सांवले' और 'भूरे' रंग वाले 'गोरे' होना चाहते थे।

फिर 'ग्लोबलाइजेशन' का दौर आया। उसके साथ 'वर्ल्डवाइड वेब', 'इंटरनेट' व 'कंप्यूटर' क्रांति आई और कंप्यूटरों के विज्ञापन आने लगे। 'कंप्यूटर क्रांति' ने समाज को तेजी से बदला। फिर उसके लगभग साथ-साथ आई 'मोबाइल क्रांति' ने दुनिया को 'कनेक्ट' करने और 'संवाद' करने के तरीके को बदला। 'मेसेजिंग' व 'चेटिंग' शुरू की। 'इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों' और 'मोबाइल कनेक्शनों' के विज्ञापन भी आने लगे। आज हाल यह है कि बड़े-बड़े अखबार बेहद चिकने पेजों पर नये-नये स्मार्ट फोनों के विज्ञापन छापते रहते हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया क्रांति आई और गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर (अब 'एक्स') और 'लिंक्डइन' और अब तो 'एआई' यानी 'चेटजीपीटी' और 'ओपिनआई' आदि टाइप के 'कृत्रिम बुद्धि' के टूल्स के 'एडवर्टोरियल' आने लगे। इसी दौर में 'अंबेसेडर' व 'फिएट' कारें विदा हुईं और उनकी जगह बड़ी-बड़ी विश्व ब्रांड कारों के विज्ञापन ललचाने लगे और हम इन्हें खरीदने भी लगे।

और, गोरा बनाने वाली तरह-तरह की क्रीमों, बाल काले करने वाले तरह-तरह के शेंपुओं, कपड़ा धोने वाले पाउडरों व नहाने के साबुनों के नये-नये ब्रांड हमें घेरे रहने लगे। इसी दौर में ब्रांडेड 'कच्छा बनियान' के साथ 'चोली व कंडोम ब्रांडों' ने मीडिया का एक बड़ा हिस्सा छेका। 'त्वचा क्रीम क्रांति' भी हुई। तरह-तरह के 'टूथपेस्टों' के विज्ञापनों के अलावा, 'शराब' के 'सरोगेट विज्ञापन' के अलावा मुंह की बदबू मिटाने वाली खुश्बूदार इलायची के विज्ञापनों की भी भरमार रहती है। आज महंगे 'स्मार्टफोन' और 'महंगी कारें' मात्र 'सुविधा' के नहीं, बल्कि 'हैसियत' के प्रतीक हैं।

पिछले बरसों से मीडिया में 'सीमेंट', 'सरिया', 'प्लास्टिक पाइपों' व 'टाइलों' के विज्ञापनों का हल्ला बढ़ा है। इससे साफ है कि मिडिल क्लास की अपना घर बनाने की कामना बढ़ी है। इसके साथ ही कुछ विज्ञापनों में हमारे 'जीवन की चिंता' भी बढ़ी। तरह-तरह की बीमा कंपनियां हमारा बीमा करने के लिए पीछा करने लगीं और कई कंपनियां 'गोल्ड' के बदले 'कैश/लोन' लेने के लिए कहने लगीं। विज्ञापनों ने हमारी ही जेब ढीली कराके हमें आधुनिक शहरी और सभ्य बनाया है और निरा 'ऑनलाइन मनुष्य' बना डाला है। विज्ञापनों से भरे मीडिया सीन को देख कर यही कहा जा सकता है कि मीडिया और उसको चलाने वाले विज्ञापन इंडिया की नई मिडिल क्लास की उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते बाजार का प्रमाण हैं। इन विज्ञापनों ने हमारा मिडिलक्लासीकरण किया है, और हमें उपभोक्ता, निरा स्वार्थी व सुखी बनाया है। हम जहां जाते हैं सबसे पहले अपना सुख ही देखते हैं। स्पष्ट है कि मीडिया सिर्फ मेसेज या खबर नहीं देता, विचार, संस्कृति या राजनीतिक नजरिया ही नहीं देता, बल्कि हमें अंदर-बाहर से भी बदलता है। अपनी जरूरत के अनुसार ढालता है। हमें लालची बना कर बदलता है। 'पेटू' बना कर बदलता है। 'निर्भर' बना कर बदलता है, और इन दिनों तो बड़े-बड़े खिलाड़ी, सेलीब्रिटी हमें 'जुआ' खेलना यानी 'गेंमिग खेलना' सिखा रहे हैं ताकि हम 'जुआरी बने रह जाएं!

पाकिस्तान से पानी का रिश्ता खत्म

अंतरराष्ट्रीय

प्रमोद भार्गव

सिंधु जल संधि के तहत जल-बंटवारे में उदारता की अनूठी मिसाल दुनिया के किसी भी अन्य जल-समझौते में देखने में नहीं आई है। इसीलिए अमेरिकी सीनेट की विदेशी मामलों से संबंधित समिति ने 2011 में दावा किया था कि यह संधि दुनिया की सफलतम संधियों में से एक है। संधि इसलिए सफल रही क्योंकि भारत संधि की शर्तों को निभाने के प्रति उदार एवं प्रतिबद्ध बना रहा

कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकी हमले के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पांच बड़े कूटनीतिक प्रहार किए हैं। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण सिंधु जल समझौते को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना है। यह ऐसी कूटनीतिक चाल है, जिससे पाकिस्तान को भीषण जल संकट का सामना तो करना पड़ेगा ही, उसकी आर्थिक समृद्धि पर भी यह फैसला करारी चोट करेगा। अटारी-वाघा सीमा-द्वार बंद कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान से अपने सैन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। इन्हें एक सप्ताह में भारत छोड़ना होगा।

ये सभी निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा समिति (सीसीएस) की बैठक में लिए गए। आतंकवादियों की शरणस्थली बने पाकिस्तान को ये कूटनीतिक सबक समय की जरूरत हैं। अमानुषिक दगाबाजी के आदी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने 16 अप्रैल, 2025 को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन में कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के 'गले की नस' है। पाकिस्तान ने आतंकी साजिश रच कर कश्मीर के अवाम की इसी आर्थिक श्वास की नली को अवरुद्ध कर दिया है। अब भारत ने पलटवार करते हुए सिंधु की जलधार को अवरुद्ध करके ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया है। यदि यह जवाब बहुत पहले दे दिया गया होता तो शायद पाक से निर्यातित आतंक इस कदर नहीं पनप पाता।

19 सितम्बर, 1960 को सिंधु जल संधि में भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का पानी बांटने का समझौता हुआ था। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इसके तहत पाकिस्तान से पूर्वी क्षेत्र की तीन नदियों व्यास, रावी व सतलुज की जल राशि पर नियंत्रण भारत के सुपुर्द किया गया था और पश्चिम की नदियों सिंधु, चिनाब व झेलम पर नियंत्रण की जिम्मेदारी पाकिस्तान को सौंपी गई थी। इसके तहत भारत के ऊपरी हिस्से में बहने वाली इन छह नदियों का 80.52 यानी 167.2 अरब घन मीटर पानी पाकिस्तान को हर साल दिया जाता है जबकि भारत के हिस्से में महज 19.48 प्रतिशत पानी ही रह जाता है। नदियों की ऊपरी धारा (भारत में बहने वाला पानी) के जल-बंटवारे में उदारता की ऐसी अनूठी मिसाल दुनिया के किसी भी अन्य जल-समझौते में देखने में नहीं आई है। इसीलिए अमेरिकी सीनेट की विदेशी मामलों से संबंधित समिति ने 2011 में दावा किया था कि यह संधि दुनिया की सफलतम संधियों में से एक है लेकिन यह संधि केवल इसलिए सफल रही क्योंकि भारत संधि की शर्तों को निभाने के प्रति उदार एवं प्रतिबद्ध बना रहा जबकि जम्मू-कश्मीर को हर साल इस संधि के पालन में करीब 60 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता रहा है।

दरअसल, द्विपक्षीय वार्ता के बाद शिमला समझौते में स्पष्ट उल्लेख है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवाद को फैलाने की इजाजत नहीं देगा किंतु पाकिस्तान इस समझौते के लागू होने के बाद से ही इसका उल्लंघन करता रहा है। लिहाजा, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के नजरिए से सिंधु जल-संधि के पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। पुलवामा हमले के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों का पानी रोकने की बात कही थी।

तय है कि इस कूटनीतिक पहल से पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। नदियों के प्रवाह को बाधित करना इसलिए भी अनुचित नहीं है, क्योंकि यह संधि भारत के अपने राज्य जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के लिए न केवल औद्योगिक व कृषि उत्पादन के लिए पानी के दोहन में बाधा बन रही है, बल्कि पेयजल के लिए नये संसाधन निर्माण में भी बाधा है। हैरानी की बात यह भी है कि पाकिस्तान में सत्तारूढ़ रहने वाली सरकारों और अलगाववादी जमातों ने इस बुनियादी मुद्दे को अनदेखा किया। इसलिए आतंक का माकूल जवाब देने के लिए भारत सरकार की कूटनीतिक पहल का स्वागत होना चाहिए।

कोचिंग संस्थानों के छलावे का सच

मुद्दा

नृपेंद्र अभिषेक नृप

भारत में शिक्षा को हमेशा पुनीत कार्य माना गया है। यह केवल ज्ञानार्जन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन निर्माण की आधारशिला भी है। किंतु विगत कुछ दशकों में जिस तेजी से शिक्षा का व्यावसायीकरण हुआ है, उसने इस पवित्र व्यवस्था की आत्मा को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाई है। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्थाओं की बाढ़ ने ऐसा परिदृश्य रच दिया है, जहां दावा और भ्रम का चक्रव्यूह हर अभ्यर्थी को घेरे खड़ा है। यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ। इसमें टॉपर का फोटो ज्यादातर कोचिंग में दिख रहा है, जो नये छात्रों को बरगलाने का माध्यम बन गया है।

कोचिंग संस्थानों की भूमिका का उद्भव एक सहायता प्रणाली के रूप में हुआ था। यह उन विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त संबल था जो कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए मार्गदर्शन की तलाश में थे। परंतु समय के साथ यह सहायक तंत्र व्यापक उद्योग का रूप ले बैठा, जहां सफलता को ब्रांड की तरह बेचा जाने लगा। आज स्थिति यह है कि कोचिंग संस्थानों ने शिक्षा जगत में अपनी समानांतर सत्ता बना ली है। वे अपने विज्ञापनों में इस कदर दावा करते है मानो सफलता की गारंटी वही दे सकते हैं। अखबार, टेलीविजन, सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थलों पर चस्पां होर्डिंग्स में ऐसे दावे भरे पड़े हैं, जिनमें कहा जाता है कि परीक्षा विशेष में सफलता पाने वाले छात्र 'फलां कोचिंग संस्थान' के हैं। दावों के पीछे कोई ठोस आंकड़ा या प्रमाण नहीं होता, बल्कि यह भ्रम फैलाने की रणनीति के तहत किया गया प्रचार होता है।

यह प्रवृत्ति तब और भी खतरनाक हो जाती है, जब एक ही छात्र को एक साथ अनेक संस्थाएं अपने प्रचार में शामिल कर लेती हैं। बिना उसकी सहमति के उसके नाम, तस्वीर और अंक का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक छात्र भ्रमित होकर उस संस्थान में नामांकन लें। इस तरह की भ्रामक प्रचार प्रणाली ने कोचिंग उद्योग को ऐसी प्रतिस्पर्धा में धकेल दिया है, जहां नैतिकता, पारदर्शिता और ईमानदारी जैसे मूल्यों का कोई स्थान नहीं रह गया है। छात्रों और अभिभावकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला यह खेल ऐसी संस्कृति को जन्म दे रहा है, जहां शिक्षा के नाम पर छल और भ्रम का साम्राज्य फल-फूल रहा है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा हाल में कोचिंग संस्थानों के लिए जारी चेतावनी और दिशा-निर्देश स्वागतयोग्य कदम हैं। इन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्था छात्र की सहमति के बिना उसका नाम या चित्र अपने प्रचार में नहीं दिखा सकती। यह भी अनिवार्य किया गया है कि संस्थान अपने दावों के पीछे स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करें। यह पहल सकारात्मक शुरुआत है, लेकिन इसे लागू करना और इस पर सतत निगरानी रखना भी आवश्यक है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऐसी व्यवस्थाएं कागजों तक सीमित रह जाती हैं, और व्यवहार में उनका पालन नहीं होता। इन संस्थानों द्वारा फैलाए गए भ्रम का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ता है, जो दूरदराज के गांवों या छोटे शहरों से आते हैं। अंततः यह कहना उचित होगा कि शिक्षा को प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि सृजन और आत्म विकास का आधार बनाना होगा। कोचिंग संस्थान अपनी भूमिका को मार्गदर्शक के रूप में देखें, न कि एक 'सफलता की दुकान' के रूप में। छात्रों को भ्रमित करने वाली रणनीतियां न केवल अनैतिक हैं, बल्कि शिक्षा की आत्मा के प्रति अपराध भी हैं।

भविष्य के लिए अतीत को सहेजना

विमर्श

गिरीश पांडे

हाल में श्रीमद्भगवीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल किया गया जो भारत के लिए उसकी महान सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अब कुल 14 भारतीय ग्रंथ हो गए हैं।

गौरतलब है कि उत्कृष्ट मूल्यों वाली दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करने की यह एक वैश्विक पहल है। प्रसंगवश, उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि 1982 से प्रति वर्ष 18 अप्रैल को सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के सम्मान और संरक्षण के लिए विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, और उसी क्रम में इस बार मनाए जाने वाले विश्व विरासत दिवस की थीम थी-विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट। इसे हम अतीत को भविष्य के लिए संरक्षित करने की पहल भी कह सकते हैं।

भारत की विरासत वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत से लेकर अजन्ता-एलोरा की गुफाओं, मीनाक्षी मंदिर, ताजमहल जैसे स्थापत्य चमत्कारों तक फैली हुई है। भारत की विरासत में योग, आयुर्वेद, शास्त्रीय संगीत, नृत्य रूपों जैसे भरतनाट्यम और कत्थक, और विभिन्न त्योहारों की रंगीनता शामिल है, जो इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। यह विरासत भारत की पारंपरिक जीवनशैली, खानपान, पोशाक, लोक कथाओं, शिल्पकला और आचार-विचार में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यही नहीं, भारत ने विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्रों में भी विश्व को महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है-जैसे शून्य की खोज, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे विद्वानों का ज्ञान और प्राचीन नालंदा तथा तक्षशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय। धार्मिक दृष्टि से भी भारत अनेक धर्मों की जन्मभूमि है-हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म यहीं उत्पन्न हुए हैं। भारत ने सूफी और भक्ति आंदोलन के जरिए आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया। भारत की हस्तकला जैसे बनारसी साड़ी, कांच की चूड़ियां, मधुबनी और वारली चित्रकला, पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक तकनीकों और रचनात्मकता के प्रतीक हैं।

भारतीय लोक संगीत, वाद्य यंत्र (जैसे सितार, तबला, सरोद) और राग-रागिनियां न केवल मनोरंजन के माध्यम हैं, बल्कि भावनाओं और दर्शन का भी गहरा स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार, भारतीय विरासत जीवंत धरोहर है जो आज भी आधुनिकता के साथ संतुलन बना कर, भारत को उसकी जड़ों से जोड़ती है, और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। विरासत केवल अतीत नहीं, भविष्य का आधार है। समय, जलवायु और प्राकृतिक क्षरण हमेशा से प्राचीन संरचनाओं और परंपराओं के शत्रु रहे हैं, लेकिन आज एक और अधिक तात्कालिक और खतरनाक खतरा राजनीतिक विचारधाराओं और शासनों से आता है। दुनिया भर में हमने देखा है कि विरासत को जानबूझ कर अपना प्रभुत्व स्थापित करने, इतिहास को फिर से तोड़-मरोड़ कर लिखने या प्रतिशोध की भावना से नष्ट किया गया। लेकिन अतीत को मिटाने की कोशिश में, ये शासन न केवल संरचनाओं को नष्ट करते हैं, बल्कि पहचान को भी मिटा देते हैं। सबसे दुखद और प्रतीकात्मक उदाहरणों में से एक 2001 में तालिबान द्वारा बामियान बुद्ध प्रतिमाओं का विनाश था। 6वीं शताब्दी में निर्मित ये विशाल मूर्तियां केवल धार्मिक और कलात्मक दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण नहीं थीं-वे अफगान इतिहास के अपूरणीय पन्ने थीं। शासन ने इस विध्वंस से न केवल मूर्तियों को नष्ट किया, बल्कि उनके पीछे की पूरी सांस्कृतिक परंपरा को अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार रूस में हमने विरासत के विनाश का अलग रूप देखा। सोवियत संघ के पतन के बाद लेनिन और कम्युनिस्ट युग के अन्य प्रतीकों की मूर्तियों को नये शासन द्वारा हटाया या नष्ट किया गया। उपनिवेशोत्तर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, उपनिवेशवादियों की मूर्तियां नई सरकारों या जन आंदोलनों द्वारा गिरा दी गईं।

लेकिन भारत ने इस संबंध में अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने प्राचीन मंदिरों, किलों और नगरों को संरक्षित करने की दिशा में प्रतिबद्धता दिखाई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) हजारों स्मारकों का प्रबंधन करता है, और ताजमहल, हम्पी, खजुराहो जैसे स्थल न केवल राष्ट्रीय, बल्कि वैश्विक संरक्षण और सराहना प्राप्त करते हैं। भारत ने 2024 में असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर अपनी भाषायी विविधता को भी मजबूत किया। सच्चाई है कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। चाहे वह कितना भी असुविधाजनक क्यों न हो, अतीत हममें जीवित रहता है। स्मारक पत्थर या मूर्तियां नहीं हैं; वे स्मृति के वाहक हैं, चेतावनियां हैं, उपलब्धियां हैं, असफलताएं हैं-और इन सबके बीच का पुल भी हैं। उनका विनाश किसी राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए भी नुकसान है। इसलिए सरकारों को विरासत के प्रति अधिक परिपक्व दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

भारत ने इस संबंध में अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने प्राचीन मंदिरों, किलों और नगरों को संरक्षित करने की दिशा में प्रतिबद्धता दिखाई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) हजारों स्मारकों का प्रबंधन करता है, और ताजमहल, हम्पी, खजुराहो जैसे स्थल न केवल राष्ट्रीय, बल्कि वैश्विक संरक्षण और सराहना प्राप्त करते हैं। भारत ने 2024 में असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर अपनी भाषायी विविधता को भी मजबूत किया। सच्चाई है कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। चाहे वह कितना भी असुविधाजनक क्यों न हो, अतीत हममें जीवित रहता है। स्मारक पत्थर या मूर्तियां नहीं हैं; वे स्मृति के वाहक हैं, चेतावनियां हैं, उपलब्धियां हैं, असफलताएं हैं-और इन सबके बीच का पुल भी हैं। उनका विनाश किसी राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए भी नुकसान है। इसलिए सरकारों को विरासत के प्रति अधिक परिपक्व दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। **समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, **फैक्स** - 23352370, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750
वर्ष-34, अंक 250 आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भारत में डेढ़ हजार साल तक ऐसा दौर रहा जब लोग अपना काम-धंधा नहीं बदल सके और न ही अपनी जाति से बाहर विवाह कर सके। इसलिए एक किस्म का सामाजिक ठहराव आया। समाज में परस्पर दुराव बढ़ा और कुछ जातियों को निम्न जाति माना जाने लगा जिन्हें छूना तक हेय हो गया।
-देवदत्त पटनायक, धर्म मर्मज्ञ @devduttmyth

विचार-मीमांसा

ललित गर्ग

मौलिक सृजन का संरक्षण बड़ी चुनौती

रचनात्मकता, सृजनात्मकता और संरचनात्मकता मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति हैं। इन मौलिक विशेषताओं एवं उपलब्धियों को उचित सम्मान, प्रोत्साहन एवं पारिश्रमिक मिले, ऐसे नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ही हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा (आईपी) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, और नवाचार तथा रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में आईपी की भूमिका को उजागर करना है।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) के दौर में मानव की स्वतः स्फूर्त बौद्धिकता का संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन ज्यादा जरूरी है। 2025 की थीम-'आईपी और संगीत : आईपी की धड़कन महसूस करें'-है। इस थीम का उद्देश्य आईपी के माध्यम से संगीत रचनाकारों की रचनाओं की रक्षा करना और उनके काम को उचित मान्यता दिलाना है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) की स्थापना करने वाला कन्वेंशन लागू हुआ था।

बौद्धिक संपदा दिमाग की रचनाओं से संबंधित है, जैसे आविष्कार, साहित्यिक सृजन, संगीत, कला एवं कलात्मक कार्य, डिजाइन और व्यापार में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम और चित्र आदि। ऐसा रचनात्मक काम जो पहले नहीं किया गया हो, वह हमारी बौद्धिक संपदा है। इस रचनात्मक संपदा का कोई दूसरा अनधिकृत उपयोग न कर सके, इसके लिए बौद्धिक संपदा को सुरक्षित एवं संरक्षित करवाना चाहिए। यह दिवस बौद्धिक संपदा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है, दुनिया भर में बौद्धिक संपदा संरक्षण के प्रभाव को विस्तार देता है, देशों से बौद्धिक संपदा संरक्षण कानूनों और विनियमों को प्रचारित और लोकप्रिय बनाने का आग्रह करता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में सार्वजनिक कानूनी जागरूकता बढ़ाता है। इसका बड़ा उद्देश्य यह भी है कि विभिन्न देशों में आविष्कार-नवाचार गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले और बौद्धिक संपदा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान मजबूत हों। भारत भी डब्ल्यूआईपीओ का सदस्य है। इस संगठन की स्थापना 14 जुलाई, 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। एआई के उद्भव एवं प्रचलन का बौद्धिक संपदा ढांचे पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जो बड़ी चुनौती है। हमें एआई जैसे नवाचार प्रोत्साहनों के उभरते परिदृश्य और मौजूदा आईपी ढांचे के लिए इसके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर मंथन करना होगा।

पेटेंट योग्यता दुविधाओं से लेकर कॉपीराइट पहेली तक, हम पाते हैं कि तेजी से तकनीकी प्रगति के बीच नवाचार को बढ़ावा देने और सामाजिक हितों की रक्षा करने के बीच एक नाजुक संतुलन है। एआई प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के साथ हमारे संपर्क के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। जैसे-जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, इसका बौद्धिक संपदा के संरक्षण पर चुनौतीपूर्ण गहरा प्रभाव पड़ रहा है। चैटजीपीटी जैसे एआई चैट बॉट अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत मानव-जैसे लिखित उत्तर दे सकते हैं क्योंकि भाषा मॉडल की प्रश्नों और कार्यों को समझने और उनमें टेक्स्ट और डेटा के आधार पर प्रतिक्रियाएं देने की क्षमता है, जिन पर इसे प्रशिक्षित किया गया है।

एआई अन्य क्षेत्रों में भी जैसे कला, लेखन, युद्ध, व्यापार, प्रबंधन, संगीत, फिल्म-निर्माण आदि में भी दखल बढ़ रहा है। इसी के साथ बौद्धिक संपदा के सम्मुख सोशल मीडिया भी बड़ी चुनौती है क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हर कोई दूसरों की रचनात्मकता एवं मौलिक सृजन को अपना बता कर पेश कर रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी बौद्धिक संपदा के लिए जागरूक होना होगा। हर किसी में कुछ अलग और रचनात्मक एवं मौलिक काम करने की क्षमता होती है। हम अपनी बौद्धिक संपदा को पांच तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। इसमें पहला है कॉपीराइट, दूसरा पेटेंट, तीसरा ट्रेडमार्क, चौथा है औद्योगिक

डिजाइन और पांचवा है भौगोलिक संकेतक। अगर आप कुछ लिखते हैं, जो आपका मौलिक लेखन है तो आप कॉपीराइट करा सकते हैं। इसके बाद व्यापार के क्षेत्र में होता है ट्रेडमार्क, जो आपका सिंबल होता है, जो किसी संस्था, कंपनी की पहचान के लिए होता है, उसे अगर ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, तो कोई दूसरा उस सिंबल का उपयोग नहीं कर सकेगा। अगर आपने कोई आविष्कार किया है तो उसे पेटेंट करा कर सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक।

इस वर्ष की थीम संगीत पर केंद्रित है। संगीत ने हमेशा लोगों को जोड़ने, बदलाव को प्रेरित करने और सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाने में अनूठी भूमिका निभाई है। यह विषय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आईपी अधिकार संगीतकारों और अन्य संगीत रचनाकारों की रचनाओं की रक्षा करते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस डब्ल्यूआईपीओ का सबसे बड़ा आईपी सार्वजनिक जनजागृति अभियान है। कॉपीराइट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार संगीत उद्योग की प्रभावी मदद करते हैं। सुनिश्चित करते हैं कि संगीत रचनाकारों को उनके काम का श्रेय और भुगतान मिले। यह दिन यह भी दिखाएगा कि इन अधिकारों की मदद से संगीत को बेहतर बनाने में रचनात्मकता और नये विचार कितने महत्त्वपूर्ण हैं।

आधुनिक समय में संगीत बौद्धिक एवं आर्थिक संपदा का बड़ा माध्यम है। आज की आपाधापी, तनाव एवं अवसादपूर्ण जीवन में संगीत ही ऐसा माध्यम है, जो शांति, सुकून एवं आनंद प्रदान कर सकता है। संगीत सुनने से इंसान को आलौकिकता का अहसास होता है। डॉक्टर भी संगीत को सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं। संगीत को लेकर हुए अध्ययनों में पता चला है कि संगीत शरीर में बदलाव लाता है, जो स्वास्थ्य में सुधार एवं शांति स्थापित करता है। इसके अलावा, जो मरीज अवसाद और निराशा के शिकार होते हैं, उन्हें इससे बाहर निकालने के लिए संगीत थेरेपी दी जाती है। संगीत मन और शरीर, दोनों को आराम पहुंचाता है। संगीत अमूर्त कला है पर उसमें निहित शांति, सौंदर्य एवं संतुलन की अनुभूति विरल है। संगीत अशांति के अंधेरों में शांति का उजाला है। यह अंतर्मन की संवेदनाओं में स्वरों का ओज है। इसीलिए संगीत एक बड़ी बौद्धिक संपदा है।

शादी में ढोलक-शहनाई, भजन-मंडली में ढोल-मंजीरा, शास्त्रीय संगीत में तानपूरा, तबला, सरोद, सारंगी का हम सब भरपूर आनंद उठाते हैं। बचपन में सपेरों द्वारा बीन बजाते ही लहराते हुए सांप का खेल भी हमने खूब देखा है। इन संगीत प्रस्तुतियों से जुड़े कलाकार एवं संगीतकारों के लिए यह उनकी बौद्धिक संपदा है। यह दिन इन बौद्धिक संपदा से जुड़े अधिकारों के संरक्षण के महत्त्व को रेखांकित करता है, जो रचनाकारों और आविष्कारकों को उनके काम के लिए पुरस्कृत करने में मदद करता है एवं उनके उचित पारिश्रमिक को सुनिश्चित करता है। वैश्विक स्तर पर युवा नवाचार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा और सरलता, अपनी जिज्ञासा और सरलता का उपयोग करके बेहतर भविष्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं। नये विश्व के निर्माण में बौद्धिक संपदा की प्रभावी भूमिका है। तकनीकी विकास एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दौर में बौद्धिक संपदाओं को संरक्षित करते हुए बौद्धिक संपदाओं के रचनाकारों एवं मौलिक सृजनकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना ही इस दिवस का ध्येय है, और इसी में इस दिवस की सार्थकता भी है। ■

हम अपनी बौद्धिक संपदा को पांच तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। इसमें पहला है कॉपीराइट, दूसरा पेटेंट, तीसरा ट्रेडमार्क, चौथा है औद्योगिक डिजाइन और पांचवा है भौगोलिक संकेतक। आप कुछ लिखते हैं, जो आपका मौलिक लेखन है तो कॉपीराइट करा सकते हैं। इसके बाद व्यापार के क्षेत्र में होता है ट्रेडमार्क, जो किसी संस्था, कंपनी की पहचान के लिए होता है, उसे अगर ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। आपने कोई आविष्कार किया है तो उसे पेटेंट करा कर सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक

'इन गलियों में' भारत को खोजते अविनाश

विष्णु राजगढ़िया

फिल्म 'इन गलियों में' देखना सार्थक रहा। लखनऊ की गलियों में 'भारत की खोज' करते हमारे आसपास के पात्रों के साथ बेहद सहज और दिलचस्प कथानक है। साझा संस्कृति में ईद और होली के रंगों के साथ प्रेम और इंसानी रिश्तों को बखूबी पिरोया गया है। इनमें खटास पैदा करने वाली ताकतों के कारण भ्रम की स्थितियों के बावजूद आपसी भरोसे की दीवारें कायम रहना फिल्म का खूबसूरत पक्ष है। लंबे अरसे के बाद किशोरवय प्रेम के दृश्य और संवाद गुदगुदाते हैं। खासकर किशोरी नायिका ने कई मौकों पर नये दौर की नारी के सशक्तिकरण के तेवर पेश किए हैं। प्रेम हमारा आपसी मामला है, और इसका फैसला चौराहे पर करने वाले आप कौन होते हैं? ऐसे संवादों और तेवर के कारण अंत तक उत्सुकता कायम रही। राजनीति और सोशल मीडिया के खेल से पैदा चुनौतियां दर्शकों को आज के दौर की चुनौतियां समझने को प्रेरित करती हैं।

नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक के पुत्र विवान शाह ने फिल्म में युवा प्रेमी हरिया की भूमिका निभाई है। अवंतिका दसानी ने शबनम के बतौर उसका अच्छा साथ दिया। मोहल्ले के हरदिल अजीज शायर मिर्जा की भूमिका में जावेद जाफरी खरे उतरते हैं। शायराना अंदाज में आपसी रिश्तों और राजनीतिक दांव-पेच पर उनके संवाद काफी प्रभावित करते हैं। राजीव ध्यानी ने समाज के उदार चेहरे का अच्छा प्रतिनिधित्व किया। कुटिल नेता की भूमिका में सुशांत सिंह का अभिनय भी जीवंत है।

पत्रकार से फिल्म निर्देशक बने अविनाश दास अपनी पहली फिल्म 'अनारकली आरा वाली' से चर्चा में आए थे। स्वरा भास्कर ने उसमें एक बेबस पीड़ित युवती के विद्रोह का शानदार अभिनय किया था। बाद में अविनाश की फिल्म 'रात बाकी' भी चर्चा में रही। अब 'इन गलियों में' बना कर अविनाश दास ने मौजूदा दौर की सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया है। नफरत की संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने के इस दौर में गंगा-जमुनी एकता की बात करना बड़े साहस की बात है।

'इन गलियों में' एक कथित 'पागल' चरित्र भी है, जो पूरी फिल्म में बुदबुदाता रहता है, लेकिन उसके छोटे से एक वाक्य में ही गहरा अर्थ दिख जाता है। उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर, वह कहना क्या चाहता है। भंगा के इस चरित्र को इश्तियाक खान ने बखूबी निभाया है। पूरी फिल्म में वह उस भारत को ढूंढ़ रहा है, जिसे हमने खो दिया, या शायद जिसे हमसे छीन लिया गया। एक जगह वह जवाब नहीं, वार करता है-कवि, गीतकार और पटकथाकार पुनीत शर्मा की एक पंक्ति से। यह पंक्ति तमाचा नहीं, हथौड़ा है, जो सामने वाले की चेतना पर गिरता है। नीरू यादव और विनोद यादव प्रोड्यूसर हैं। पटकथा पुनर्वसु ने लिखी है। म्यूजिक अमाल मल्लिक और अरविंद संगोले का है। अरविंद कन्नाबीरन की सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है। फिरोज ए खान ने कोरियोग्राफर तथा जबीन मर्चेंट ने एडिटर की भूमिका निभाई है। इसे कम बजट में सार्थक सिनेमा बनाने की कोशिश के बतौर देखा जा रहा है। ■

निर्मला जैन की आलोचना में स्त्री विमर्श

परिचय दास

निर्मला जैन की आलोचना-दृष्टि और विचार भारतीय साहित्यिक परंपरा में विशेष संवेदनात्मक और वैचारिक हस्तक्षेप की तरह हैं। उन्होंने न केवल साहित्य को कलात्मक अनुभव के रूप में देखा, बल्कि उसे समय, समाज और संस्कृति के बीच निरंतर संवाद करता हुआ जीवंत क्षेत्र माना। उनकी आलोचना में विचार और संवेदना, तर्क और करुणा, परंपरा और आधुनिकता, सभी तत्त्व एक जटिल लेकिन सौंदर्यपूर्ण ढंग से उपस्थित होते हैं।

निर्मला जैन का साहित्य-विवेक परंपरागत आलोचना से भिन्न इसलिए भी है क्योंकि वे किसी भी वाद, आंदोलन या रुचि को किसी सीमित परिभाषा में नहीं बांधतीं, बल्कि उसे उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रसंगों के भीतर रख कर देखती हैं। मानती हैं कि आलोचना का कार्य गुण-दोष की परख नहीं, बल्कि साहित्यिक रचना के भीतर उस सामाजिक अर्थगर्भ को पहचानना भी है, जो लेखक के समय और परिस्थिति का हिस्सा रहा है। इस अर्थ में उनकी आलोचना बहुस्तरीय और बहुस्वरात्मक है। उनकी विचारधारा में स्त्री-विमर्श का एक आत्मीय और अनुभवजन्य पक्ष है। उन्होंने नारी को विषय या पात्र के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक उपस्थिति को उसके समग्र अस्तित्व के साथ समझने का प्रयास किया।

निर्मला जैन के लिए नारी विमर्श कोई अलग कोना नहीं था, बल्कि साहित्य की मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा प्रश्न था-प्रश्न उस असमानता का, जो समाज की भाषा, दृष्टि और संरचना में ही निहित है। उनकी आलोचना में अक्सर दिखाई देता है कि वे रचना और आलोचना के बीच आत्मीय रिश्ता स्थापित करती हैं। रचनाकार की संवेदना को समझने का प्रयास करती हैं, और उस पर बाहरी सांचों को आरोपित करने से बचती हैं। यही कारण है कि उनकी आलोचना में एक प्रकार की सौम्यता, संवादात्मकता और सांस्कृतिक विनम्रता मिलती है। उनके लेखन में विचारों की तीव्रता होते हुए भी भाषा में कोमलता और स्पष्टता है।

निर्मला जैन ने भाषा, शिल्प और शैली की सूक्ष्मता को केवल सौंदर्यशास्त्रीय दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि उसमें छिपे सामाजिक-वैचारिक संकेतों को भी उजागर किया। वे भाषा को जीवित सत्ता मानती थीं जो समाज के भीतर सत्ता-संबंधों को रचती और चुनौती भी देती है। यही कारण है कि वे किसी भी लेखक की भाषा-प्रकृति को उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग करके नहीं देखतीं।

श्रद्धांजलि

उनका मानना था कि आलोचना निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि प्रश्नों को उठाने और साहित्य को नये संदर्भों में खोलने का रचनात्मक उपक्रम भी है। वे एक ही रचना में कई स्तरों पर देखने की क्षमता रखती थीं-कभी पाठ के भीतर जाकर, कभी उसके बाहर के समाज को जोड़ कर तो कभी उसकी अन्तर्ध्वनियों को सुन कर। निर्मला जैन का विचार था कि भारतीय साहित्य को केवल पाश्चात्य सैद्धांतिक प्रतिमानों से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने भारतीय परंपरा की आलोचनात्मक परंपराओं को पुनर्स्मरण में लाकर उसे आधुनिक विमर्शों के समकक्ष खड़ा किया। वे आलोचना को ऐतिहासिक उत्तरदायित्व की तरह देखती थीं-ऐसा उत्तरदायित्व जो न केवल साहित्य को समझे, बल्कि अपने समय और समाज को भी। उनकी आलोचना दृष्टि में एक नैतिकता है-ऐसी नैतिकता जो केवल आदर्शवाद नहीं है, बल्कि वह सृजन और सोच के भीतर सत्य की खोज से जुड़ी हुई है। यह नैतिकता उन्हें संवेदनशील बनाती है, लेकिन उन्हें सतर्क और आलोचनात्मक भी रखती है। वे किसी भी रचना को केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया से नहीं देखतीं, बल्कि उसमें निहित वैचारिक संरचना, सामाजिक स्पंदन और भाषिक गहराई को पहचानने का प्रयास करती हैं।

निर्मला जैन की आलोचना का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि उसमें पाठक के लिए सोचने का खुला आकाश होता है। वे न तो अपने निष्कर्ष थोपती हैं, न किसी वाद का प्रचार करती हैं। उनका कार्य आलोचना के माध्यम से साहित्य और समाज के बीच पुल बनाना है-ऐसा पुल जो स्थायी नहीं, बल्कि समय के साथ लचकने और नया आकार लेने में समर्थ हो। वे मानती थीं कि आलोचना अगर जीवित है तो वह हमेशा बहस, असहमति और पुनर्पाठ के लिए खुली रहेगी। उनका लेखन आलोचना के माध्यम से आत्मपरीक्षण का भी एक प्रयास है-जहां वे साहित्य के साथ-साथ अपने समय, अपने समाज और अंततः स्वयं से संवाद करती हैं। यही कारण है कि निर्मला जैन की आलोचना पाठकों को केवल साहित्य पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से देखने की प्रेरणा भी देती है। ■

राग रंग | आलोक पराड़कर

संकटमोचन में संगीत को पीते हुए

प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र, जिनकी इसी 25 अप्रैल को चौथी पुण्यतिथि थी, ने कभी बनारस की चर्चा करते हुए कहा था, 'यहां की जो परंपरा थी वह संगीत को सुनने की नहीं थी, संगीत को पीने की थी। संगीत पीया जा सकता है, वह बनारस में ही देखने को मिला। हम लोगों के बचपन में रात-रात भर एक से एक बड़े-बुजुर्ग का गाना होता रहा है, और जैसे फूल का रस मधुमक्खी लेती है, वैसे ही यहां के श्रोता संगीत का रस लेते थे।'

बनारस में रात भर चलने वाले संगीत समारोह कई रहे हैं, लेकिन इनमें मुख्य है संकटमोचन संगीत समारोह जो यहां प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर के परिसर में होता है। 101 वर्षों की यात्रा कर चुके इस संगीत समारोह में देश भर से कलाकारों का जमावड़ा होता है, रात आठ बजे से शुरुआत होकर सुबह छह-सात बजे तक संगीत कार्यक्रमों का सिलसिला चलता है। कलाकारों की उपस्थिति को देखते हुए कुछ वर्षों पूर्व इसे पांच दिन से बढ़ाकर छह दिनों का किया जा चुका है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे समय कम पड़ जाता हो। पंडित राजन मिश्र के शब्दों में कहें तो रात-रात भर रसिक संगीत को पीते हैं, मधुमक्खी की तरह प्रस्तुतियों के पुष्पों से संगीत का रस लेते हैं, थकते नहीं हैं, मुग्ध और आनंदित होते हैं। स्थानीय संगीत रसिकों के साथ ही बाहर से भी बड़ी संख्या में संगीतप्रेमी समारोह के कार्यक्रमों को सुनने-देखने के लिए आते हैं।

संकटमोचन संगीत समारोह का इस वर्ष का आयोजन 16 से 21 अप्रैल तक जब मंदिर परिसर में हुआ तो इसमें कई दिग्गज कलाकारों ने शिरकत की, कई दूसरी पीढ़ी के वे कलाकार भी थे जिनके पिता नियमित तौर पर समारोह में शिरकत करते थे। समारोह की लंबी यात्रा में शामिल रहे संगीतप्रेमी जानते हैं कि किस प्रकार किसी समय समारोह का समापन पंडित जसराज के गायन से ही होता था। यह सिलसिला लंबा चला और पंडित जसराज के शिष्य-शिष्याओं की भी समारोह में खूब शिरकत होती थी। बाद में समारोह की अंतिम प्रस्तुति पंडित राजन-साजन मिश्र करने लगे। अब यह दायित्व पंडित साजन मिश्र और उनके पुत्र स्वरांश मिश्र निभाते हैं। इसी प्रकार पंडित केलूचरण महापात्र यहां नियमित तौर पर अपने शिष्य-शिष्याओं के साथ ओडिशी नृत्य प्रस्तुत करते थे। पंडित जसराज जी अक्सर उनका केवट प्रसंग देखते और रो पड़ते थे।अब पंडित केलूचरण महापात्र के बेटे रतिकांत महापात्र यहां नियमित तौर पर प्रस्तुति देने के लिए आते हैं। पंडित जसराज की तरह ही उनके बड़े भाई पंडित प्रताप नारायण भी यहां नियमित तौर पर आते रहे हैं। पंडित शिवकुमार शर्मा के संतूर वादन की स्मृति भी समारोह के श्रोताओं को खूब है। कई बार ऐसा भी हुआ कि विदेश में होने के कारण वह समारोह में शिरकत नहीं कर पाते थे, ऐसे में जब वह लौट कर आते तो अलग से यहां कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। समारोह की नियमित कलाकार रहीं सुनंदा पटनायक से श्रोता 'खिलौना माटी का' जरूर सुनते थे। पंडित भजन सोपोरी भी यहां नियमित तौर पर आने वाले कलाकार थे।

पंडित शिवकुमार शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा और पंडित भजन सोपोरी के पुत्र अभय रुस्तम सोपोरी ने इस वर्ष संतूर वादन प्रस्तुत कर पुरानी यादों को ताजा किया। राहुल शर्मा ने राग-'झिंझोटी' और अभय रुस्तम सोपोरी ने राग-'विभास' बजाया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भी समारोह में लंबे समय से शिरकत करते रहे हैं। इस वर्ष उनकी बांसुरी पर 'विहाग' के बीच समारोह की शुरूआत हुई। खास बात यह भी रही कि मंदिर के महंत और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर पंडित विशंभर नाथ मिश्र ने पखावज पर उनके साथ संगत भी की। पंडित अजय चक्रवर्ती ने राग 'यमन', पंडित अजय पोहनकर ने 'आभोगी' तो पंडित उल्हास कशालकर ने राग 'केदार' सुनाया।

प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक पंडित विश्वमोहन भट्ट को उनके 75वें जन्म वर्ष के अवसर पर सम्मानित किया गया। अपने पुत्र सात्विक वीणा वादक सलिल भट्ट के साथ उन्होंने राग-'जोग' की मधुर प्रस्तुत की। किसी समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम रहे इस समारोह में अब संगीत की दूसरी शैलियों को लेकर भी उदारता दिखती है। शिवमणि के ड्रम और महंत जी के पखावज वादन के बीच यू राजेश के मेंडोलिन वादन को खूब पसंद किया गया। अनूप जलोटा तो पिछले कई सालों से आ ही रहे हैं, फिल्मों के संगीत निर्देशक राम शंकर और उनकी बेटी स्नेहा शंकर ने भी समारोह में प्रस्तुति दी। स्थानीय और बाहर से आए कई अन्य कलाकारों की प्रस्तुतियां भी समारोह के श्रोताओं को संगीत रस देती रहीं। ■

कैनवस | जय त्रिपाठी

लोक परंपरा का कला उत्सव

सांस्कृतिक धरोहर से उत्पन्न भारतीय चित्रकला की लोक कला एक जीवंत परंपरा है, जिसमें समृद्ध विविधता है। सदियों बाद भी आज भी गुफा चित्रों को देख कर कहा जा सकता है कि लोक और जनजातीय चित्रकला ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों से आती है। लोक कलाकार कलात्मक अभिव्यक्ति में प्रकृति के उस स्वरूप को चित्रित करते हैं जहां लोक चित्रकला मात्र कला के रूप में ही नहीं वरन दैनिक जीवन में किए जाने वाले धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान के रूप में जागृत हुई। मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को रंगते हुए लोक चित्रकला आज अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में व्याप्त है। जीवंत परंपरा के साथ-साथ वैचारिक दृष्टि से भी व्यापक होती लोक कला आज अपने उस उच्च स्तर पर आ पंहुची है, जहां फोकार्टोपीडिया जैसी संस्थाएं लोक कला का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर कर रही हैं।

फोकार्टोपीडिया ने लोक कला को कला के उस रूप में परिभाषित किया है, जो समाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप में पुरस्कृत कला से परिष्कृत होती यात्रा है। यह कला आयोजन पटना स्थित कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में 'लोक परंपरा का उत्सव' शीर्षक से आयोजित किया गया। त्रिदिवसीय राष्ट्रीय लोक चित्रकला के उद्घाटन के अवसर पर बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने देश भर की अनेक विधाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाने वाले इस आयोजन के लिए फोकार्टोपीडिया की प्रशंसा करते हुए विश्व धरोहर दिवस की बधाई भी दी और कहा कि उत्सव के साथ-साथ हमें अपनी लोक कलाओं को अक्षुण्ण रखने की भी जरूरत है।

भारतीय लोक कला को समृद्ध बनाने के लिए फोकार्टोपीडिया के संस्थापक निदेशक सुनील कुमार को कई कलाकारों ने लोक कला के लिए प्रेरित किया है और सुनील कुमार ने भी इन कलाकारों में भाव भरे कि कला न केवल रचनात्मकता की अभिव्यक्ति है, बल्कि यह अपने आप में एक अनुष्ठान है। प्रदर्शित चित्रों एवं व्याख्यानों से यह बात विशेष रूप से निकल कर आती है कि भूगोल और जलवायु द्वारा एक विशेष स्वरूप में आकार लेती लोक चित्रकला परंपराओं को संरक्षित एवं प्रचारित-प्रसारित करने की आवश्यकता है। विशिष्ट क्षेत्रीय संस्कृतियों द्वारा आकार लेती यही लोक कला कलाकारों और संरक्षकों की पहचान को विशिष्ट बनाती है।

दो दिनों के विमर्श के दौरान विभिन्न सत्रों में लोक कलाओं की पारंपरिक पहचान, समकालीन प्रयोग और सामाजिक प्रासंगिकता पर विमर्श हुआ जिसमें यह बात भी सामने आई कि क्षेत्रीय लोक कलाएं वैश्विक मंच पर किस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती हैं तथा पारंपरिकता और नवाचार के संतुलन को कैसे बनाए रखा जा सकता है। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य पारंपरिक कला और आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना है, ताकि कलाकारों को सामाजिक-आर्थिक समर्थन मिल सके। कला की आत्मा भी सुरक्षित रह सके। इस लोक उत्सव में पद्मश्री शांति देवी सहित कई लोक कलाकार के चित्रों को प्रदर्शित किया गया।

बिहार कला संस्कृति विभाग की डायरेक्टर रुबी, दिल्ली से प्रसार भारती बोर्ड के चैयरमैन नवनीत सहगल और फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, लखनऊ की डीन एवं प्राचार्या वंदना सहगल, मृदुला प्रकाश, विनय कुमार, नीलम चौधरी, पद्मश्री लोक कलाकार अशोक विश्वास एवं कलाकार गीतांजली ने फोकआर्टोपिडिया के आयोजन को सराहा। विजय प्रकाश ने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसी प्रदर्शनी देखी जहां भारत के 18 आर्ट फोरम देखने को मिले। 'लोक परंपरा का उत्सव' लोक परंपरा पर विमर्श गंभीर मंथन को संदर्भित करता है, जिसमें पारंपरिकता और नवाचार का संतुलन कैसे बनाए रखा जा सके, इस पर भी विचार हुआ। यह बात भी चर्चा में रही कि बिहार में लोकचित्रकलाओं पर केंद्रित यह अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय आयोजन है।

समकालीन प्रयोग और सामाजिक प्रासंगिकता पर विमर्श के दौरान आयोजन के समूचे परिदृश्य से यह बात विशेष तौर पर निकल कर आई कि फोकार्टोपीडिया ने लोक कलाओं पर काम करने वालों को ऐसा मंच दिया है जिससे लुप्तप्राय हो रही कलाओं को न सिर्फ संरक्षित किया जा रहा है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में भी लोक कला नई जगह बना रही है। प्रदर्शनी में कावी आर्ट, जूट आर्ट, जादोपटिया, गोंड, उराव, खोवर, चितारा, पट्टिचत्र, पिछवइ, पिथोड़ा, फड़, भील, भोजपुरी, मधुबनी, वरली, सुरपुर और सोहराइ जैसी लोकचित्र परंपराओं से जुड़ी देश भर के कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। ■

बचपन में 3 पहियों की साइकल से शुरुआत होती है और फिर हम 2 पहियों की साइकल पर बैलंस बनाना सीख जाते हैं। दिल्ली के रिटायर्ड विद्यालय प्रमुख और साइकलिस्ट भरत चंद ठाकुर यहां खुद बता रहे हैं कि कैसे उन्हें साइकल से प्यार हुआ और देश-विदेश के रोमांचक सफर का सिलसिला शुरू हुआ:

सैर कर दुनिया की ग़ाफ़िल
ज़िंदगानी फिर कहां

ज़िंदगी गर कुछ रही तो ये
जवानी फिर कहां
– ख़्वाजा मीर दर्द

साइकल पर दुनिया की सैर

यह साल 2018 की बात है। उदयपुर की एक संस्था की ओर से हुई 3 दिन की वर्कशॉप 'पर्यटक से मुसाफिर बनने का सफर' ने मेरी यात्रा और जीवन के प्रति सोच ही बदल दी। इसके बाद, मैंने साइकलिस्ट ग्रुप के लीडर राम जी की अगुवाई में 'स्व-पथगामी साइकल यात्रा' में हिस्सा लिया, जो गुजरात के तेजगढ़ के आदिवासी इलाके में आयोजित सप्ताह भर की यात्रा थी। इस दौरान हमारे पास में न मोबाइल था और न पैसे। देश के अलग-अलग हिस्सों से आए 19 साइकल यात्री इसमें शामिल हुए थे। हम पूरी तरह से गांवों, स्कूलों, पंचायतों और आश्रमों की मेहमान नवाजी पर निर्भर थे।

बेटे की साइकल से हुई थी शुरुआत

उस वक्त ज़िंदगी में एकरसता महसूस हो रही थी और मैं कोई बदलाव चाहता था। हालांकि मैं स्कूल के काम में बिजी रहता था, लेकिन कुछ नया करना चाहता था। मेरे बेटे की एक साइकल कई साल से बेकार पड़ी थी। मैंने उसे निकालकर नोएडा साइकलिंग क्लब के साथ वीकेंड साइकलिंग शुरू कर दी। एक साल बाद मैंने यूथ हॉस्टल असोसिएशन ऑफ इंडिया (YHAI) के साथ लेह-लद्दाख में साइकलिंग अभियान में हिस्सा लिया। कोविड-19 महामारी के बाद मैंने दिल्ली से जिम कॉर्बेट तक अपनी पहली सेल्फ सपोर्टिड साइकल यात्रा अपने दो साथियों के साथ की। वाकई, वह शानदार अनुभव था, जिसने मेरा हौसला इतना बढ़ाया कि लंबी दूरी वाला साइकल सफर शुरू हो गया।

नौकरी छोड़ी और साइकल थाम ली

अगस्त 2022 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और साइकल यात्राओं पर ज्यादा ध्यान देने लगा। मेरी पहली बड़ी यात्रा ओडिशा का साइक्लोथॉन 'टूर डी कलिंगा' रही, जिसमें मैंने 13 दिनों में ओडिशा की पहाड़ियों और आदिवासी इलाकों में 1300 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद मैंने भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारियों के संगठन 'अतुल्य गंगा साइक्लोथॉन' में हिस्सा लिया। तब हमने यमुनोत्री से आगरा तक साइकल चलाई। पहली इंटरनैशनल साइकल यात्रा भूटान में हुई जो अपनी कुदरती सुंदरता और ऊंचे हैपिनेस इंडेक्स के लिए मशहूर है। पहाड़ों और दर्रों के बीच साइकलिंग अनूठा अनुभव था। इसके बाद दिल्ली से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ (अपने जन्मस्थान) और कुमाऊं में साइकिलिंग की। बरसों से मैं धारचूला के पास नारायण आश्रम जाने का सपना देख रहा था और आखिरकार यह सफर साइकल से रानीखेत जाकर तक पूरा हुआ। गर्मियों में मैंने YHAI के मनाली-लेह-खारदुंगला अभियान में भाग लिया, जो दुनिया के सबसे मुश्किल और खूबसूरत साइकल रूटों में से एक है।

पामीर हाइवेः दुनिया की दूसरी ऊंची सड़क पर हम

अगस्त 2023 में मैंने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की - पामीर हाइवे अभियान (पामीर हाइवे को दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सड़क माना जाता है)। हमने ताजिकिस्तान की सड़क M-41 (पामीर हाइवे), ओल्ड सिल्क रूट के अलग-अलग हिस्सों में साइकल चलाई। कारवां लर्निंग स्कूल के बैनर तले हुई इस यात्रा में हमारे दल में भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल के कुल 6 साइकल यात्री शामिल थे। अफगानिस्तान की सीमा से लगी पंज नदी के साथ साइकल चलाते हुए हमने कई ऊंचाई वाले दर्रों को पार किया। हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मार्को पोलो और ह्वेनसांग जैसे महान यात्रियों के युग में पहुंच गए। हमने ताजिक लोगों की मेहमान-नवाज़ी और दरियादिली को भी महसूस किया। इस सफर में हमें बुखारा, समरकंद और ताशकंद जैसे ऐतिहासिक शहर भी देखे।

विदेशी गांव में नदी किनारे जन्मदिन: ताजिकिस्तान के पामीर हाइवे के किनारे बसे गांव का नाम है 'लंगर'। 23 अगस्त, 2023 की सुबह हम वहां थे। साथी राइडर्स ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। मैंने सबको खजूर बांटे। तब मुझे उस स्कूल की याद आई जहां मैं विद्यालय प्रमुख था। वहां बच्चे अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी या चॉकलेट दिया करते थे। इसके बाद का सफर मुश्किलों भरा था - ऊंची चढ़ाई, कंकरीले रास्ते और बार-बार साइकल को धकेलना पड़ा। 12 किलोमीटर के बाद टेंट लगाया। हमने बाजरे और आलू की खिचड़ी बनाई। शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन खुले आसमान के नीचे सोने का सुख कुछ अलग ही था। करीब 1 किलोमीटर बाद हमें नदी पार करनी थी- पानी जांघ तक था और बहाव तेज। सौभाग्य से छोटा टोयोटा ट्रक मिला, जिसने हमारी साइकल को और हमें नदी पार कराई। शाम ढल रही थी, ठंड बढ़ने लगी और दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। लेकिन 8 किलोमीटर आगे हमें एक शेल्टर हाउस दिखा। वहां पानी की बाल्टी, लकड़ी जलाने की जगह, कुछ तेल, बर्तन और 6-7 लोगों के लिए बिस्तर व कपड़े रखे थे। हालांकि, हमने अपने स्लीपिंग बैग्स का ही इस्तेमाल किया। इस रात को खास बना दिया साथी योगेंद्र सिंह ने। उन्होंने सबको हलवा बनाया। हमारे यूरोपीय साथी उसे बड़े चाव से खा रहे थे। इससे बेहतर जन्मदिन शायद ही सेलिब्रेट होता।

2700 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा

देश लौटकर मैंने अपने साथी योगेन्द्र के साथ 2700 किमी की नर्मदा नदी की परिक्रमा पूरी की। यह दुनिया की एकमात्र नदी परिक्रमा है, जिसमें आपको किसी भी बिंदु पर नदी को पार नहीं करना है। अमरकंटक से अरब सागर और वापसी में नर्मदा मैया के साथ-साथ की गई यात्रा, जहां 'नर्मदे हर' की गूंज हर मुश्किल का हल बन गई। फिर मैंने श्रीलंका में 1700 किलोमीटर की साइकल यात्रा की। इस सफर में तटीय कोलंबो, गाले, त्रिंकोमाली, जाफना, मन्नार, पहाड़ी कैंडी और नुवारा एलिया जैसी जगहों से होकर गुजरे। वहां हमने रामायण से जुड़े ऐतिहासिक स्थल और श्रीलंका की संस्कृति को करीब से देखा।

ऐसे मिला पहला SR टाइटल (2024)

पिछले साल ही मैंने सुपर रॉन्दोनर (Super Randonneur - SR) का खिताब हासिल किया। साइकलिंग में SR टाइटल उन्हें दिया जाता है जो एक ही कैलेंडर ईयर में 200 किमी, 300 किमी, 400 किमी और 600 किमी की ब्रुवे (Brevet) राइड्स पूरी करते हैं। यह लंबी दूरी की साइकलिंग में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इस सफर में सिर्फ दूरी पार करना ही चुनौती नहीं थी, बल्कि अनजानी रुकावटों को पार करना और अपनी मानसिक व शारीरिक सीमाओं को भी लांघना था। इससे न केवल हिम्मत बढ़ी, बल्कि उन साइकल यात्रियों के साथ खास जुड़ाव भी महसूस हुआ जो इसी जुनून को जीते हैं।

भारत की खोज - रेगिस्तान से समुद्र तक

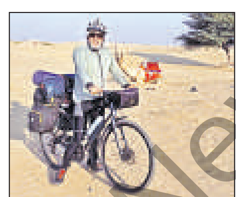

साल 2024 की गर्मियों में मैंने और मेरे साथी योगेन्द्र ने दिल्ली से स्पीति घाटी तक साइकलिंग की। हिमालय के शिमला, किन्नौर, छितकुल और लोसर घाटी में साइकल चलाने का अनुभव बिलकुल अलग था। कुछ अरसा पहले ही राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में 3700 किमी का साइकल सफर किया है। इस दौरान राजस्थान की हवेलियों, थार मरुस्थल, कच्छ के रण, भारत-पाक सीमा के साथ जामनगर, द्वारका, सोमनाथ, सूरत और मुंबई तक पहुंचा।

अनजाने मुल्क में दोस्ती

मिस्टर और मिसेज उरबेक का पिश गांव

ताजिकिस्तान के पामीर हाइवे के किनारे ही पिश नाम के गांव से गुजरते हुए हमने देखा कि मि. उरबेक सड़क के बीचों-बीच खुद ही टूटी हुई पानी की पाइपलाइन ठीक कर रहे थे, जो उनके घर की ओर जा रही थी। हमने उनसे सिर्फ पानी (ताजिक में ओब) मांगा था, लेकिन उन्होंने हमें सीधे अपने घर चाय के लिए बुला लिया। घर में मुलायम कालीनों से सजे फर्श पर बैठते ही हमारे सामने ताजे उबले आलू रख दिए गए जो उनके अपने खेतों के थे। फिर खीरे, सलामी, ब्रेड, कुकीज़, चॉकलेट और गर्म काली चाय का बड़ा फ्लास्क भी आ गया। थोड़ी देर बाद हमारे यूरोपीय साथी भी आ पहुंचे। बातचीत कभी इशारों में, कभी गूगल ट्रांसलेटर की मदद से की गई। उनके घर के पास ही पंज नदी बह रही थी, जिसके उस पार अफगानिस्तान था। मि. उरबेक ने बताया कि पहले वह तैरकर अफगानिस्तान पहुंच जाते थे। लेकिन अब सीमाएं बंद हैं। तालिबान के कब्जे के बाद हालात बदल गए हैं।

मिसेज उरबेक बेहद सौम्य और विनम्र थीं, वह पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं और उनके बच्चे भी वहीं नौकरी कर रहे हैं। पूरी यात्रा में ताजिक मेहमान-नवाज़ी बार-बार दिल छू गई। ये लोग मेहमानों के लिए घर और दिल दोनों के दरवाजे खोल देते हैं। वैसे 'हिंदुस्तानियों' के लिए यहां अलग ही स्नेह देखने को मिला।

जीना सिखाया इस धीमे सफर ने

मैंने साइकलिंग के अनुभव से सीखा कि कम सामान लेकर चलना, बजट वाली या मुफ्त जगहों पर रुकना और अनजानी परिस्थितियों से तालमेल बिठाने में ही सफर का असली मजा आता है। साइकलिंग ने मुझे सिखाया कि धीमी गति में भी अलग तरह की ताकत होती है। साइकलिंग हमें हर छोटी चीज़ को देखने, सुनने और महसूस करने के लिए मजबूर करती है - जैसे पेड़ों की सरसराहट, आसमान के बदलते रंग, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू। यह सफर सिर्फ पहियों पर नहीं, बल्कि हर सांस में जीने का अहसास है।

साइकल यात्रा में सबसे बड़ी खुशी यह होती है कि आप उन गांवों और जगहों को देख सकते हैं, जो आम टूरिस्ट कभी नहीं देख पाते। इस सफर में अनजान भी अपने बन जाते हैं। न जाने कितनी बार अजनबियों ने हमें अपने घर बुलाया, अपने हिस्से का खाना बांटा, चाय पर बातें कीं। भाषा और संस्कृति की दीवारें इंसानियत की गर्मजोशी के आगे छोटी पड़ जाती हैं। इन यात्राओं में मैंने सिर्फ नई जगहों की ही खोज नहीं की, बल्कि खुद को भी टटोला। पामीर हाइवे की ऊंचाइयों से लेकर स्पीति की दुर्गम घाटियों तक, श्रीलंका के शांत समुद्री तटों से लेकर भूटान के ऊचे दर्रों तक या नर्मदा परिक्रमा के आध्यात्मिक मार्ग से लेकर अनगिनत अनजान रास्तों तक - हर सफर सिर्फ एक साइकल यात्रा नहीं था, बल्कि आत्मिक और मानसिक अनुभव रहा है।

लेकिन हर दिन आसान नहीं होता। कभी तेज चढ़ाई, कभी तेज हवाएं, कभी टायर पंचर, कभी थकावट हद से ज्यादा। लेकिन यह सफर सिखाता है कि हर मुश्किल गुजर ही जाती है। अब धीरे-धीरे लंबी दूरी के सफर पर जाने और दूसरे देशों को साइकलिंग की सीमाओं के भीतर लाने का मन है। वैसे हमारे देश में लंबी दूरी की साइकलिंग अब भी ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। यूरोपीय देशों के मुकाबले यहां अच्छे साइकल ट्रैक न होना, सुरक्षा व्यवस्था और सड़क की क्वॉलिटी बढ़िया न होना जैसी चुनौतियां हैं।

विचार विंडो

कैंसर वॉर्डः दर्द के हमसफर

■ संजय खाती

उनकी उम्र शायद 70 साल है या शायद 80। कैंसर रोगियों की उम्र जानना मुश्किल होता है। उनका नाम शारदा है। बेड नंबर 16 पर लेटी वह कभी धीमे और कभी ऊंचे स्वर में कुछ बड़बड़ा रही हैं। वह असल में अपने बेटे को याद कर रही हैं जो ठीक उस समय कहीं गायब हो गया है जब नाश्ते की गाड़ी वॉर्ड में पहुंच रही है। उन्हें मदद चाहिए और यह बात वह एक लंबे किस्से की तरह सुनने वाले कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। जैसा कि वॉर्ड में अक्सर होता है, कोई सहयात्री मदद के लिए आ जाता है और शारदा को उनका नाश्ता मिल जाता है -एक गिलास दूध, दो ब्रेड और दो उबले अंडे। धीरे-धीरे वह इस नाश्ते को ठिकाने लगाती हैं, लेकिन एक अंडा उन्होंने बचा लिया है।

बिच्छू का डंक

कैंसर वॉर्ड में जिंदगी धीरे-धीरे चलती है। एक सरकारी और तीन प्राइवेट कैंसर वॉर्डों से गुजरने के बाद मैं इस रिदम को शायद पहचानने लगा हूं। सरकारी और प्राइवेट की दुनिया बाहर से दिखने में अलग-अलग लगती है, लेकिन कैंसर की जो कहानी भारतीय समाज में आगे बढ़ रही है, उसका तूफानी अंदाज किसी से अब छिपा नहीं होना चाहिए। अपने आसपास देखिए, बहुत कम ऐसे परिवार हैं जिनमें कैंसर की चिंता की नौबत न आई हो। प्राइवेट अस्पतालों में यह तूफानी हलचल बहुत सारे सुहाने इंतजामों और रोशनियों के बीच अक्सर छुप जाती है। दर्द पर्दों के पीछे रह जाता है। बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब भी मैं गया, मुझे लगा किसी रेस्टोरेंट में आ गया हूं। हर तरफ कॉफी और बेकरी की महक। यहां वॉर्ड में एक सम्मानित खामोशी है। एक दूरी, जो दर्द को ट्रेजडी में तब्दील होने से जबरन रोक देती है।

अफसोस और उम्मीद

ऊपर मैंने सहयात्री शब्द का इस्तेमाल किया। लगभग एक जैसे सूखते, सिकुड़ते, लड़खड़ाते शरीरों की इस साझी दुनिया में एक बिरादराना भाव चुटकियों में पनप जाता है। एक ही रोग की अलग-अलग कहानियां शेयर की जाने लगती हैं। दिल, गुर्दे या किसी भी दूसरी बीमारी की तरह कैंसर एक जैसा नहीं होता। इसलिए हर किसी का अनुभव नया हो जाता है। कैंसर वॉर्ड में कैंसर शब्द आमतौर पर सुनाई नहीं देता। उसे सिर्फ बीमारी कहा जाता है। यहां उन टोटकों की भी चर्चा नहीं होती जिनकी सोशल मीडिया में भरमार है। बकरी के मूत्र से लेकर महापुरुषों के आशीर्वाद तक जो भी चुटकियों में कैंसर को हवा कर सकता है, वह दावा यहां मजाक की बात बन चुका है। बचा है सिर्फ अफसोस और एक उम्मीद कि किसी दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इलाज और डॉक्टर पर आखिरी यकीन। कई-कई बरसों से घर और वॉर्ड के बीच आवाजाही जारी है, फिर भी हौसला टूटता नहीं। अमेरिकन डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी ने कैंसर को सभी बीमारियों का बादशाह (The Emperor of All Maladies) ऐसे ही नहीं कहा। वह सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी भी। वह कई-कई रूप लेकर आता है और अलग-अलग तरीकों से अपने शिकार से खेलता है। इस बहुरूपिये आतंकवादी के चरित्र को जरा समझते हैं;

Adobe Stock

फंड के लिए कैंसर मिशन

आंकड़े बताते हैं कि कैंसर आने वाले वक्त की सबसे बड़ी महामारी हो सकती है। सिर्फ संख्या के लिहाज से नहीं, परिवार और समाज पर इसके असर की घातकता को लेकर। कैंसर का इलाज लंबा और महंगा होता है, उसके बजट का पहले से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारे जैसे मुल्क में जहां सालाना बजट का सिर्फ 2.5 पर्सेंट स्वास्थ्य पर खर्च हो पाता हो, वहां कैंसर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या यह मुमकिन है कि सरकार एक कैंसर मिशन की शुरुआत करे जिसके लिए अलग से सेस लगाए या तमाम तरीकों से फंड का इंतजाम करें? जिस तरह टाटा ने कैंसर के इलाज में बहुमूल्य योगदान दिया है, वैसे ही दूसरे दानदाता इस फंड को कामयाब बनाएं। और जब ऐसा हो जाए तो तमाम जरूरतमंद हिंदुस्तानियों को सिर्फ बेहतर इलाज ही न मिले वॉर्ड से बाहर भी उनकी देखरेख का कुछ इंतजाम हो सके। उन्हे अपने रखरखाव और पोषण के लिए कुछ पैसा हाथ में मिले।

- ■ क्योंकि कैंसर कोशिका विभाजन (सेल डिविजन) की बायोलॉजिकल प्रोसेस का ही बुरा पहलू है, इसलिए उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता।
- ■ कैंसर अनगिनत वजहों से हो सकता है, इसलिए यह भी मुमकिन नहीं कि एक खास तरह का जीवन जीकर उससे बचा जा सके जैसा कि कई दूसरी बीमारियों में मुमकिन है।
- ■ कैंसर से लड़ाई का पहला मोर्चा है वक्त पर उसकी पहचान। लेकिन इस तरह की प्रिवेंटिव डायग्नोसिस भारत जैसे देश में कब और कितनी हो सकेगी, यह एक मुश्किल सवाल है?
- ■ अगर वक्त रहते पहचान हो जाए तो बहुत-से कैंसर मरीजों का इलाज हो सकता है। लेकिन कई तरह के मरीज दो वजहों से इलाज से बाहर छूट सकते हैंः पहले वे हैं जिनके इलाज के लिए महंगे प्रोसीजर और महंगी दवाओं की जरूरत पड़ेगी। सरकारी सिस्टम में खर्च की सीमाएं बहुत साफ हैं। प्राइवेट मामलों में भी खर्च की बात आड़े आ सकती है। सिर्फ अमीर या सेलिब्रिटी विदेश में जाकर इस तरह के इलाज का फायदा उठा पाते हैं।
- ■ दूसरे वे मरीज हैं जिनके कैंसर का कोई इलाज अभी तक निकला ही नहीं है। इनके लिए जिंदगी की मोहलत बढ़ाने का उपाय ही बचता है।
- ■ कैंसर की दुनिया में जबरदस्त रिसर्च हो रही है और नए-नए इलाजों पर ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन वह वक्त अभी कुछ दूर है जब सभी तरह के कैंसर का संतोषजनक इलाज निकल आए। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के जमाने में इसकी उम्मीद काफी बढ़ गई है, लेकिन बात घूम कर वहीं आ जाती है कि अगर इलाज मुमकिन भी हो तो कितने लोग उसका खर्च उठा पाएंगे?

सिर्फ इलाज से क्या

इन तथ्यों में वह बात जोड़ना जरूरी है जो मुझे इस वक्त सबसे अहम नजर आती है। आपको वह उबला हुआ अंडा याद है जिसका जिक्र शुरू में आया था? शारदा ने उसे रख दिया था अपने उस बेटे के लिए जो काफी देर से कहीं गायब था। अब वह आ गया है और अंडे को खा रहा है। आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए नहीं कि शारदा का बेटा गैर-जिम्मेदार है बल्कि इसलिए कि वह अंडा एक कैंसर मरीज की डाइट का हिस्सा है जिसे सामान्य से ज्यादा पोषण की जरूरत है क्योंकि उसकी कीमोथेरपी चल रही है। जाहिर है, नाश्ते में दो अंडे शारदा को अपने घर में शायद ही मयस्सर होते हों। उन्हें पोषण चाहिए। और ऐसा ही पोषण उन लाखों हिंदुस्तानियों को भी चाहिए जिन्हें कैंसर ने अपना शिकार बनाया है। क्या यह मुमकिन है?

जो मैंने देखा] वह निराशाजनक है। कैंसर सहयात्रियों में से इक्का-दुक्का को ही मैंने पोषण को लेकर जागरूक देखा। ज्यादातर के लिए यह चर्चा से बाहर की बात थी। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि कैंसर थेरपी के दौरान शरीर पर बहुत ही बुरे असर पड़ते हैं। भूख चली जाती है और शरीर सूखता चला जाता है। ऐसे में अच्छा पोषक भोजन और इंफेक्शन से बचाव- दो बहुत जरूरी बातें हैं और दोनों ही हमारे मौजूदा सिस्टम में नामुमकिन-सी बात लगती हैं। यहां मैं बहुसंख्यक भारतीयों की बात कर रहा हूं, प्राइवेट अस्पतालों के मरीजों की नहीं। ज्यादातर मरीज कुछ भी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। इंफेक्शन से बचाव की तो उनके माहौल में कोई गुंजाइश ही नहीं। इन बातों की उनसे अपेक्षा करना भी एक पाप लगता है जब हम देखते हैं कि कैंसर किसी एक शरीर का नहीं, एक साथ कई ज़िंदगियों और परिवार का रोग है। हर कैंसर मरीज के पीछे उजड़ता हुआ परिवार नजर आएगा।

बराबरी = की भाषा
नवभारत टाइम्स की पहल

सैनिक का भी होगा स्त्रीलिंग शब्द

जब मैदान में बराबरी है तो शब्दों में क्यों नहीं?

■ नमिता जोशी

जब भी देश पर खतरा आया, मोर्चा संभालने में न कोई मूंछ का झंडा लेकर दौड़ा, न कोई चूड़ी दिखाकर पीछे हटा। वीर भगत सिंह हों या वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अहिल्याबाई होल्कर, सबने जान दांव पर लगाई। तब भाषा ने भी समझदारी दिखाई और 'वीरांगना' जैसा सम्मानजनक शब्द गढ़ लिया। किसी ने नहीं कहा कि 'रानी लक्ष्मीबाई को बस वीर ही कहो, भाषा के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो?' आज जब महिलाएं सेना में हथियार उठाकर देश की रक्षा कर रही हैं, तब 'सैनिक' शब्द का स्त्रीलिंग बनाने में हम पीछे क्यों रहें?

नवभारत टाइम्स ने 'बराबरी की भाषा' के तहत पिछले कुछ समय से यह काम शुरू किया है। हम उन शब्दों की पहचान बदल रहे हैं जो बरसों से सिर्फ पुरुषों की जागीर बने बैठे थे। जब महिलाएं धरती से आकाश तक फतह कर रही हैं, तो शब्दकोश में भी उनकी बराबरी दर्ज होनी चाहिए। हो सकता है कि सैनिक शब्द का अब तक स्त्रीलिंग इसलिए नहीं बना क्योंकि पहले फौज में महिलाएं औपचारिक तौर पर नहीं थीं। मगर हकीकत यह भी है कि झांसी की रानी से लेकर महारानी दुर्गावती तक युद्धकला में पारंगत थीं। तब तो भाषा ने उन्हें वीरांगना कहा था- बड़े गर्व से, न कि किसी टीका-टिप्पणी के साथ!

लेकिन आज कुछ विद्वान चिंतित हैं – 'भाषा टूट जाएगी!, क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा करने से क्या हासिल होगा, ये तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है' तो विद्वान भाई साहब और बहनजी, जब अंग्रेज़ी में actor से actress, फ्रेंच में auteur से autrice, स्पैनिश में doctor से doctora बन गया, तब किसी की संस्कृति का सर्वनाश नहीं हुआ, बल्कि भाषा ने महिलाओं का सम्मान करना सीखा। जब झांसी की रानी को वीरांगना कहकर दुनिया ने सिर झुकाया था, तब किसी ने 'हिंदी बर्बाद हो गई' की हेडलाइन नहीं चिपकाई थी और न ही सोशल मीडिया में जाकर अपना गुस्सा दिखाया था।

कुछ लोग सवाल उठाते हैं — दुनिया तो जेंडर न्यूट्रल हो रही है, एनबीटी क्यों नए-नए स्त्रीलिंग शब्द गढ़कर फर्क पैदा कर रहा है? लोग जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट तक बना रहे हैं फिर एनबीटी क्यों पिछड़ेपन की बात कर रहा है। तो भई, अगर सब कुछ वाकई न्यूट्रल होता तो किसी महिला सैनिक को 'महिला सैनिक' क्यों कहना पड़ता? सीधा सैनिक कह देते न! महिला डॉक्टर, महिला पुलिस अधिकारी क्यों कहना पड़ता है? कहना पड़ता है, क्योंकि 'सैनिक' सुनते ही ज़हन में पहले पुरुष की तस्वीर बनती है। सिर्फ पुलिस अधिकारी कहेंगे तो मूंछ वाले कड़क पुरुष की छवि उभरती है। असल दिक्कत यहीं है। भाषा जब तक invisibility की चादर ओढ़े रहेगी, बराबरी बस कागज़ों तक सीमित रहेगी। असल में 'न्यूट्रल' का नाम लेकर भाषा में जो ,खाली स्थान है, उसमें पुरुषत्व का कब्जा है। एनबीटी की 'बराबरी की भाषा' पहल उस कब्जे को चुनौती देती है। यह कोई दीवार नहीं खड़ी कर रही, बल्कि उन दरवाज़ों को खोल रही है, जो पहले से एकतरफा बंद थे। बराबरी का मतलब सबका दिखना है, सिर्फ एक का नहीं। जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम हों या नीतियां, ये एक जरूरत हैं, ताकि सभी को समान सुविधा और सम्मान मिले, लेकिन पेशेवर पहचान में बराबरी तब दिखेगी जब महिलाएं भी भाषा में अपने आप शामिल होंगी, अपने पूरे गौरव के साथ। 'बराबरी की भाषा' का मकसद कोई खाई नहीं बनाना है, बल्कि वह पुल बनाना है जिससे हर पहचान बिना सफाई मांगे, बिना झिझक के गुजर सके।

असल सवाल भाषा का नहीं, बराबरी का है। अगर सेना में महिलाएं दिन-रात ड्यूटी कर सकती हैं, बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा ले सकती हैं, तो शब्दकोश में उनका ठिकाना बनाने में इतनी हिचक क्यों? अब फैसला आपके हाथ में है।

जब खतरा सामने आया तो न किसी ने मूंछों का दम देखा, न चूड़ियों की झिझक। झांसी की रानी से लेकर अहिल्याबाई तक, वीरों और वीरांगनाओं ने बराबरी से लड़ा। अब जब महिलाएं भी सेना में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो शब्दों में भी उनकी बराबरी तय होनी चाहिए।

इस हफ्ते का शब्द

सैनिक का स्त्रीलिंग क्या हो?

- A सैनिका
- B सैन्या
- C रक्षिका
- D या कुछ और

याद रखिए, जब लड़ाई बराबरी की है तो जीत भी भाषा में दर्ज होनी चाहिए!

आप सुझाव दें कि इस शब्द का स्त्रीलिंग क्या होना चाहिए। हमें ई-मेल करें nbtreader@timesofindia.com पर शनिवार शाम 5 बजे तक। सब्जेक्ट में लिखें Barabarikibhasha

इस QR कोड को स्कैन करके लेख के अंत में वोट डालें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर एमएएचएचआईएन/ 2009/27562 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः(022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 6.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 7.00 रुपये।

एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं इस बात से वाकिफ हूं कि जीवन एक व्यापार है। -पीटर ब्लेयर हेनरी

स्क्रीन पर वुल्फ वॉरियर-2 की धमक। लेंग फेंग, स्पेशल ऑप्स का बागी सिपाही, अफ्रीका में अमेरिकियों को धूल चटाता है। उसका डायलॉग गूंजता है : 'चीन का दुश्मन कहीं भी हो, मिटा देंगे!' यह 141 ईसा पूर्व के हान जनरल की गूंज थी, जिसे इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। शी जिनपिंग के चीन की नई कूटनीति का यही कोड है। यह ग्लोबल साउथ के देशों को बीजिंग की तरफ खींचने का इशारा करती है।

ड्रैगन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी

कूटनीतिक गलियारों में 'ड्रैगन प्लान' की चर्चा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, और ब्रिक्स देशों में चीनी निवेश की बाढ़, डॉलर को चुनौती देने के लिए एक नई डिजिटल करेंसी का प्लान। ग्लोबल साउथ का नया आर्थिक गठजोड़, तो यह सब ट्रेड वार की तैयारी का हिस्सा था।

ड्रैगन को मंदी रोकते हुए ट्रेड वार जीतना है, क्या शी से हो पाएगा?

अंशुमान तिवारी

वरिष्ठ पत्रकार

कूटनीति के आलिम-फाजिल चिल्ला रहे हैं कि शी जिनपिंग ने ट्रंप के ट्रेड वार का जवाब देने की बिसात पहले ही बिछा ली है। अफसरों की छुट्टियां रद्द, पुराने कूटनीतिक शेर मैदान में, और हर टैरिफ का जवाब तड़ाक से! वाशिंगटन को अब समझ में आ रहा है कि ड्रैगन किसी प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। शी का प्रशासन कह रहा है कि अमेरिका के टैरिफ से आसमान नहीं फटने वाला। चुप्पा और अदृश्य कूटनीति वाले चीन में अब वुल्फ वॉरियर दहाड़ रहे हैं। बज रहे हैं ट्रेड वार के जंगी नगाडे। आइए, बैठिए टाइम मशीन में, हम ले चलते हैं उस सफर पर, जहां इस जंग की जड़ें हैं।

पहला पड़ाव, नानकिंग, 1842-

टाइम मशीन नानकिंग के तट पर उतर रही है। हवा में बारूद की गंध है। ब्रिटिश तोपों की गूंज अभी थमी है। अफीम युद्ध ने क्विंग साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया है। चीन में ब्रिटेन के अफीम के कारोबार को रोकना भारी पड़ा है। क्विंग हार गए हैं। नानकिंग संधि ने चीन का सीना चाक कर दिया-हांगकांग ब्रिटेन की जेब में, पांच बंदरगाह विदेशियों के लिए खुल गए हैं। सम्राट के चेहरे पर शर्मिंदगी की स्याही पुत गई है।

नानकिंग में चर्चा है कि एक पुरानी किताब में क्विंग दरबार के एक गुमनाम अफसर की चिट्ठी मिली है, 'ये अपमान हमारा अंत नहीं, बल्कि इससे एक नई ताकत का जन्म होगा। सदी बाद हमारा सूरज फिर चमकेगा।' नानकिंग की संधि के साथ चीन के 'अपमान की सदी' शुरू हो रही है। पश्चिम का रौब बढ़ा है। चीनी दिलों में गुस्सा भड़कने लगा है। टाइम मशीन 1900 में सरकती है। यिहेक्वान के बॉक्सर बागी पश्चिम के खिलाफ उबल पड़े हैं। मार्शल आर्ट के उस्ताद, गुस्साए नौजवान, बिना किसी सरदार के दूतावासों पर टूट पड़ते हैं। बीजिंग में अफवाह उड़ रही है कि बागियों का नेतृत्व कोई 'छाया योद्धा' कर रहा है, जो रात में गायब हो जाता है। पर सात पश्चिमी देशों की फौजों ने बगावत को रौंद दिया है। आप अब 1901 की बॉक्सर संधि यानी चीन के नए अपमान के गवाह हैं। बीजिंग की सड़कों पर संधि की शर्तें लटकी हैं। चीनी दिलों में अपमान की भट्ठियां जल रही हैं।

टाइम मशीन — अतीत से सुनें वर्तमान की धड़कन ■ हर पखवाड़े

दूसरा पड़ाव, 1979, वाशिंगटन-

टाइम मशीन 1979 में वाशिंगटन में उतर गई है। देंग श्याओपेंग, छोटे कद का जादूगर, अमेरिकी धरती पर कदम रखता है। माओ का दौर गया, देंग ने नई राह दिखाई है- 'ताकत छिपाओ, वक्त का इंतजार करो।' निक्सन की 1972 की यात्रा और हेनरी किसिंजर की कोशिशों ने बर्फ पिघलानी शुरू की है।

कूटनीतिक गलियों में चर्चा है कि देंग अपनी अमेरिका यात्रा से पहले बीजिंग के एक गुप्त कमरे में किसिंजर से मिले थे। मेज पर सिर्फ चीनी चाय नहीं, बल्कि एक बड़ा सौदा था-अमेरिका को सस्ता माल, और चीन को तकनीक। देंग ने मुस्कराते हुए कहा, 'पहले अमीर बनो, फिर हिसाब करेंगे।' अमेरिका ने चीन को 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का तमगा थमाया है। व्यापार के दरवाजे खुले, अमेरिकी कंपनियां चीन की ओर लपकीं और शंघाई में फैक्टरियां चमकने लगी हैं। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में घुसा, और बीस साल बाद अमेरिकी बाजार उसकी मुट्ठी में है।

तीसरा पड़ाव, 2017, बीजिंग का सिनेमा घर-

टाइम मशीन 2017 में सिनेमा हॉल के अंधेरे में उतर गई है। स्क्रीन पर वुल्फ वॉरियर-2 की धमक। लेंग फेंग, स्पेशल ऑप्स का बागी सिपाही, अफ्रीका में अमेरिकियों को धूल चटाता है। उसका डायलॉग गूंजता है : 'चीन का दुश्मन कहीं भी हो, मिटा देंगे!' यह 141 ईसा पूर्व के हान जनरल की गूंज थी, जो इस फिल्म में इस्तेमाल हुई है।

यह शी जिनपिंग के चीन की नई कूटनीति का कोड भी है। शी जिनपिंग ने देंग युग की शांति को छोड़ दहाड़ते वुल्फ वॉरियर को अपना कूटनीतिक प्रतीक बनाया है। यह फिल्म ग्लोबल साउथ के देशों को बीजिंग की तरफ खींचने का इशारा करती है। शी ने पार्टी पर शिकंजा कसा, और दुनिया को ललकारा-अब चीन झुकेगा नहीं। 'वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी' का डंका बजने लगा है। बीजिंग के दूतावासों से राजनयिक एक्स पर पश्चिम को दो टूक जवाब दे रहे हैं। इधर बेल्ट एंड रोड की सड़कें बिछ रही हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी बढ़ रही है। अफ्रीका के बाजारों में चीनी सामान की धूम है। चीन अपना कारोबारी जाल फैला चुका है।

चौथा पड़ाव 2021, एंकरेज अलास्का- अब हम अलास्का के एंकरेज में बर्फीली हवाओं के बीच हैं। बाइडन प्रशासन और चीन आमने-सामने। बात शुरू होते ही तलवारें खिंचीं। चीन बोला, 'अमेरिका हमें बदनाम कर रहा है!' अमेरिका ने पलटवार किया, 'चीन हमें नीचा दिखाने की साजिश लेकर आया है।' बैठक बेकार गई।

पीपल्स डेली ने वीबो पर दो तस्वीरें चिपकाईं -1901 की बॉक्सर संधि और एंकरेज। संदेश साफ : अमेरिका फिर वही अपमान दोहराना चाहता है, लेकिन बीजिंग कह रहा है 'हम अब वह चीन नहीं, जो झुकें!' कहते हैं कि चीन के राजनयिकों ने बैठक से पहले एक गुप्त रणनीति बनाई थी-हर सवाल का जवाब इतिहास से देना, ताकि दुनिया को याद दिलाया जाए कि अपमान की सदी अब बीत चुकी है।

बीजिंग 2025,

अब हम बीजिंग में हैं ट्रंप के 145 फीसदी टैरिफ के बदले शी ने अपनी बिसात बिछा दी है- रेयर अर्थ का निर्यात रोका, बोइंग के ऑर्डर काटे, अमेरिकी खेती पर चोट-चीन ने कमर कस ली। कूटनीतिक गलियारों में 'ड्रैगन प्लान' की चर्चा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, और ब्रिक्स देशों में चीनी निवेश की बाढ़, डॉलर को चुनौती देने के लिए एक नई डिजिटल करेंसी का प्लान। ग्लोबल साउथ का नया आर्थिक गठजोड़, तो यह सब ट्रेड वार की तैयारी का हिस्सा था! अलबत्ता घर में मंदी, बेरोजगारी, और जनविरोध का डर भी है। शी ने वेतन बढ़ाए, रियायतें दीं, पर ड्रैगन को मंदी रोकते हुए ट्रेड वार जीतना है, क्या शी से हो पाएगा? यात्रीगण, कृपया ध्यान दें, टाइम मशीन का सफर यहीं तक है। आप इस रोमांचक पल के गवाह बनिए। आप इतिहास में छिपे आज और आज में छिपे इतिहास को बनता देख रहे हैं। फिर मिलते हैं, जल्द ही अगले सफर पर...

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग

लेखक एवं अनुवादक

पापात्मा वेन के शासन में धर्म का लोप हो गया। इस तरह वेन, भगवान विष्णु के वरदान और सुशंख के शाप का मिश्रण सिद्ध हुआ। आखिर वेन के पापों से दुखी ऋषियों ने उसका अंत कर दिया।

वरदान और शाप का मिश्रण था राजा वेन

मृत्यु की एक पुत्री थी। उसका नाम सुनीथा था। एक दिन सुनीथा अपनी सखियों के साथ वन में गई। वहां उसने गंधर्वकुमार सुशंख को तपस्या में लीन देखा। सुनीथा सुशंख को सताने लगी। सुशंख ने सुनीथा को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिर सुशंख को क्रोध आ गया। उन्होंने सुनीथा को शाप दे दियाः 'विवाह के बाद तुम्हारे गर्भ से पापाचारी और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा।' यह शाप सुनकर सुनीथा बहुत दुखी हुई और घर लौट आई। इस बीच महर्षि अत्रि के पुत्र अंग नंदन वन में गए और उन्होंने वहां देवराज इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव और भोग-विलास को देखकर अंग के मन में इंद्र के समान पुत्र पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उन्होंने लौटकर अपने पिता अत्रि से कहा, 'मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र चाहिए। इसका कोई उपाय बताएं।' अत्रि ने अंग को भगवान श्रीविष्णु की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने का सुझाव दिया। यह सुनकर अंग ने भगवान की कठोर तपस्या शुरू कर दी। अंग की तपस्या से प्रसन्न होकर श्रीविष्णु प्रकट हुए और बोले, 'मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं, कोई वर मांग लो।' अंग ने हर्ष में भरकर कहा, 'देवेश्वर! मुझे इंद्र के समान तेजस्वी पुत्र देने की कृपा करें।' भगवान विष्णु अंग को पुत्र का आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। इस बीच, सुशंख के शाप से दुखी सुनीथा वन में गई और तपस्या करने लगी। एक दिन उसके पास रंभा आदि सखियां आईं। उन्होंने सुनीथा से उसके दुख का कारण पूछा, तो सुनीथा ने सारी बात कह दी।

धूप आने दो

> सारा वृतांत सुनकर सखियों ने कहा, 'तुम दुख को त्याग दो। तुम सर्वगुण संपन्न और उत्तम अंगों से युक्त हो। हम तुम्हें ऐसी विद्या प्रदान करेंगे, जो पुरुषों को मोहित कर लेती है।'

यह कहकर सखियों ने सुनीथा को वह विद्या प्रदान की और कहा, 'कल्याणी! अब तुम जिस भी पुरुष को चाहो, उसे तत्काल मोहित कर सकती हो।' सखियों के यों कहने पर सुनीथा ने उस विद्या का अभ्यास किया और उसमें सिद्ध हो गई। फिर सुनीथा सखियों के साथ ही वन में घूमने लगी। एक दिन उसने गंगाजी के तट पर महर्षि अत्रि के पुत्र अंग को देखा। उसने अपनी सखियों से अंग के विषय में पूछा, तो रंभा बोली, 'यह महर्षि अत्रि के पुत्र अंग हैं। इन्होंने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इंद्र के समान पुत्र का वरदान पाया है। तुम महाराज अंग को मोहित कर लो, तो तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी।' यह सुनकर सुनीथा, अंग के निकट बैठकर मधुर स्वर में गीत गाने लगी। मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त विचलित हो गया। वह आसन से उठे और इधर-उधर देखने लगे। माया से उनका मन चंचल हो उठा था। फिर उन्होंने जैसे ही सुनीथा को देखा, तो वह मोह के वशीभूत होकर उसके पास गए। अंग ने पूछा, 'सुंदरी! तुम कौन हो? यहां किस काम से आई हो?' सुनीथा कुछ न बोली। उसके स्थान पर रंभा ने कहा, 'महर्षे! यह मृत्यु की सौभाग्यवती कन्या सुनीथा है। यह अपने लिए धर्मात्मा और जितेंद्रिय पति की खोज में है।' यह सुनकर अंग ने रंभा से कहा, 'भगवान विष्णु ने मुझे पुत्र का वरदान दिया है। इसलिए मैं भी किसी योग्य कन्या की तलाश में हूं। मैं सुनीथा को पत्नी बनाने के लिए तैयार हूं।'

अंग और सुनीथा का विवाह हो गया। कुछ समय बाद सुनीथा ने एक सर्वलक्षण-संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम वेन रखा गया। वह महातेजस्वी बालक शीघ्र ही वेद-शास्त्र आदि का अध्ययन कर समस्त विद्याओं का ज्ञाता हो गया। यह देखकर उसके माता-पिता अत्यंत प्रसन्न थे। परंतु गंधर्व कुमार सुशंख का शाप अभी फलीभूत होना शेष था। एक दिन वेन के दरबार में एक छद्मवेशधारी पुरुष आया, जिसकी बातों से वेन मोहित हो गया। उसने समस्त वैदिक धर्म तथा सत्य-धर्म क्रियाओं को त्याग दिया। पापात्मा वेन के शासन में ब्राह्मण लोग न दान कर पाते थे, न स्वाध्याय। धर्म का लोप हो गया और सब ओर पाप छा गया। इस तरह वेन, भगवान विष्णु के वरदान और सुशंख के शाप का मिश्रण सिद्ध हुआ। आखिर वेन के पापों से दुखी ऋषियों ने वेन का अंत कर दिया। उसके शरीर के मंथन से पृथु का जन्म हुआ, जिनके नाम पर धरती को 'पृथ्वी' नाम मिला।

अर्थोपार्जनदक्षश्च
क्षान्तिशीलः सदा भवेत्।
न तत्र परकार्याणि
विद्वानपि विशेषयेत्॥

व्यक्ति को अर्थोपार्जन में दक्ष और सदैव क्षमाशील होना चाहिए। उसे कभी भी दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही बड़ा विद्वान ही क्यों न हो।

चाणक्यनीति : 2110

प्रस्तुति : शास्त्री कोसलेंद्रदास

जब कोई बात बिगड़ जाए

क्रिस्टीना कैरन

द न्यूयॉर्क टाइम्स

कोई कुछ गलत कह दे, या जब कोई बात बिगड़ जाए, तो कुछ क्षण रुकें, गहरी सांस लें और फिर देखें जादू।

कल्पना कीजिए कि एक चमकदार गुब्बारे में सूई चुभो दी जाए, तो क्या होगा? इससे वह या तो फट पड़ेगा या फिर हवा निकल जाएगी। ऐसा इन्सानों के साथ भी होता है। एक सोशल मीडिया क्रिएटर ने बताया कि अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (एडीएचडी) यानी ध्यान आकर्षित न कर पाने से उत्पन्न विकार से पीड़ित व्यक्ति के लिए अस्वीकृति ऐसी हो सकती है, मानो भावनाओं का विस्फोट हो गया। इस क्लिप को लाखों लाइक्स मिले हैं। यह रिजेक्शन सेंसिटिव डाइस्फोरिया (आरएसडी) यानी अस्वीकृति से उपजी बेचैनी से संबंधित हजारों पोस्टों में से एक है। इन शब्दों का उपयोग चिकित्सकों द्वारा भी बहुत कम किया जाता है, पर ये आजकल खूब वायरल हो रहे हैं।

एडीएचडी से पीड़ित 24 वर्षीय शिक्षिका एरिन राइडर ने बताया कि हाल ही में उनके प्रेमी ने सप्ताह भर काम करने के बाद अपनी योजना स्थगित कर दी। वह कहती हैं कि इससे उन्हें काफी गुस्सा आया कि उसने पहले से बने कार्यक्रम को रद्द क्यों कर दिया। वह कहती हैं कि थोड़ी देर के लिए तो वह पगला-सी गई थीं। हालांकि, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्रतिक्रिया गलत थी। एडीएचडी का उपचार करने वाले मनोवैज्ञानिक डॉ. बिल डॉडसन ने आरएसडी शब्द को लोकप्रिय बनाया है। वह कहते हैं कि यह शब्द उन्होंने नहीं गढ़ा, बल्कि अवसाद पर उपलब्ध पुराने साहित्य से उधार लिया है। उनके अनुसार, अस्वीकृति संवेदनशीलता कथित आलोचना पर तीव्र प्रतिक्रिया देना है। मनोचिकित्सा और व्यवहार न्यूरोसाइंस विशेषज्ञ डॉ. एरिक मेसियस कहते हैं कि आरएसडी दिमागी और व्यक्तित्व संबंधी विकारों से जुड़ा है। इससे पीड़ित व्यक्ति न केवल कथित आलोचना के प्रति संवेदनशील होता है, बल्कि कई मामलों में खुद को कमतर भी समझता है। यदि ऐसे व्यक्ति को चिढ़ाया जाए, मजाक उड़ाया जाए, उसकी बात काट दी जाए, या फिर कुछ अप्रिय बोल दिया जाए, तो उसका मूड तुरंत बदल जाएगा और वह या तो गुस्सा करेगा या उदासी में डूब जाएगा। यहीं से 'डिस्फोरिया' शब्द आता है, जिसका अर्थ है : बेचैन या असंतुष्ट महसूस करने की स्थिति। मनोवैज्ञानिक डॉ. लिंडसे ब्लास कहती हैं कि आलोचना किसी-किसी के लिए बहुत दर्दनाक होती है। डॉ. डॉडसन कहते हैं एडीएचडी पीड़ितों के लिए कोई मान्य दवा नहीं है, उन्हें अवसाद की ही दवा दी जाती है। एक्सपोजर थेरेपी के तहत चिकित्सक धीरे-धीरे रोगी के आत्मविश्वास को जगाते हैं, ताकि आलोचना या अन्य किसी बात से उपजी उदासी या हीन भावना को दूर किया जा सके। उन्हें प्रेरित किया जाता है कि छोटी-छोटी बातों पर क्रोध न करें और जब जिंदगी में कोई बात बिगड़ जाए, तो उसे दिल पर न लें।

©The New York Times 2025

अध्ययन कक्ष

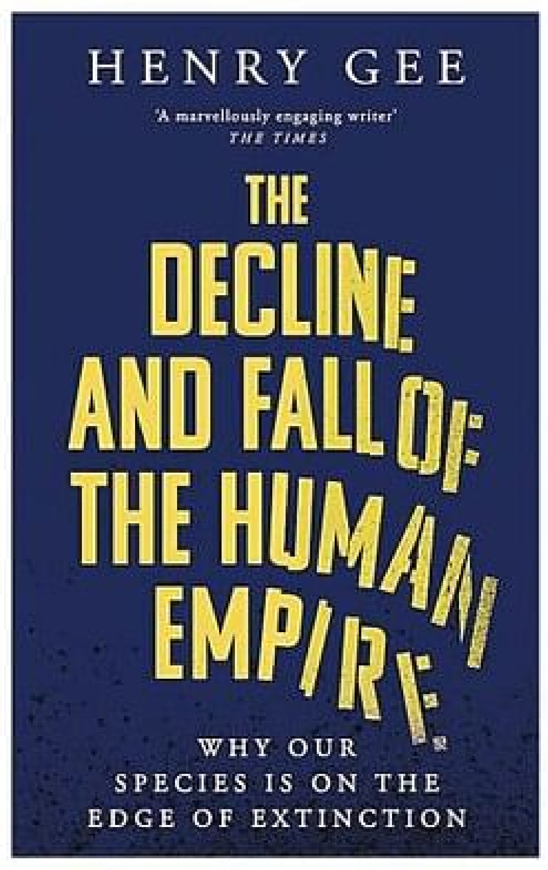

द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ ह्यूमन एंपायर

व्हाई ऑवर स्पेसिज इज ऑन द एज ऑफ एक्सिटंक्शन

लेखक : हेनरी गी

प्रकाशक : पिकोडोर

मूल्य : 1,989 रुपये (हार्डकवर)

क्या 'द टाइम मशीन' ने झूठ बोला था

एचजी वेल्स ने 1895 में *द टाइम मशीन* उपन्यास लिखा, जिसमें एक समय-यात्री करीबन आठ लाख वर्ष बाद की दुनिया में पहुंचता है। हेनरी गी की शीघ्र प्रकाश्य पुस्तक इस तथ्य को झुठलाती हुई सांख्यिकीय आधार पर साबित करती है कि धरती पर अब दस से बारह हजार वर्ष का जीवन ही शेष है।

एचजी वेल्स के 1895 के उपन्यास *द टाइम मशीन* में एक अनाम विक्टोरियन वैज्ञानिक वर्ष 802,701 में यात्रा करता है। आर्थिक और बौद्धिक विकास के सहस्राब्दियों के संचयी लाभों को हासिल करने वाली एक समृद्ध, प्रबुद्ध मानव सभ्यता को खोजने के बजाय वह एक भयावह दृश्य पाता है। विज्ञान लेखक हेनरी गी ने अपनी पुस्तक *द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द ह्यूमन एंपायर* में मानवता के भविष्य की कम भयावह, लेकिन उतनी ही चिंताजनक तस्वीर पेश की है। वेल्स के विपरीत, गी को नहीं लगता कि मानव प्रजाति अगले 8,000-12,000 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रह पाएगी। यह संख्या कोई निराशावादी राय नहीं है।

यह सांख्यिकीय विश्लेषणों पर आधारित है, जो दर्शाती है कि हमारी प्रजाति हमारे तेजी से घटते पर्यावरण के बीच तेजी से क्षय हो रही है। हालांकि यह सब निराशाजनक लग सकता है, लेकिन यह किताब पढ़ने में अजीब तरह से मनोरंजक है, क्योंकि इसमें हमारी प्रजाति की उत्पत्ति और अपरिहार्य गिरावट के बारे में दिलचस्प तथ्य हैं, और यह भी बताया गया है कि हमने अपने ग्रह को कैसे कई अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित किया है। कई बार व्यंग्यात्मक रूप से, गी की किताब हमारे भविष्य पर कार्रवाई के लिए अंतिम चेतावनी लगती है। गी की यह पुस्तक मानवता के पतन पर एक स्थिर नजर डालती है। उनका तर्क है कि यह कुछ ऐसा है, जिसे हम एक प्रजाति के रूप में टाल नहीं सकते, क्योंकि ग्रह के कई पर्यावरणों पर हमारा हानिकारक प्रभाव है, जिनमें से कुछ हमारे भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। वह इस समय-सीमा से परे हमारे अस्तित्व के लिए कुछ उम्मीदें पेश करते हैं, लेकिन यह कठोर व असंभव समाधानों पर निर्भर करेगा। पुस्तक तीन भागों में विभाजित हैः उदय, पतन और पलायन। प्रत्येक भाग में हमारी अनोखी प्रजाति की कहानी को इसके प्रागैतिहासिक आरंभ से लेकर पृथ्वी पर प्रमुख स्तनपायी के रूप में हमारी सफलता तक और अंत में, अत्यधिक सफल होने तक विस्तृत रूप से बताया गया है। हमारी प्रजाति के लिए एक और चिंता का विषय यह है कि पुरुषों में वाई क्रोमोसोम का नुकसान, जो तेजी से घट रहा है, जो एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति है। वैश्विक स्तर पर प्रजनन दर तेजी से घट रही है। यदि हम अपने ग्रह को और अधिक विनाश तथा आसन्न पर्यावरणीय पतन से बचा सकें, तो हम अपनी प्रजाति के लंबे समय तक जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें अभी से कार्य करना होगा। गी के पास हमारी प्रजाति को बचाने के लिए एक शानदार, हालांकि बेहद असंभव समाधान है। वह लिखते हैं कि अगली सदी में, प्रौद्योगिकी की बढ़ती गति के साथ, चंद्रमा या मंगल पर मानव बस्तियों को स्थायी रूप से विकसित करना संभव हो सकता है। हमें सबसे पहले एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जो लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्राओं पर जीवित रहने के लिए भोजन, स्वच्छ हवा और जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करेगा। गी का अनुमान है कि एक दिन अंतरिक्ष में बसावट होगी, लेकिन हम उस लक्ष्य से कम से कम दो से तीन शताब्दी दूर हैं। सुकरात कहते हैं कि अगर हम किसी समस्या के बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस मामले में हम बहुत कुछ कर सकते हैं।

अभियान

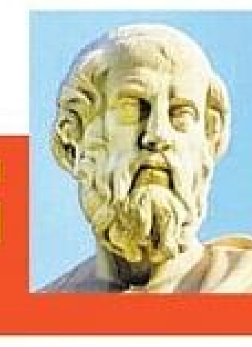

हम उस बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं, जो अंधेरे से डरता है। जीवन की असल त्रासदी तब होती है, जब लोग प्रकाश से डरते हैं। - प्लेटो

amarujala.com
अमर उजाला

Hindi@mithelesh
■ मिथिलेश बारिया

गोल चबूतरा

वो जागेगा रातभर सरहद पर,
जिसकी बातें करते-करते तुम सो गए हो...
सरहद कितनी महंगी है,
कभी उस मां से पूछना, जो दाम चुका
कर बैठी है...
बंदूक है सरहद पर खड़े उस फौजी के हाथ में,
मां-बाप जिसके गांव में, डरे-डरे से रहते हैं...

इतिहास में विमान की एक 'उड़ान'

झरोखा
27 अप्रैल

'एयरबस ए380' दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान है, जिसने 2005 में आज के ही दिन उड़ान भरी थी। यह ऐतिहासिक उड़ान फ्रांस के टूलूज शहर से भरी गई थी।

इस परीक्षण उड़ान में छह चालक दल के सदस्य सवार थे और यह लगभग चार घंटे तक आसमान में रहा। ए380 को लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कुल लंबाई 72.7 मीटर और ऊंचाई 24.1 मीटर है। इसके पंखों का फैलाव 79.8 मीटर है। विमान का पंख क्षेत्र 845 वर्ग मीटर है। यह दो मंजिला विमान इकोनॉमी क्लास में एक बार में लगभग 850 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। हालांकि एयरलाइंस इसे तीन क्लास व्यवस्था में फर्स्ट, बिजनेस और इकोनॉमी क्लास में 500 से 600 यात्रियों के साथ उड़ाती हैं।

विमान की खासियत है कि इसमें चार शक्तिशाली इंजन लगे हैं, जो इसे 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं। इसकी अधिकतम उड़ान रेंज लगभग 15,000 किलोमीटर है, जो इसे बिना रुके लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। इसने पहली व्यावसायिक उड़ान 25 अक्तूबर, 2007 को सिंगापुर से सिडनी के लिए भरी थी। यह सिंगारपुर एयरलाइंस से चलाई गई थी।

■ संतोष पांडे, बागेश्वर

फुरसत के पल और खिलखिलाते स्वर

तस्वीर में महान गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले रिकॉर्डिंग ब्रेक के दौरान किसी बात पर खिलखिला कर हंस रही हैं।

■ नंदिनी, गुरुग्राम

छायानट

नसीरुद्दीन शाह पर भड़के थे बेनेगल

गर्मियों के दिनों की बात है। श्याम बेनेगल आंध्र प्रदेश के एक सुदूर गांव में फिल्म 'निशांत' की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह प्रमुख भूमिका में थे। भीषण गर्मी के बीच जिस लोकेशन पर शूट चल रहा था, वहां पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके चलते पूरी यूनिट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गरम और उमस भरी रातों में सोना एक बड़ी चुनौती थी, खासकर तब, जब दिनभर धूप में शूटिंग के बाद आराम करना बेहद जरूरी होता था। एक रात नसीरुद्दीन शाह को इतनी बेचैनी हुई कि वह नींद न आने की वजह से चुपचाप गांव की सीमा के बाहर टहलने निकल गए। सुबह जब काफी देर तक वह नहीं लौटे तो यूनिट में हलचल मच गई। साथियों को उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी, लेकिन कुछ देर बाद वह थके-हारे लोकेशन पर लौटे और पूरी कहानी बयां की। इस पर श्याम बेनेगल ने मजाकिया अंदाज में नाराजगी जताते हुए कहा कि अगली बार कहानी में यह भी डालेंगे कि नायक नींद न आने पर गांव छोड़कर चला जाता है। इतना सुनते ही पूरी यूनिट हंसने लगी।

■ संदीप त्रिपाठी, सीतापुर

कश्मीर में पर्यटन समेत अन्य गतिविधियां पटरी पर लौटने लगी थीं, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले ने भारतीयों के जख्म को फिर से कुरेदा है। वक्त आ गया है कि भारत आतंकवाद का खात्मा कर समस्या का स्थायी समाधान निकाले।

हमारे जख्म कैसे भरेंगे?

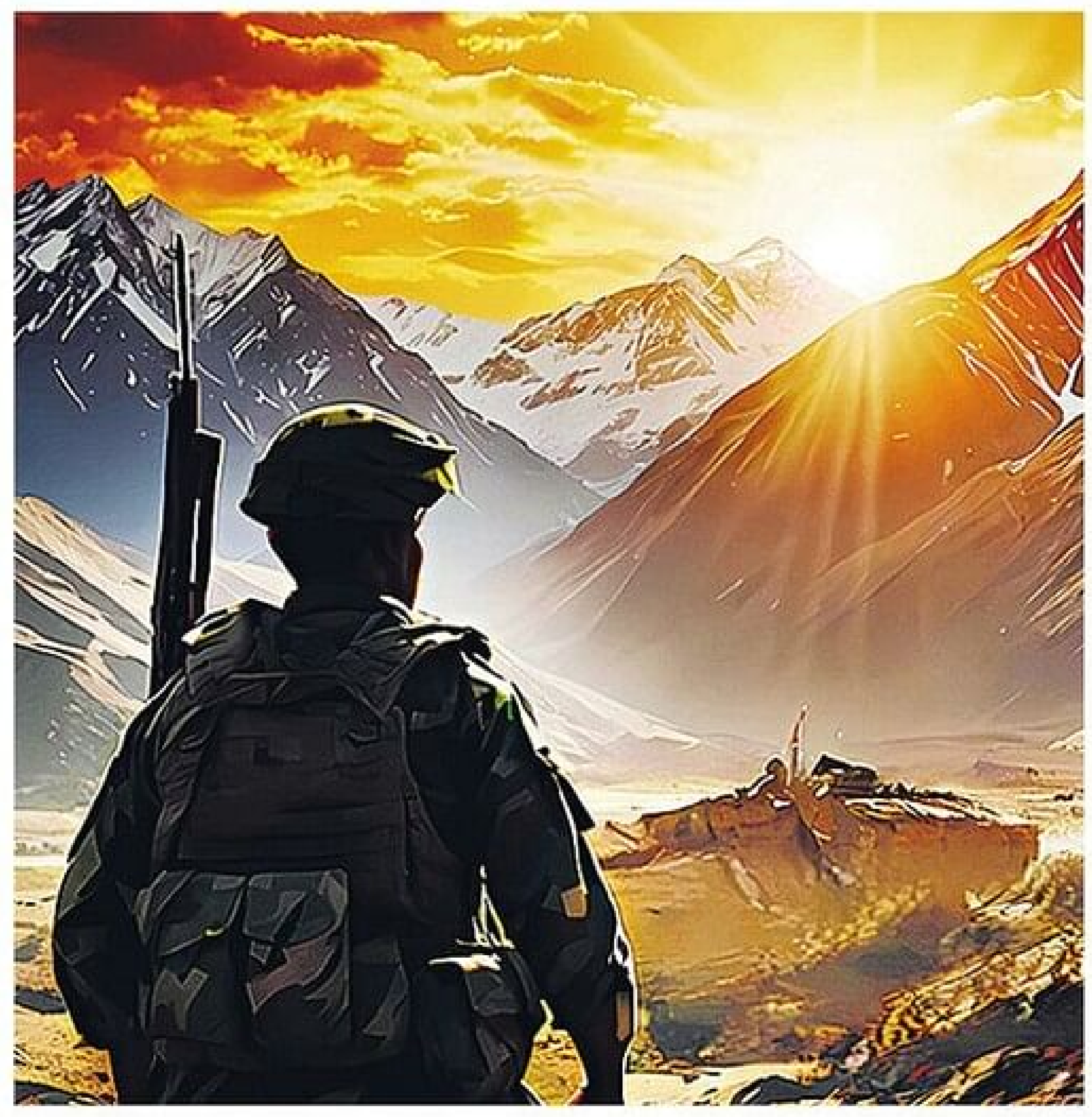

देना होगा मुंहतोड़ जवाब

चिट्ठी 1

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से साफ है कि पाकिस्तान शांति से मानने वालों में नहीं है। इस हमले ने उसके कश्मीर घाटी को फिर से अशांत करने के मंसूबों को उजागर किया है।

हालिया वर्षों में कश्मीर समस्या के लिए भारत की तरफ से जो कोशिशें हुई हैं, वे निश्चित तौर पर पाकिस्तान से देखी नहीं जा रही हैं। यही कारण है कि वह इस तरह की हरकतें कर रहा है। यह आतंकी हमला हर भारतीय नागरिक पर हुआ है। यह देश की संप्रभुता पर हमला है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान परस्त आतंकवाद के मुद्दे पर भारत तह तक पहुंचे और इसे पूरी तरह तहस-नहस कर दे।

अब भारत न केवल कश्मीर घाटी की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करे, बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। पाक परस्त आतंकवाद के स्थायी समाधान के लिए यह जरूरी है। पाकिस्तान हमारी धरती का हमारे खिलाफ आतंक फैलाने के लिए उपयोग करता है। इसलिए पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को खत्म कर भारत को अपनी जमीन भी वापस लेनी होगी। यह सही समय है। इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ें तो उठाए जाएं, लेकिन किसी तरह की कोताही न बरती जाए।

भारत ने कुछ फौरी कदम उठाए हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। आखिर कब तक इस तरह हमारे देशवासियों का खून बहता रहेगा? कब तक हम कश्मीर समस्या से जूझते रहेंगे? दोस्ती की आड़ में दुश्मनी नहीं चल सकती। चाहे पाकिस्तान लाख दुहाई देता रहे, लेकिन सच यही है कि इस घटना के पीछे वही है। भारत सरकार को अब पीछे नहीं हटना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।

■ हरिप्रसाद चौरसिया, देवास

चूक से सीख लेनी होगी

चिट्ठी 2

पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर जो कायराना हमला हुआ, उसने हर किसी को झकझोर दिया है। हंसते-खेलते परिवारों के बिखर जाने की घटना से हर कोई सहमा हुआ है। हम सब जानते हैं कि कश्मीर अब भी आतंक के साए में है। ऐसे में सवाल यह है कि जब एक आम नागरिक इस बात को समझ रहा है तो फिर सरकार के स्तर पर इतनी भारी चूक कैसे हुई? सुरक्षा को लेकर लापरवाही क्यों बरती गई? पर्यटकों के लिहाज से भीड़भाड़ वाले स्थान पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे?

कश्मीर देश की सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील राज्य है। वहां पर सेना, अर्द्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस के हजारों जवान तैनात हैं। अलग स्तर पर खुफिया एजेंसी काम कर रही है। फिर भी इतना बड़ा हमला होने का मतलब है कि कहीं तो चूक हुई है!

भले ही आतंकवाद से पूरा विश्व परेशान हो, लेकिन निपटना सबको अपने तरीके से ही है। भारत को भी आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए खुद ही गंभीर होना पड़ेगा। भारत के मामले में साफ है कि पाकिस्तान की शह पर ही आतंक का पूरा खेल चलता है।

हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है और हम हर कदम पर उनके साथ हैं, लेकिन चूक हुई है तो उसकी जांच करना भी जरूरी है। यह देश की सुरक्षा का मामला है। हमले के बाद सरकार ने सक्रियता दिखाई है, जो जरूरी थी और यह जारी भी रहनी चाहिए।

■ राजेश कुमार चौहान, जालंधर

परीक्षाओं में देरी क्यों?

चिट्ठी 3

भारत में परीक्षाओं की शुचिता लगातार सवालों के घेरे में है। देश में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से कराने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) का गठन किया।

जेईई, नीट, सीयूईटी, नेट समेत अन्य प्रमुख परीक्षाएं इसके जिम्मे हैं। लेकिन देखने में आया है कि बीते कुछ वर्षों से यह समस्या और बढ़ती जा रही है। चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर छात्रों की सुविधाए का, एनटीए अभी तक पूरी तरह असफल साबित हुआ है। हाल में संपन्न जेईई-मेन परीक्षा की फाइनल आंसर-की में 11 बदलाव देखने को मिले। एक सवाल ड्रॉप किया गया, छह सवालों के जवाब बदले गए और चार सवालों में दो-दो विकल्प सही माने गए। एक-दो गलती समझ में आती है, लेकिन जिस परीक्षा में साढ़े नौ लाख छात्र शामिल हो रहे हों और एक-एक नंबर का महत्व हो, वहां पर एनटीए जैसी संस्था ऐसी गलती कैसे कर सकती है। इस परीक्षा के लिए बच्चे और उनके माता-पिता सालों से परिश्रम करते हैं। अपना पैसा और समय खर्च करते हैं और उसके बाद इस तरह की लापरवाही सामने आती है तो पेरशानी होती है।

यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। बीते वर्ष नीट का प्रकरण हम सबके सामने रहा और पूरे साल छात्र तथा अभिभावक इससे जूझते रहे। यूजीसी-नेट की परीक्षा भी पिछले साल एनटीए ने रद की। एनटीए की कार्यप्रणाली में व्यापक स्तर पर सुधार की जरूरत है।

■ प्रो. आरके जैन, बड़वानी

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं

रुड़की से डॉ. सम्राट सुधा, दिल्ली से योगेश कुमार गोयल, गाजियाबाद से ललित शंकर, श्रावस्ती से अनुपम पाठक अनुपम, आजमगढ़ से अवनीश कुमार गुप्ता, मेरठ से डॉ. सुधाकर आशावादी, फिरोजाबाद से शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, इंदौर से अमृतलाल मारू, रायपुर से संजीव ठाकुर, सूरत से कांतिलाल मंडोत।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

चिमनी, सफेद धुआं और ताज

पोप फ्रांसिस के निधन के बाद कैथोलिक ईसाई धर्म के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव होगा। पोप की चयन प्रक्रिया बहुत गोपनीय रहती है।

पोप ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक समूह 'कैथोलिक चर्च' के सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं, जो वेटिकन सिटी में रहते हैं। निवर्तमान पोप की मृत्यु या त्याग-पत्र के बाद नए पोप का चयन होना एक सामान्य बात है, लेकिन चयन की गोपनीय प्रक्रिया इसे खास बनाती है।

नए पोप के चयन के लिए रोम स्थित 'सिस्टिन चैपल' में एक गुप्त बैठक होती है, जिसे 'कॉन्क्लेव' कहा जाता है। इसमें दुनियाभर से वरिष्ठ पादरी पहुंचते हैं। इनको कार्डिनल्स कहा जाता है। वर्तमान में कार्डिनल्स कॉलेज में 222 सदस्य हैं, जिनमें से 120 वोट करने योग्य हैं। केवल 80 वर्ष से कम उम्र के कार्डिनल को ही वोट देने का अधिकार होता है। दो तिहाई मत मिलने पर पोप चुना जाता है।

कॉन्क्लेव की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कार्डिनल को तब तक के लिए बंद कर दिया जाता है, जब तक नया पोप नहीं चुन लिया जाता। सभी कार्डिनल एक विशेष शपथ लेते हैं कि वे चुनाव से जुड़ी कोई जानकारी बाहरी दुनिया के साथ साझा नहीं करेंगे। चुनाव के दौरान कार्डिनल गुप्त मतदान करते हैं। यदि किसी भी उम्मीदवार को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलता तो मतदान दोबारा कराया जाता है। एक दिन में अधिकतम चार बार मतदान हो सकता है- दो बार सुबह और दो बार शाम को।

मतदान के बाद मत पत्रों को केमिकल मिलाकर जला दिया जाता है। यदि पोप का चयन नहीं होता है तो काले धुएं वाला केमिकल डाला जाता है, जबकि चयन हो जाने पर सफेद धुएं वाला केमिकल उपयोग किया जाता है। चिमनी से सफेद धुआं निकलना इस बात का संकेत होता है कि चर्च को नया पोप मिल चुका है। इसके बाद कार्डिनल से पूछा जाता है कि क्या वह पोप बनने के लिए तैयार हैं। यदि वह स्वीकार करते हैं तो अपना एक नया नाम चुनते हैं। उसके बाद बालकनी में आते हैं। मतदान की गोपनीयता अनिश्चितकाल तक जारी रहती है।

■ प्रिया शर्मा, शिमला

दो अप्रिय विकल्पों के बीच खड़ा भारत!

टैरिफ युद्ध में भारत को दो देशों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर टैरिफ की वजह से अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष खत्म हो गया और चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया तो इससे भारत के लिए स्थिति और खराब हो जाएगी।

पी चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय मंत्री

'स्काइला और चरीबडीस के बीच' जैसा शीर्षक लिखकर मैं एक सुरक्षित खेल खेलना चाहता हूं। अगर मैं 'बिटवीन द डेविल एंड सी' जैसे अंग्रेजी मुहावरे का प्रयोग करूं तो तुरंत सवाल उठेगा कि इसमें समुद्र कौन है और शैतान कौन है? 2 अप्रैल, 2025 से जो टैरिफ युद्ध शुरू हुआ है, उसमें भारत को दो देशों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा चीन। एक को मैं 'स्काइला' मान सकता हूं और दूसरे को 'चरीबडीस'। कहने का मतलब है- दो चट्टानों के बीच में फंसा होना। वर्तमान संदर्भ में देखें तो दोनों ही अप्रिय विकल्प हैं।

समस्या का पहला पक्ष

■ 2024-25 में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत का वस्तु व्यापार था-

	अमेरिका	चीन	विश्व
निर्यात	86.51	14.25	437.42
आयात	45.3	113.45	720.24
अधिशेष/घाटा	+ 41.21	- 99.20	- 282.82

नोट : आंकड़े बिलियन में

इसलिए भारत को दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ काम करते समय दो विपरीत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे व्यापार खाते में अधिशेष है। हम यूएस को जवाहरात और आभूषणों का निर्यात करते हैं। इसके अलावा दवाएं, इंजीनियरिंग और कृषि से जुड़े कुछ सामान। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्ता वाली दवाओं को छोड़कर अन्य ऐसी वस्तुएं हैं, जिनके बिना अमेरिका काम चला सकता है या जिन्हें वह अन्य देशों से आयात कर सकता है, लेकिन भारत से निर्यात किया जाने वाला हर सामान हजारों पुरुषों और महिलाओं के लिए आजीविका का स्रोत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने से व्यापार खाते में अधिशेष को खतरा है। हालांकि अभी इस पर रोक है और फार्मास्यूटिकल्स को अस्थायी रूप से छूट दी गई है, लेकिन टैरिफ की तलवार भारत के सिर पर अभी भी लटकी हुई है। अगर टैरिफ लागू कर दिया जाता है तो इससे सबसे अधिक निर्यातक, नौकरी, विदेशी आय अर्जित करने वाले और चालू खाताधारकों के प्रभावित होने की संभावना है। भारत के हित में यही है कि वह अमेरिका के साथ बैठकर बातचीत करे और कठोर टैरिफ से बचने की कोशिश करे।

ट्रंप इस बात को जानते हैं कि भारत से आने वाली वस्तुओं पर रोक लगाने से अमेरिका को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वह भारत को आयात की अनुमति देने का कोई न कोई रास्ता खोज तो लेंगे, लेकिन वह इसके लिए कीमत वसूलेंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर जोर देंगे कि भारत अमेरिका से अधिक खरीदारी करे, ताकि व्यापार को 'संतुलित' रखा जा सके। जहां तक मेरा अनुभव है, ट्रंप भारत को अधिक महंगे सैन्य सामान और विमान खरीदने को कहेंगे। भारत अपनी अन्य जरूरतों के सामान, जैसे कि लोहा और इस्पात, कार्बनिक रसायन, प्लास्टिक, खनिज, तेल तथा पेट्रोलियम उत्पाद दुनिया के दूसरे देशों से आयात कर सकता है, लेकिन अमेरिकी सामान चुनने में वह समझदारी दिखा सकता है। यहां बड़ा सवाल यह है कि भारत उच्च लागत वाले अमेरिकी सैन्य उपकरणों और विमानों की खरीद पर कितना अधिक खर्च कर सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी विरोध के अब तक अमेरिकी उकसावे और ज्यादतियों को सहा है, हो सकता है कि वह ट्रंप के आगे झुक जाएं।

समस्या का दूसरा पक्ष

चीन के साथ भारत की समस्या इससे उल्टी है। भारत के व्यापारिक खाते में घाटा बहुत बड़ा और बढ़ता जा रहा है। यह 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहुत बड़ा घाटा है। भारतीय उद्योग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों, जैसे कि मशीनरी, ऑर्गेनिक रसायन, लोहा और इस्पात के लिए चीन पर निर्भर हैं, क्योंकि वे सस्ते होते हैं। भारत के पास सामान को उसी कीमत और समय पर डिलीवरी करने जैसे विकल्पों की कमी है। भारत जब तक अपने घरेलू विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार और उसे उन्नत नहीं करता, तब तक ऐसा करना संभव नहीं है। जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी जब तक 13-14 प्रतिशत पर अटकी रहेगी, उसे चीन पर निर्भर रहना पड़ेगा।

भारत चीन को मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुएं, खनिज और पेट्रोलियम आधारित ईंधन, समुद्री खाद्य पदार्थ, सूती धागा और कुछ कृषि उत्पाद निर्यात करता है। जाहिर है, कुछ मूल्य वर्धित सामान हैं, जिन्हें भारत चीन को निर्यात कर सकता है, जबकि चीन घरेलू स्तर पर उत्पादन नहीं कर सकता या अन्य देशों से आयात नहीं कर सकता।

चीन ने भारत से और भी वस्तुओं को आयात करने की इच्छा जताई है, लेकिन भारत चीन के इस ऑफर का लाभ उठा पाएगा या नहीं, यह बहस का विषय है। अमेरिका के साथ अधिशेष ने एक हद तक चीन के साथ घाटे की भरपाई की है। अगर ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष खत्म हो गया और चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया तो इससे भारत के लिए स्थिति और खराब हो जाएगी।

क्वाड की बात

क्वाड, जिसका पूरा नाम क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, चार देशों का समूह है- भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताओं से अलग हैं। अमेरिका यह चाहता है कि क्वाड चीन की आक्रामक नीतियों का विरोध करे। वहीं भारत क्वाड को समुद्री सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, उभरती हुई तकनीकों तक ही सीमित रखना चाहता है और वह क्वाड को चीन विरोधी समूह में बदलने के प्रति सचेत भी है। चीन ने विश्व को इस बात की चेतावनी दी है कि अगर कोई देश अमेरिका के साथ ऐसा समझौता करता है, जो चीन के हितों के खिलाफ है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत को पूंजी एवं प्रौद्योगिकी के प्रमुख स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्यवर्ती एवं पूंजीगत वस्तुओं के प्रमुख स्रोत चीन, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा चीन एक शत्रुता रखने वाला पड़ोसी है, जो भारत के क्षेत्रों पर कब्जा जमाता जा रहा है। क्वाड में भारत की भागीदारी अब तक नपी-तुली और व्यावहारिक रही है, लेकिन कुछ दक्षिणपंथी प्रभावशाली लोगों द्वारा भारत और चीन को विवाद में धकेलने का खतरा है।

एक अन्य रोचक तथ्य

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल 20 जनवरी, 2029 तक है, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब तक चाहें, पद पर रह सकते हैं। ट्रंप जहां ढीठ और बेबाक हैं, वहीं शी बेहद चालाक हैं। ट्रंप के इस कदम ने प्रधानमंत्री मोदी की संरक्षणवादी नीतियों को उजागर कर दिया है। मोदी को कदम पीछे हटाने होंगे। उन्हें अधिक परामर्शी होने और विपक्षी दलों को दुश्मन मानने से भी बचना होगा।

Licensed by The Indian Express Limited

यादों के पिटारे में एक चबूतरा

वसीम अहमद
नगरामी

खुला आकाश

जब अमरूद और शहतूत के साथ नीम पर भी फूल आते हैं तो ऐसा लगता है, जैसे ये फलदार वृक्ष तान से तान मिला कर प्रफुल्लित हो रहे हों और तरह-तरह के जीव-जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा कर रहे हों।

एक ऐसा चबूतरा, जहां झींगुरों की रुनझुन, गिरगिटों की किटकिट, कौवों की कांव-कांव, गिलहरियों की टिल-टिल और अलग-अलग पक्षियों की चहचहाहट के साथ बच्चों की फुसफुसाहट वाली आवाजें सुनने को मिलती रहती हैं। एक साथ इतना सब कुछ एक ही स्थान पर एक सुखद संयोग ही तो है। वास्तव में, नगराम के दिल में आबाद है एक वार्ड, उस वार्ड के दिल में आबाद है एक घर और उस घर के जहन में आबाद है अपनी तरह का इकलौता चबूतरा।

जी हां! नगराम बाजार नामक यह वार्ड कमोबेश कस्बे के बीचोबीच दिल की मानिंद स्थित है। इसका चबूतरा किसी बाग से कम नहीं है, जिसमें लगे फलदार पेड़ उधर से गुजरने वालों के आकर्षण का केंद्र हैं।

इस घर का यह चबूतरा, चबूतरा कम बगिया ज्यादा लगता है। जिन पेड़ों ने इस चबूतरे पर कब्जा कर रखा है, उनमें नीम, शहतूत, शरीफा और अमरूद प्रमुख हैं। इन पेड़ों के होते हुए क्या मजाल कि लू के थपेड़े इस घर को छू भी सकें। जो भी चिलचिलाती धूप में इस गली से गुजरता है, उसे कुछ पलों के लिए ही सही, पेड़ों की छाया रोक ही लेती है। यहां रुकने पर चिलचिलाती धूप से तो राहत मिलती ही है, चबूतरे के फल भी सुलभ होते हैं। स्कूल से आते बच्चे ढेर सारे शहतूत इकट्ठा करते हैं। घर का स्वामी बचपन से ही पेड़-पौधों का प्रेमी रहा है। पहले यह कुटिया कच्ची मिट्टी की थी। कुछ दिन बाद जब पक्के घर में तब्दील होने लगी तो सबकी राय के विपरीत गृह स्वामी ने घर के चबूतरे को पक्का बनवाने से मना कर दिया। उसने अपने घर के चबूतरे को कच्चा ही रखा। उसके बाद उस पर फलदार पेड़-पौधे लगाए। मजे की बात तो यह है कि इन पेड़ों के आधे से ज्यादा फल, फूल और पत्तियों पर हमेशा पक्षी, गिलहरी, तितली, मधुमक्खी और तरह-तरह के कीट-पतंगों का कब्जा रहता है। यह चबूतरा इन सबका स्वच्छंद बसेरा है। गृह स्वामी ने भी मान लिया है कि पेड़-पौधों पर पहला अधिकार इन्हीं का है। ये चाहें तो सारे फल-फूल खा डालें या डाल पर तोड़-फोड़ करें। इन्हीं पेड़ों के बहाने चबूतरा सुखद प्राकृतिक शोरगुल से आह्लादित रहता है। चबूतरे पर बुलबुल नित्य जोड़े संग आकर धमा-चौकड़ी करती हैं। एक पत्तों की आड़ में छिप जाए तो दूसरा उसे आवाज देकर ढूंढ लेता है। चबूतरे के पेड़ों की छाया ही मनोहारी और तन को सुख पहुंचाने वाली नहीं लगती, बल्कि सुखद तो यह भी है कि इस चबूतरे के फलदार वृक्ष भी उन्नत किस्म के हैं, जिनमें वर्ष में दो बार फल आते हैं। कमोबेश, हर मौसम में चबूतरा गुलजार रहता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में काफी आक्रोश है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आतंकी हमले को अंजाम देने वाले व उसे प्रायोजित करने वाले को कड़ा सबक सिखाया जाय। सरकार ने इस दिशा में एक्शन शुरू कर दिया है। जम्मू-कश्मीर में जहां आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं सरकार पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रतीकात्मक व क्रियात्मक एक्शन ले रही है। सिंधु जल संधि के निलंबन से लेकर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, उच्चायोग में कर्मियों की कटौती की गई है, अटारी व वाघा सीमा से ट्रेड बंद किए गए हैं, हालांकि ये पहले से ही बंद जैसे हैं। पीएम नरेन्द्र मोदी ने हमलावर आतंकियों व इसके साजिशकर्ताओं को कल्पना से अधिक कड़ी सजा देने की बात कही है। आज इसकी जरूरत भी है। द रेजिसटेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, टीआरएफ पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट लश्करे तैयबा की ही शाखा है, ऐसे में इस आतंकी हमले में भी पाकिस्तान के तार जुड़ रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में पाक फौज व आईएसआई के कई आतंकी प्रशिक्षण ठिकाने हैं। पीछे सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक भी इसी क्षेत्र के आतंकी ठिकानों पर हुए थे। आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारत का पीओके पर कब्जा जरूरी है। टेरर के खिलाफ एक्शन पर केंद्रित आजकल का यह अंक...

पीओके पर कब्जे से टूटेगी आतंक की कमर

कूटनीति

प्रभात कुमार राय
विदेश मामलों के जानकार

पहलगाम नृशंस हत्याकांड के पश्चात भारत सरकार द्वारा जो तत्कालिक निर्णय लिए गए हैं, उनके संदर्भ में यक्ष प्रश्न है कि क्या वर्ष 1960 में पाकिस्तान के साथ अंजाम दी गई, सिंधु जल संधि को स्थगित कर देने से पाकिस्तान द्वारा परवरिश किए गए जिहादी आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकती है? क्या बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर को सील कर देने से भारत और पाकिस्तान के मध्य विद्यमान 3323 किलोमीटर लंबी सरहद पार करके लगातार दाखिल हो रहे जिहादी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से रोका जा सकता है? कश्मीर की सरजमीं पर विगत 37 वर्षों से निरंतर जारी जिहादी आतंकवाद का निराकरण करने का क्या निर्णायक उपाय है?

पाकिस्तान द्वारा प्रेरित और परिपोषित जिहादी आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में अंजाम दिया गया नृशंस हत्याकांड कश्मीर में जिहादी आतंकवाद का ज्वलंत प्रश्न वस्तुतः एक बार फिर से राष्ट्रीय पटल पर आ गया है। इस नृशंस हत्याकांड के पश्चात भारत सरकार द्वारा जो तत्कालिक निर्णय लिए गए हैं, उनके संदर्भ में यक्ष प्रश्न है कि क्या वर्ष 1960 में पाकिस्तान के साथ अंजाम दी गई, सिंधु जल संधि को स्थगित कर देने से पाकिस्तान द्वारा परवरिश किए गए जिहादी आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकती है? क्या बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर को सील कर देने से भारत और पाकिस्तान के मध्य विद्यमान 3323 किलोमीटर लंबी सरहद पार करके लगातार दाखिल हो रहे जिहादी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से रोका जा सकता है? आखिरकार कश्मीर की सरजमीं पर विगत 37 वर्षों से निरंतर जारी जिहादी आतंकवाद का निराकरण करने का क्या निर्णायक उपाय है?

कश्मीर के ज्वलंत प्रश्न पर भारत और पाक के मध्य चार भीषण युद्ध लड़े गए, जिनमें पाक फौज पराजित हुईं, किंतु कश्मीर विवाद यथास्थान खड़ा है। आक्रामक युद्धों में शिकस्त खाने के पश्चात पाक हुक्मरानों ने कश्मीर पर आधिपत्य स्थापित करने की खातिर जिहादी दहशतगर्दों के द्वारा प्राक्सी वार संचालित करने की रणनीति अख्तियार की। विगत 36 वर्षों से निरंतर जारी प्राक्सी वार द्वारा प्रदत्त जख्मों को भारत निरंतर झेलकर अपने तकरीबन 45 हजार सैनिकों और अफसरों का बलिदान दे चुका है। यूं तो कश्मीर की सरजमीं पर तकरीबन एक लाख से अधिक इंसान अपनी जान गवां चुके हैं। आखिरकार क्या निदान है कश्मीर विवाद का और पाकिस्तान द्वारा प्रेषित परिपोषित जिहादी आतंकवाद का?

प्रॉक्सी वार कर रहा पाकिस्तान

भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के तत्पश्चात ही पाक हुकूमत द्वारा कश्मीर को सैन्य शक्ति द्वारा हथियाने की बाकायदा संगीन कोशिश अंजाम दी गई। जबकि पश्तुन कबाईली हमले का नकाब धारण करके मेजर जनरल अकबर अली खान के नेतृत्व में पाक फौज द्वारा ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत रियासत कश्मीर पर 22 अक्टूबर 1947 को सैन्य धावा बोला गया। जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह की छोटी सी सेना ताकतवर पाक फौज के आक्रमण का मुकाबला करने में नाकाम सिद्ध हुई। अंततः महाराजा हरि सिंह ने तत्काल प्रभाव से 26 अक्टूबर 1947 को संपूर्ण जम्मू कश्मीर रियासत का भारत के साथ संविलयन करने के लिए बाकायदा विलयपत्र पर दस्तखत कर दिए। भारतीय फौज आक्रमणकारी पाकिस्तानी फौज़ को जबरदस्त शिकस्त देते हुए निरंतर गति से आगे बढ़ रही थी और अपनी विजय पताका फहराती हुई उरी इलाके तक पहुंच गई थी, जहां से पाक अधिकृत कश्मीर का मुजफ्फराबाद इलाका कुछ ही घंटे की दूरी पर स्थित था। विजय पताका लहराती हुई भारतीय सेना को यकायक युद्ध विराम करने का आदेश भारत की केंद्रीय हुकूमत द्वारा दिया गया। भारत की तत्कालीन अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया। पाकिस्तान की हठधर्मिता के कारण जम्मू-कश्मीर में कभी संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जनमत संग्रह नहीं आयोजित किया जा सका। 1988 से पाक हुकूमत ने कश्मीर पर बलपूर्वक आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रॉक्सी वार का संचालन प्रारंभ किया।

आर्टिकल 370 को निरस्त किया

वर्ष 2019 में भारत सरकार में जम्मू कश्मीर प्रांत के लिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आर्टिकल 370 को निरस्त किया। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा यह दावा पेश किया गया कि आर्टिकल 370 के निरस्त हो जाने से कश्मीर में जिहादी आतंकवाद का स्वतः सफाया हो जाएगा। मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी अंजाम दी गई और दावा किया गया कि भारत में सक्रिय आतंकवादी गिरोहों की कमर टूट जाएगी। नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर तो कदाचित नहीं टूट सकी, छोटे व्यापारियों की कमर जरूर टूट गई। कश्मीर में आतंकवाद निरंतर सक्रिय बना रहा, किंतु उसकी घातक क्षमता में किंचित मात्र कमी जरूर आई।

मंगलवार 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अत्यंत बर्बर और नृशंस वारदात अंजाम दी गई, इसे विगत 10 वर्षों में सबसे विकट और घातक आतंकवादी हमला करार दिया जा रहा है। इस वारदात के बाद भारत सरकार की कश्मीर नीति पर अनेक तल्ख़ प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। वर्ष 2014 में सत्तासीन होते ही नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में जिहादी आतंकवाद का सफाया करने का जबरदस्त वादा पेश किया गया था। भारत की केंद्रीय हुकूमत ने ऐलान किया था कि आर्टिकल 370 के समापन के बाद भारत के सभी प्रांतों के लोग जम्मू-कश्मीर में अब जमीन खरीद सकते हैं, अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं, अपने घरों का निर्माण कर सकते हैं।

नागरिकों को कड़ी सुरक्षा का दावा

भारत सरकार की कश्मीर नीति का सबसे आवश्यक ऐलान रहा है कि कश्मीर घाटी में पर्यटन को बढ़ावा प्रदान करना है और साथ ही भारतीय नागरिकों को कड़ी सुरक्षा प्रदान करनी है। यकीनन कश्मीर घाटी में पर्यटकों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होने का दीदार हुआ। विगत वर्ष 2024 में तकरीबन 35 लाख पर्यटक कश्मीर घाटी में पधारे। कश्मीर की सरजमीं पर बॉर्डर टूरिज्म का भी आगाज़ किया गया। भारतीय हुकूमत की तरफ से कश्मीर में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त तामीरें अंजाम दी गईं। अनेक शानदार बड़े टनल निर्मित किए गए। जम्मू कश्मीर के अत्यंत दुर्गम इलाकों को आपस में संबद्ध करने का अत्यंत दुरूह काम अंजाम दिया गया। इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया जोकि सोनमर्ग को गगनगिरी से संबद्ध करता है। जम्मू-कश्मीर में ऊंची तालीम प्रदान करने के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया गया। भारतीय हुकूमत की तरफ से यह पैगाम दिया गया कि कश्मीर में अब खौफ ओ दहशत का दौर खत्म हो गया है। भारतीय हुकूमत निरंतर दावा पेश करती रही कि कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं और जिहादी दहशतगर्दी पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। भारत को एकजुट रखने के लिए केंद्रीय हुकूमत में शासन करने वाली पार्टी को अपनी ध्रुवीकरण और विभाजनकारी नीतियों का पूर्णतया परित्याग भी करना होगा। जिहादी आतंकवादी तो मजहब को आधार बनाकर मारने से पहले नाम पूछेंगे ही, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही मजहब के आधार पर हुआ है। यक्ष प्रश्न यह है कि हम भारतीय क्या कर रहे हैं? पहलगाम क्षेत्र से जहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी घटना अंजाम दी गई, भारतीय सेना की सुरक्षा हटा ली गई थी और तकरीबन डेढ़ वर्ष पूर्व जम्मू-कश्मीर पुलिस को इस क्षेत्र की समस्त सुरक्षा सौंप दी गई थी। एक ज्वलंत तथ्य पोनी घोड़ा चलाने वाला एक शख्स जो कि मजहब से मुसलमान था, उसने एक आतंकवादी से राइफल छीन लेने के प्रयास में अपनी जान दे दी। पहलगाम में तकरीबन दो हजार पर्यटकों की भीड़ को सुरक्षा देने वाला एक भी पुलिसकर्मी विद्यमान नहीं था। पाकिस्तान के दहशतगर्द जिहादी शर्मनाक और नृशंस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मौका ए वारदात से बिना किसी मुकाबले के फरार हो गए।

आतंकवादी हमले का मिला था इनपुट

इंटेलिजेंस के रॉबिनहुड कहे जाने वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल कितने नाकाम सिद्ध हुए। पुलवामा की तरह पहलगाम में इंटेलिजेंस का इनपुट था कि आतंकवादी हमला अंजाम दिया जा सकता है, किंतु केंद्रीय हुकूमत ने इस पर कोई तवज्जो प्रदान नहीं की। आखिरकार वही हुआ जो कि नहीं होना था। वर्ष 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में पहली दफा कश्मीर घाटी का दौरा किया। नरेंद्र मोदी का जम्मू-कश्मीर दौरा लोकसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले संपन्न हुआ था। श्रीनगर की एक बड़ी आम सभा में जोरदार तकरीर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरमाया था कि कश्मीरी आजादी की सांस ले रहे हैं उन्होंने आगे फरमाया कि आर्टिकल 370 के निरस्त हो जाने के बाद कश्मीर की प्रगति और समृद्धि नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रही है। प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर में आगे कहा कि वर्षों तक कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने आर्टिकल 370 के विषय में जम्मू-कश्मीर और राष्ट्र के लोगों को भरमाया और बरगलाया। भारतीय हुकूमत के प्रधानमंत्री के तमाम दावों के बावजूद कश्मीर की वस्तु स्थिति के वास्तविक जानकार निरंतर कहते रहे हैं कि कश्मीर में जिहादी आतंकवाद पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका और यहां-वहां जम्मू-कश्मीर में अनेक स्थानों पर आतंकवादी हिंसा निरंतर जारी रही है। भारतीय सैनिक और कश्मीरी नागरिक आतंकवादियों द्वारा निरंतर हलाक किए जाते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद सुरक्षा प्रबंधन की संपूर्ण शक्तियां केंद्रीय हुकूमत के हाथों में निहित रही हैं। कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ देने का केंद्रीय गृहमंत्री का दावा एकदम खोखला सिद्ध हुआ। कश्मीर घाटी की कठोर सच्चाई है कि आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद कश्मीर घाटी के आवाम पहले की ही तरह आतंकवाद की दहशत से पूर्णतया मुक्त नहीं हुए हैं। वर्ष 2019 में ही पुलवामा में आतंकवादी आक्रमण में सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए। केंद्रीय हुकूमत ने कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया, जोकि पहले से नहीं किया जा रहा हो।

संसद के प्रस्ताव को जामा पहनाना होगा

भारत को आतंकवाद के प्रतिरोध को अंजाम देने में तभी कामयाबी मिलेगी,जब भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कथित एलओसी अर्थात लाइन ऑफ़ कंट्रोल को रौंद कर पाक अधिकृत कश्मीर में पाक आईएसआई द्वारा स्थापित किए गए आतंकवादी सैन्य शिविरों पर निरंतर आक्रमण अंजाम दिए जाएं। वर्ष 1993 में भारतीय संसद एक मत से यह प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि संपूर्ण कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वक्त आ गया है कि संसद के प्रस्ताव को भारतीय हुकूमत द्वारा अमली जामा पहनाया जाए और अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए एक बड़ी सैनिक कार्यवाही अंजाम दी जाए। अन्यथा कश्मीर में आतंकवाद का सफाया नामुमकिन रहेगा। कश्मीर पर संपूर्ण आधिपत्य स्थापित करने के लिए भारत को कूटनीति के साथ सैन्यनीति से एक निर्णायक जंग पाकिस्तान से लड़नी ही होगी।

भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई ही शेष

पहलगाम

अवधेश कुमार
वरिष्ठ स्तंभकार

पहलगाम हमले के बाद संपूर्ण देश का सामूहिक मानस वैसी कार्रवाई, प्रतिरोध और प्रतिशोध का इच्छुक है जिससे भारत को दोबारा ऐसी भयानक घटना का सामना न करना पड़े। यह स्वाभाविक है। एक समय जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं आम थी और तब भी लोगों के अंदर क्रोध पैदा होता था लेकिन आम मानस यह था कि इसे रोकना अभी संभव नहीं। 5 अगस्त, 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के बाद माहौल बदला, आतंकवादी घटनाओं में व्यापक कमी आई है। जम्मू के साथ-साथ कश्मीर घाटी भी धीरे-धीरे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक,शैक्षणिक गतिविधियों में देश के सामान्य राज्य की तरह काफी हद तक पटरी पर लौट गई है। ऐसे माहौल में एक साथ 26 हिंदुओं तथा एक गैर मुस्लिम की हत्या के बाद उबाल स्वाभाविक है।

आतंकवाद के नाश का संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भी आंतरिक और सीमा पार आतंकवाद के समूल नाश का सक्रिय संकल्प दिखाया है। मोदी सरकार ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक तथा 2018 में पुलवामा हमले के बाद हवाई बमबारी जैसी भारत की दृष्टि से अकल्पनीय मानी जाने वाली कार्रवाई करके देश का विश्वास प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी की आमसभा में केवल आतंकवादी नहीं उनको प्रायोजित करने वाली शक्तियों के विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई की घोषणा की जिसकी कल्पना नहीं की गई होगी। उनका विश्व के लिए संदेश था कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत कमर कस चुका है और कार्रवाई करेगा। कोई देश सार्वजनिक संकल्प दिखाते हुए समानांतर कदम उठाता है और उसकी पृष्ठभूमि आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की हो चुकी है तो विश्व समुदाय को भी सोच और व्यवहार को उसके अनुरूप बदलना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ एक देश नहीं खड़ा है। वे मुस्लिम देश, जो सामान्यतः जम्मू कश्मीर पर इस्लामिक सम्मेलन संगठन या ओआईसी में उसका साथ देते थे, हिम्मत नहीं दिखा रहे। अमेरिकी विदेश विभाग की ब्रीफिंग में एक पाकिस्तानी पत्रकार के प्रश्न की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हिकारत के भाव से उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस पर भारत के साथ हैं। सच है कि काश पटेल के नेतृत्व में अमेरिका की एफबीआई तथा तुलसी गवार्ड के निर्देशन में नेशनल इंटेलिजेंस आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में भारत के साथ खड़ा है। यूरोपीय देशों ने स्पष्ट रूप से भारत का समर्थन किया है। पाकिस्तान ने यद्यपि इस्लामाबाद में 26 देशों के राजनयिकों को बुलाकर अपनी दृष्टि से ब्रीफिंग की किंतु कोई उससे प्रभावित है, ऐसा लगता नहीं।

सिंधु जल संधि स्थगित

प्रश्न है कि भारत क्या कर सकता है, क्या करेगा और कैसी संभावनाएं हैं? घटना के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर से लौटने के बाद मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानियों को दिये हर तरह का वीजा रद करने, उन्हें देश छोड़ने, पाकिस्तानी

उच्चायोग से रक्षा और सैनिक विभाग के अपने समकक्षों को इस्लामाबाद से बुलाने तथा संख्या कम करने का अदम उठाया। इसके साथ सिंधु जल संधि स्थगित करने का अभूतपूर्व कदम उठाया। पाकिस्तान ने इसकी प्रतिक्रिया में सीनेट में प्रस्ताव पारित किया तथा आतंकवादी घटना से स्वयं को अलग करते हुए भारत पर ही बदनाम करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा वक्तव्य है कि सिंधु जल समझौते को रद करना युद्ध जैसा कदम है। उसने 1972 के शिमला समझौते को समाप्त करने की धमकी दी। पाकिस्तान की दुर्दशा देखिए कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक साक्षात्कार में आतंकी संगठनों के वित्त पोषण, प्रशिक्षण और समर्थन के इतिहास संबंधी प्रश्न पर स्वीकार किया कि हम अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों के लिए ऐसा करते रहे हैं और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम अगर सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान युद्ध या 9/11 में साथ नहीं होते तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड साफ रहता। तो इतना उन्होंने स्वीकार किया। यह भी वास्तविक सच को इस मायने में झूठलाना है क्योंकि स्थिति का लाभ उठाते हुए जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पाकिस्तान ने अपनी ओर से प्रायोजित किया और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जो एक हद तक अभी भी कायम है। विश्व के प्रमुख देशों की सूचना में ये सारी बातें हैं। इसलिए भारत ने जब 2018 में हवाई बमबारी की तो एक भी देश ने उसका विरोध नहीं किया। उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के और व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति थे। निःसंदेह, संपूर्ण देश में पाकिस्तान के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई या युद्ध का माहौल बना हुआ है। इस दृष्टि से देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई बमबारी की जा चुकी तथा इसके प्रभाव भी पड़े। स्वाभाविक ही इससे बड़ी कार्रवाई की स्थिति सामने है। तो आगे क्या? जम्मू-कश्मीर के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर कार्रवाई की आवश्यकता थी, जो हो रही है। पहलगाम के बाद उसको पूर्णता तक ले जाना अपरिहार्य हो गया है। भारत ने आंतरिक रूप से पहलगाम हमले के एक आतंकवादी अनंतनाग के बरा स्थित आदिल ठोकर उर्फ आदिल कुड़ी के घर को ध्वस्त किया तथा दूसरे आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के आसिफ शेख का मकान तलाशी के दौरान स्वयं ध्वस्त हो गया।

भारत अब बदल चुका

यह आतंकवादियों को सीधा संदेश है कि भारत बदल चुका है। सच यही है कि जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में न केवल भारत बदला है बल्कि जम्मू कश्मीर तथा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी बदला हुआ है। यह पहली बार है जब आतंकवादी घटना के विरुद्ध कम या ज्यादा संख्या में संपूर्ण जम्मू कश्मीर से लोग सड़कों पर आए हैं, कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि यह सब गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे के बाद ही आरंभ हुआ। अमित शाह के साथ बैठक में मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला भी उपस्थित थे और वहां कुछ बातें हुई होंगी। उसके बाद नेशनल कांफ्रेंस ने पहली बार विरोध प्रदर्शन किया और महबूबा मुफ्ती जैसी पाकिस्तान के प्रति नरम नीति अपनाने वाली नेत्री को भी सड़क पर उतरना पड़ा। कश्मीर में जहां आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा कार्रवाई के विरुद्ध नारे लगाते थे, पत्थरबाजी होती थी और किसी तरह आतंकवादियों के निकल भागने का रास्ता तैयार किया जाता था, उसके विपरीत यह दृश्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बदलाव का संदेश है। थोड़ी गहराई और व्यापकता से विचार करें तो निष्कर्ष आएगा कि सीमा पर सैन्य कार्रवाई को छोड़कर किसी देश के विरुद्ध जितने कदम उठाए जा सकते थे, लगभग भारत ने एक बारगी उठा लिया है। इसका अर्थ है कि भारत समग्रता में दीर्घकालिक समाधान की दृष्टि से बहुपक्षीय कार्रवाई की ओर अग्रसर है।

सबक सिखाना और सीखना दोनों जरूरी

आतंकवाद

राजकुमार सिंह
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक

बड़े लोगों के परिजन अकसर विदेश में ही रहते हैं, पर कहा जा रहा है कि सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारियों ने परिवारों को यूरोप भेज दिया है। यह पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद भारत-पाक में बढ़ते तनाव का असर है। उन्हें डर है कि प्रतिक्रियास्वरूप भारत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अभी तक सरकार ने सिंधु जल संधि स्थगित करने, पाक उच्चायोग स्टाफ घटाने, सार्क समेत 14 श्रेणियों में पाक नागरिकों को जारी वीजा तुरंत रद करने और अटारी बॉर्डर बंद करने जैसे कुछ सख्त फैसले लिये हैं। पाकिस्तान ने भी भारत के लिए अपना एयरस्पेस बंद करते हुए जवाबी कदम उठाये हैं। यह तनाव और बढ़ सकता है। इसी साल विधानसभा चुनाव वाले बिहार में जनसभा के बजाय दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकियों को 'मिट्टी में मिला देने' की चेतावनी देते तो शायद और बेहतर संदेश जाता। बिहार को कुछ सौगातें देने के मौके पर जनसभा में मोदी ने कहा कि 'उन्हें उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा' मिलेगी। धार्मिक पहचान पूछ कर 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने वाले मानवता के दुश्मनों को कठोरतम सजा मिलनी ही चाहिए, पर उनको नापाक मंसूबों में सफल हो जाने देने के लिए जिम्मेदार हमारे तंत्र पर भी तो गाज गिरनी चाहिए। पर्यटन कश्मीर की अर्थव्यस्था की रीढ़ है।

सुरक्षा में चूक का सवाल

हाल के वर्षों में वहां पर्यटकों की बढ़ती संख्या भी सुखद है। फिर स्विटजरलैंड से तुलना वाली पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हजारों पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई मौजूद क्यों नहीं था? आखिर देश भर से ये पर्यटक 'स्थिति सामान्य' होने के सरकारी दावों पर भरोसा करते हुए ही वहां गये थे। आपसी रिश्ते रसातल में पहुंच जाने के बावजूद इस संकटकाल में विपक्ष ने हर कदम के लिए सरकार को समर्थन देकर समझदारी का परिचय दिया है, लेकिन सुरक्षा में चूक की बात घुमा-फिरा कर स्वीकार करने वाली व्यवस्था खुद पर उठते सवालों का जवाब कब देगी? केंद्र सरकार के ये स्पष्टीकरण कि टूर ऑपरेटर्स ने बिना बताये टूर शुरू कर दिये तथा जहां हमला हुआ, वह जगह मेन रोड से बहुत दूर है, गैर-जिम्मेदारी की पराकाष्ठा हैं। जो सरकारी तंत्र हजारों पर्यटकों के पहलगाम पहुंचने की जानकारी के लिए टूर ऑपरेटर्स की सूचना पर निर्भर हो तथा घटनास्थल मेन रोड से बहुत दूर होने के कारण वहां पर सुरक्षाकर्मी न होने का कुतर्क दे सकता हो, उसकी क्षमता और दक्षता पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। सामान्य समझ भी बताती है कि ऐसे हमले को बिना सुनियोजित साजिश और लंबी तैयारी के अंजाम नहीं दिया जा सकता।

हमारे सत्ता तंत्र की जवाबदेही

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा पुनः कश्मीर राग आलापे जाने तथा पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर द्वारा अचानक हिंदू-मुसलमान के बीच स्पष्ट भेद बताते हुए

द्विराष्ट्र थ्योरी पर कुतर्कों के साथ लंबे प्रवचन से भी हमारी व्यवस्था के कान खड़े नहीं हुए। वैसे जो तंत्र हमले की आशंका की खुफिया सूचना के बावजूद पर्यटक स्थलों पर भी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाया, उससे दुनिया के घटनाक्रम से सजग होने की उम्मीद नहीं जा सकती। पहलगाम जैसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था नदारद होने से सेना की घटती संख्या तथा अग्निवीर जैसी विवादास्पद योजना पर भी नये सिरे से सवाल उठने लगे हैं। तर्क दिया जा सकता है कि सुरक्षा में चूक के बाद सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन इनके जवाब दूरगामी प्रभाव और परिणाम तय करेंगे।

पाकिस्तान तो अस्तित्व में आने के बाद से ही भारत में अलगाववाद और आतंकवाद फैलाने की साजिशें रचता रहा है, पर उन्हें नाकाम करते हुए देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही हमारे सत्ता तंत्र की है। इसलिए नापाक पाक पर निशाना साधते हुए भी अपनी नाकामी की जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। संविधान संशोधनों के बाद जम्मू-कश्मीर की वास्तविक कमान केंद्र सरकार और उसके प्रतिनिधि उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा के ही हाथ है। पिछले साल अक्तूबर में विधानसभा चुनाव हो जाने के बावजूद सुरक्षा संबंधी अहम बैठकों में निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बुलाया तक नहीं जाता। बेहद संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में निर्वाचित सरकार को नजरअंदाज कर सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद से लड़ाई में सफलता की सोच में ही विफलता निहित है। दूसरा बड़ा मुद्दा धार्मिक पहचान पूछ कर मारे जाने को बनाया जा रहा है। बेशक यह मानवता के विरुद्ध है, पर मानवता के विरुद्ध तो आतंकवाद ही है। पंजाब में आतंकवाद के दौर में भी धार्मिक पहचान के आधार पर बसों से उतार कर हत्या की जाती थी। पहलगाम में तो हिंदू पर्यटकों की जान बचाते हुए एक मुस्लिम ने अपनी जान तक गंवा दी। फिर भी देश के कई हिस्सों में कश्मीरी छात्रों को निशाना बना कर सांप्रदायिक विभाजन के पाकिस्तानी मंसूबे पूरे करने में कुछ लोग मददगार बनने को उतावले नजर आ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया को भी लग रहा है कि कुछ बड़ा होगा, पर कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या होगा, लेकन जो भी होगा, आतंकवाद पर करारा वार होगा। मोदी के ऐसे सख्त बोल पिछली बार 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा हमले पर सुनायी पड़े थे और 26 फरवरी को तड़के भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयरस्ट्राइक कर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया। उरी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह दूसरी बार था, जब भारत ने सीमा पार कर आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखाया। उसी के बाद सरकार और भाजपा ने नारा बुलंद किया कि यह नया भारत है, जो दुश्मन को घर में घुस कर मारता है। नारा जनता के सिर चढ़ कर बोला और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें 282 से बढ़ कर 303 हो गयीं। उत्साहित मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले, संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करते हुए उसे विभाजित भी कर दिया।

प्रायोजित आतंकी हमले जारी

दावा किया गया कि अनुच्छेद 370 अलगाववाद और आतंकवाद का औजार बन गया था। बाद के सालों में जम्मू-कश्मीर में बेहतर हालात का दावा भी किया जाता रहा, लेकिन पहलगाम हमला बताता है कि सुरक्षा के मोर्चे पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पाक प्रायोजित आतंकवाद के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान न भी माने, पर दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है कि पहलगाम में सीमा पार प्रायोजित आतंकी हमला ही था, लेकिन अप्रत्याशित हरगिज नहीं था।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आगे कुआं पीछे खाई

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

मेरा शीर्षक सीधा और सपाट है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैं किनकी बात कर रहा हूं। यहां एक ओर शैतान की भूमिका दिख रही है तो दूसरी ओर गहरा समुद्र। सवाल यह है कि शैतान कौन है और गहरा समुद्र किसे कहा जाए! दो अप्रैल, 2025 को शुरू हुए वर्तमान शुल्क संग्राम में भारत को दो देशों से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हैः संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। वर्तमान संदर्भ में, दोनों ही अप्रिय विकल्प हैं।

समस्या का एक पहलू...

वर्ष 2024-25 में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत का व्यापार था-

	अमेरिका	*चीन*	*विश्व*
निर्यात	86.51 अरब	14.25 अरब	437.42 अरब
आयात	45.3 अरब	113.45 अरब	720.24 अरब
अधिशेष	**41.21 अरब**	**-99.20 अरब**	**-282.82 अरब**

इसलिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ काम करते समय भारत को दो बिल्कुल विपरीत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, हमारे पास व्यापार खाते में अधिशेष है। अमेरिका को हमारे प्रमुख निर्यात- रत्न और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रानिक सामान और कुछ कृषि उत्पाद हैं। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्ता वाले फार्मास्यूटिकल्स को छोड़कर, अन्य ऐसी वस्तुएं हैं, जिनके बिना अमेरिका अपना काम चला सकता है या वह अन्य देशों से उन्हें आयात कर सकता है। मगर निर्यात होने वाली हर वस्तु से भारत में हजारों पुरुषों और महिलाओं की आजीविका चलती है। डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क लगाने के इरादे से हमारे व्यापार खाते में अधिशेष को खतरा है। जब तक 'विराम' है, और फार्मास्यूटिकल्स को अस्थायी रूप से छूट दी गई है, तब तक शुल्क की तलवार भारत के सिर पर लटकी हुई है। अगर शुल्क लगाए जाते हैं, तो इससे निर्यातक, नौकरियां, विदेशी मुद्रा आय और चालू खाता शेष गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। अमेरिका के साथ बातचीत करना और कठोर शुल्क से बचना, भारत के हित में है।

भारतीय वस्तुओं को रोकने से अमेरिका को भी कोई लाभ नहीं होगा, और ट्रंप यह अच्छी तरह जानते हैं। वे आयात को अनुमति देने का कोई तरीका निकाल लेंगे, लेकिन वे उसकी कीमत वसूलेंगे। वे भारत पर अमेरिका से अधिक खरीदने और व्यापार को 'संतुलित' करने पर जोर देंगे। मेरा अनुमान है कि वे भारत पर अधिक सैन्य उपकरण और विमान खरीदने का दबाव बनाएंगे- दोनों ही उच्च मूल्य वाले हैं। भारत अपनी अन्य जरूरतों, जैसे लोहा और इस्पात, कार्बनिक रसायन, प्लास्टिक, खनिज ईंधन और तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों को दुनिया के अन्य देशों से आयात कर सकता है, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से अमेरिकी सामान चुन सकता है। बड़ा सवाल यह है कि भारत उच्च लागत वाले अमेरिकी सैन्य उपकरणों और विमानों (और अब परमाणु रिएक्टरों) पर कितना अधिक खर्च कर सकता है? नरेंद्र मोदी ने बिना किसी विरोध के अमेरिकी उकसावे और ज्यादतियों को बर्दाश्त किया है, उन्हें ट्रंप के साथ समझौता करने पर मजबूर होना पड़ सकता है।

> **ची**न के साथ व्यापार घाटा भारत के चालू खाता घाटे को बढ़ाता है और यह एक बम की तरह है। अमेरिका के साथ अधिशेष ने एक हद तक चीन के साथ घाटे की भरपाई की है। अगर ट्रंप के शुल्क के कारण अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष गायब हो गया और चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया, तो यह भारत की स्थिति को और खराब कर देगा।

... और दूसरा पहलू

चीन के साथ भारत की समस्या बिल्कुल उलट है। भारत के व्यापार खाते में घाटा बहुत बड़ा और बढ़ता जा रहा हैः यह सौ अरब अमेरिकी डालर का बहुत बड़ा घाटा है। भारतीय उद्योग बिजली और इलेक्ट्रानिक उपकरणों, मशीनरी, कार्बनिक रसायन, प्लास्टिक और लोहा तथा इस्पात के मामले में चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है, क्योंकि चीनी माल की कीमतें कम हैं (कभी-कभी तो 'डंपिंग' के बराबर)। भारत के पास समान कीमतों और 'डिलीवरी-टाइम' पर कुछ ही वैकल्पिक स्रोत हैं। जब तक भारत अपने घरेलू विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार और उन्नयन नहीं करता- जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 13-14 फीसद पर अटकी हुई है- तब तक भारत चीन पर निर्भर रहेगा।

चीन को भारत का निर्यात मुख्य रूप से उपभोक्ता सामान, खनिज और पेट्रोलियम आधारित ईंधन, समुद्री खाद्य पदार्थ, सूती धागा और कुछ कृषि उत्पाद हैं। जाहिर है, कुछ मूल्यवर्धित सामान हैं, जिन्हें भारत चीन को निर्यात कर सकता है, जिन्हें चीन घरेलू स्तर पर नहीं बना सकता या दूसरे देशों से नहीं मंगा सकता। भारत की दुर्दशा विनिर्माण क्षेत्र की मोदी सरकार की उपेक्षा का नतीजा है। चीन ने भारत से और अधिक सामान आयात करने की इच्छा जताई है, लेकिन भारत इस प्रस्ताव का लाभ उठा सकता है या नहीं, यह बहस का विषय है।

चीन के साथ व्यापार घाटा भारत के चालू खाता घाटे को बढ़ाता है और यह एक बम की तरह है। अमेरिका के साथ अधिशेष ने एक हद तक चीन के साथ घाटे की भरपाई की है। अगर ट्रंप के शुल्क के कारण अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष गायब हो गया और चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया, तो यह भारत की स्थिति को और खराब कर देगा।

क्वाड कहां है?

एक और है जो खेल खराब करता है : क्वाड, या चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया की रणनीतिक प्राथमिकताएं भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं से काफी अलग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि क्वाड, चीन के विस्तारवाद के विरुद्ध एक मजबूत गढ़ बने। भारत क्वाड को समुद्री सुरक्षा, डिजिटल संपर्क, उभरती तकनीकों आदि तक सीमित रखना चाहता है और क्वाड को चीन विरोधी समूह में बदलने को लेकर सावधान है। इसके अलावा, चीन ने दुनिया को चेतावनी दी है कि कोई भी देश अमेरिका के साथ ऐसा समझौता करेगा, जो चीन के हितों के प्रतिकूल है, तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका (जो पूंजी और प्रौद्योगिकी का प्रमुख स्रोत है) और चीन (जो मध्यवर्ती और पूंजीगत वस्तुओं का प्रमुख स्रोत है) के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा, चीन एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी है, जो भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। अब तक, क्वाड में भारत की भागीदारी नपी-तुली और व्यावहारिक रही है, लेकिन दक्षिणपंथी प्रभावशाली लोगों (भारत और अमेरिका में) द्वारा भारत को चीन के साथ टकराव में धकेलने का खतरा है।

एक और दिलचस्प बात यह हैः राष्ट्रपति ट्रंप 20 जनवरी, 2029 को चले जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति शी जब तक चाहें पद पर बने और नियंत्रण अपने हाथ में रख सकते हैं। ट्रंप ढीठ और बेबाक हैं, शी चतुर और चालाक हैं। ट्रंप के दुस्साहस ने मोदी की दिग्भ्रमित संरक्षणवादी नीतियों को उजागर कर दिया है। मोदी को कदम पीछे खींचना चाहिए। उनके लिए अच्छी सलाह यही होगी कि वे अधिक खुले, परामर्शी बनें और विपक्षी दलों को दुश्मन मानने से बचें।

जवाब देने का वक्त

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

पहलगाम में उन पहाड़ों से घिरे, धूप से भीगे मैदान में इंसानों की ही नहीं, इंसानियत की हत्या की थी, उन कायर दरिंदों ने जो अपनी दरिंदगी करने के बाद भाग गए। दरिंदे ही होंगे, जो किसी नई दुल्हन के सामने उसके पति को जान से मार सकते हैं। जो छोटे बच्चे के सामने उसके पिता को मार सकते हैं। जो बूढ़ी मां की आंखों के सामने उसके बेटे को गोली मार सकते हैं। ऐसा काम कर सकते हैं, वैसे लोग जिनको मालूम ही नहीं होता है कि इंसानियत के मायने क्या हैं। सच पूछिए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उन लोगों की बातें सुनना, जो गए थे पहलगाम खुशियां मनाने और लौटे थे अपनी बर्बाद जिंदगियों के टुकड़े समेट कर।

दर्द जब कम हुआ तो पाया मैंने कि मुझमें इतना क्रोध भर आया कि जब बरखा दत्त के मोजो स्टोरी पर मुझसे पूछा गया कि आगे क्या करना चाहिए भारत सरकार को, तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शायद समय आ गया है एक दो पाकिस्तानी जरनैलों की हत्या करने का। जरनैल याद आए इसलिए कि कानों में गूंज रहा था पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का वह भाषण, जो उन्होंने पिछले हफ्ते दिया था प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए।

इस भाषण में भारत और हिंदुओं को लेकर इतनी नफरत थी कि शायद ही पाकिस्तान के किसी आला नेता ने पहले इतने स्पष्ट शब्दों में कहा होगा कि पाकिस्तान बनाया गया था, इसलिए कि हिंदुओं के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता था मुसलमानों का, क्योंकि हिंदू इतने अलग किस्म के लोग हैं कि उनके बीच मुसलमान रह ही नहीं सकते हैं। उनकी हर चीज अलग है हमसे, जनरल असीम मुनीर ने कहा, उनकी सभ्यता उनका मजहब, उनके तौर-तरीके। इस भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में कि कश्मीर पाकिस्तान की 'जुगुलर वेन' है। यानी शरीर की वह नस, जो काट दी जाए तो जीवित रहना असंभव है।

पाकिस्तानी सेना के आला अफसरों को मारना आसान नहीं है, जानती हूं मैं। लेकिन हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है पाकिस्तानी आतंकवादियों से, तो इस बार नुकसान ऐसा करना होगा पाकिस्तान का कि दोबारा हमारे देश में घुस कर हमारे लोगों को मारने की कभी कोशिश न कर सके। आतंकवादियों को पूरी तरह शरण मिलती है पाकिस्तानी सेना की, सो पहलगाम जनसंहार के कुछ घंटों बाद हाफिज सईद ने एक आम सभा में सीधे हमारे प्रधानमंत्री पर तल्ख बयानबाजी की।

यह वही महा-दरिंदा है, जिसने अपने प्यादों को भेज कर मुंबई में 26/11 वाली आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था। मैं मुंबई में रहती हूं और आज भी जब उन जगहों से गुजरती हूं जहां निहत्थे लोगों को मारा गया था, तो मेरे दिल में क्रोध भर जाता है, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद हमारी सरकार ने पाकिस्तान का थोड़ा-सा भी नुकसान करने का प्रयास नहीं किया था। सबूत थे हमारे पास कि उस जनसंहार में पाकिस्तानी सेना का हाथ था। सबूत था कि जिन प्यादों को मुंबई भेजा गया था, उन प्यादों ने हर कदम लेने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति से बात की थी, जो उनको लगातार आदेश दे रहा था कि आगे क्या करना है। यहां तक कि जब इन प्यादों का असलाह खत्म हो गया था और उनको पकड़ने के लिए हमारे कमांडो पहुंच रहे थे, तो उस अनजान व्यक्ति ने सलाह दी कि बस अब अल्लाह के घर जाने की तैयारी कर लो।

सारे सबूत दिए गए थे पाकिस्तान सरकार को, लेकिन एक बार भी हाफिज सईद और उसके साथियों के खिलाफ असली कार्रवाई करने की कोशिश नहीं हुई। याद है कि जब 2013 में मैं लाहौर गई थी चुनाव की रिपोर्टिंग करने, तो मैंने कोशिश की हाफिज सईद के ठिकाने की तहकीकात करने की। जब उसके अड्डे के पास पहुंची, तो देखा कि उस गढ़ की सुरक्षा कर रहे थे पाकिस्तानी पुलिसवाले। शायद पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में रहता है यह दरिंदा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसामा बिन लादेन को एबटाबाद की छावनी में रखा गया था। यथार्थ यह है कि जिहादी आतंकवादियों को पैदा किया है पाकिस्तानी सेना ने, जबसे उनको पता लगा कि युद्धभूमि में भारत को हराना असंभव है।

> **क्या** पाकिस्तान इस बार भी हमारी भूमि पर आकर आतंक फैलाने के बावजूद दंडित होने से बच सकता है? इस बार भारत का साथ दे रहे हैं दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश। यहां तक कि चीन की सरकार से भी पहलगाम वाली घटना की निंदा सुनने में आई है। लेकिन क्या हमारा साथ तब भी देंगे, अगर हम पाकिस्तान से युद्ध करने का निर्णय लेते हैं?

तो आगे क्या करना चाहिए भारत को? क्या पाकिस्तान इस बार भी हमारी भूमि पर आकर आतंक फैलाने के बावजूद दंडित होने से बच सकता है? इस बार भारत का साथ दे रहे हैं दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश। यहां तक कि चीन की सरकार से भी पहलगाम वाली घटना की निंदा सुनने में आई है। लेकिन क्या हमारा साथ तब भी देंगे, अगर हम पाकिस्तान से युद्ध करने का निर्णय लेते हैं? शायद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बेशक मोदी को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरी बार बने हैं यह वादा करके कि दुनिया में हो रहे दोनों युद्ध रोकेंगे राष्ट्रपति बनते ही। उनके इस कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने वाले हैं कुछ दिनों में और न यूक्रेन और रूस का युद्ध रोकने में सफल रहे हैं और न ही इजराइल को रोक पाए।

तो क्या कर सकते हैं मोदी? मेरी राय है कि पाकिस्तान को जवाब उसकी भाषा में देने की जरूरत है, जो उसको समझ में आए। पाकिस्तानी सेना के आतंकवादियों को खत्म करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए, चाहे उनको 'घर में घुस कर' मारना पड़े। अभी तक जो कदम उठाए हैं सरकार ने वह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इस बार हमको भूलना नहीं चाहिए पहलगाम। न आज, न कल, ना भविष्य में। इस बार सोच-समझ कर पूरी तैयारी से इसका बदला लेना चाहिए ऐसा कि पाकिस्तान के जरनैल नियंत्रण में लाए जाएं।

नीति पर गहराती अनीति

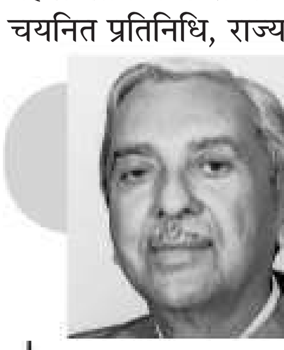

शिक्षा

जगमोहन सिंह राजपूत

अध्यापक बच्चों के शिल्पकार होते हैं। इसके लिए भावी अध्यापक निर्धारित संस्थाओं में प्रशिक्षित किए जाते हैं। वहां वे शिक्षक-प्रशिक्षकों के वक्तव्य सुनते, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते और प्रयोग करते हैं। फिर, देश के भविष्य की पीढ़ी को संवारने के काम में लग जाते हैं। यही अध्यापक उनको गढ़ता है, जो भविष्य में विभिन्न पदों पर रह कर अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। सभी जानते हैं कि इसी प्रक्रिया से सरकारी दफ्तरों के बाबू, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, देश के विभिन्न स्तरों पर चयनित जनप्रतिनिधि तैयार होते हैं।

न जाने कितने भाषण मूल्यों की शिक्षा, नैतिकता, सदाचरण, ईमानदारी, सत्य के महत्त्व आदि को लेकर दिए गए होंगे, दिए ही जाते रहते हैं। गांधी के अमर वाक्य 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश है' जैसे विषयों पर अनेक भाषण दिए जा चुके हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं। पर ऐसे विषयों पर बातें करने वालों का भी समय के साथ उत्साह कम होता देखा जाता है, क्योंकि अब अध्यापक और विद्यार्थी इसे केवल औपचारिकता के लिए सुनते तो हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि व्यवस्था और उसे चलाने वाले नैतिकता, मानवीय मूल्य, और गांधी तथा गांधीवादी आचरण से बहुत दूर जा चुके हैं। अपवाद तो अवश्य हैं, लेकिन जो भेड़चाल से अलग होता है, उसका हश्र तय करने वाले सदा सचेत रहते हैं।

देश के करोड़ों युवाओं नें गांधी का यह 'जंतर' पढ़ा होगा, जो एनसीईआरटी की सभी पाठ्य पुस्तकों का अनिवार्य पृष्ठ रहता है कि- जो भी कार्य करो; या प्रकल्प प्रारंभ करो, सदा ध्यान रखना कि इससे 'पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति' के जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा! देश में इस समय शायद ही भारतीय प्रशासनिक सेवा- आइएएस का कोई अधिकारी होगा, जिसने यह वाक्य न पढ़ा हो! फिर, गांधी के मूल्य कहां और कैसे विलुप्त होते जा रहे हैं, और स्कूलों से, विश्वविद्यालयों से जो कुछ सामान्यजन तक पहुंचता है, वह कष्टकर क्यों होता है?

आज से पांच-छह दशक पहले तक इस पर और गांधीवादी मूल्यों पर, अनेक अवसरों पर, स्कूलों, विश्वविद्यालयों तथा संवादों में पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की गहन चर्चा होती थी। आज वह गहराई औपचारिकता मात्र में खो गई है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद दौलत सिंह कोठारी साठ-सत्तर के दशक में भारत के विकास के लिए चार शब्दों का सूत्र देते थेः साइंस, टेक्नोलाजी, प्रोडक्शन (उत्पादन), और गांधी- एसटीपीजी! डा कोठारी के इस सूत्र में से चौथा- जी यानी (गांधी) कहीं खो गया है। विकास और प्रगति की किसी भी अवधारणा का आधार वही हो सकता था।

जीवन जीने के ढंग और उसके विवेचन का जो उदाहरण गांधी ने सभी के समक्ष रखा था, जिसे करोड़ों लोगों ने अपनाया था, वह प्रक्रिया तक पश्चिम का अंधानुकरण करने में कहीं खो गई। लोकतंत्र सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बन कर रह गया- अपवाद छोड़कर- और सत्ता में पहुंचकर मनमानी करने की पूर्ण स्वच्छंदता को मानक बनाने में जन-प्रतिनिधियों ने कोई देरी नहीं की। इसमें सत्ता-व्यवस्था के शिखर पर बैठे लोगों ने जमकर भागीदारी की। जब किसी भी क्षेत्र में कोई नई नीति घोषित की जाती है, जनता में सराही जाती है, मगर यह भी तुरंत याद कर लिया जाता है कि क्रियान्वयन तो वही व्यवस्था करेगी, जो एक ऐसी कार्य-संस्कृति की अभ्यस्त हो गई, जिसमें स्वार्थ ही सर्वोपरि स्थान पर आकर जम चुका है। अगर शीर्ष स्थानों पर पहुंचे कुछ जन-प्रतिनिधि भी वास्तव में जनसेवक नहीं रहे हैं, उनकी रुचियां कहीं और हैं, तो अधिकारियों और अपराधियों पर उसका प्रभाव अवश्यंभावी था! उससे ही आज हर नागरिक दिन-प्रतिदिन जूझ रहा है। बिना किसी अपवाद के यह कहा जा सकता है कि हर क्षेत्र की नीति सामान्य जन के हित की ही चर्चा करती है, उसी के प्रति समर्पित बताई जाती है। मगर क्रियान्वयन के स्तर पर सेवा-भाव और जन-कल्याण के प्रति समर्पण कहां तिरोहित हो जाता है, इसकी चिंता कौन करे!

परिवर्तन तो होगा ही, और मानव-मात्र को सदा सकारात्मक परिवर्तन के मार्ग की ही खोज करते रहना चाहिए। अगर कर्मठता, प्रतिबद्धता तथा जन-सामान्य के प्रति समर्पण का भाव स्कूलों में जगाया जा सकता, तो जनता से प्राप्त सरकारी धन का घोर दुरुपयोग करने के पहले लोग कम से कम हिचकते तो अवश्य। 1960 में सरकारी स्कूल, चयनित प्रतिनिधि, राज्य और केंद्र के लोक सेवा आयोग, न्यायाधीश को जो साख, स्वीकार्यता और सम्मान प्राप्त था, आज उसका कितना अंश शेष है? यश और प्रतिष्ठा के बदले में उनको जो मिला, कितना संतोषप्रद है, और क्या वह आगे जीवन में सुख दे सकेगा? हमारी संस्कृति का सूत्र तो यह था कि सुपात्र बनकर धन अवश्य कमाना चाहिए, लेकिन धन से सुख तभी मिलेगा जब बीच में एक अन्य महत्त्वपूर्ण कड़ी का निर्वाह किया गया होगाः सदाचरण!

> **जी**वन जीने के ढंग और उसके विवेचन का जो उदाहरण गांधी ने सभी के समक्ष रखा था, जिसे करोड़ों लोगों ने अपनाया था, वह प्रक्रिया तक पश्चिम का अंधानुकरण करने में कहीं खो गई। लोकतंत्र सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बन कर रह गया- अपवाद छोड़कर- और सत्ता में पहुंचकर मनमानी करने की पूर्ण स्वच्छंदता को मानक बनाने में जन-प्रतिनिधियों ने कोई देरी नहीं की। इसमें सत्ता-व्यवस्था के शिखर पर बैठे लोगों ने जमकर भागीदारी की।

इसको सभी मत और पंथ स्वीकार करते हैं, भारत में इस 'धर्म' यानी सद-आचरण कहते हैं, और यह सर्वव्यापी है। दुर्भाग्य से इस अत्यंत सारगर्भित शब्द को वर्ग-विशेष से जोड़ दिया जाता है। सदाचरण मानवीय धरोहर है, मनुष्य के पृथ्वी पर बनाए रहने की प्राथमिक आवश्यकता है। वह सदाचरण ही है, जो मनुष्य, अन्य सभी जीवधारियों, पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों, नदियों-पहाड़ों, समुद्रों-हिमखंडों यानी प्रकृति के हर अवयव से समन्वय के साथ जीने की कला सिखाता है। जब तक मूल्य-आधारित व्यक्तिगत आचरण स्वयं द्वारा स्वीकृत और अंतर्निहित नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी नीति या निर्णय की पूर्ण सफलता की आशा करना बेमानी होगा।

सब साथ साथ

बाखबर

सुधीश पचौरी

वक्फ कानून के खिलाफ 'जंतर मंतर' से 'तालकटोरा' तक गर्मी बढ़ाई जाती रही। वक्फ कानून का कांटा कुरेदता रहा। फिर आई पहलगाम से आतंकी हमले की खबर और हर चैनल यही दिखाता रहा कि आतंकियों ने नाम पूछ कर गोलियां मारीं। एक नवविवाहित दंपति एक रेस्तरां में बैठा भेल-पूरी खा रहा था कि हेलमेट कैमरे लगाए एके 47 ताने आतंकी ने आ घेरा और खबरों को मुताबिक, नाम पूछा और कलमा पढ़ने को कहा, उसके बाद गोली मार दी। वह युवती पति की लाश के साथ बैठी रोती-बिलखती अपना दुख बताती रही। वहां छब्बीस लोगों को गोलियां मारी गईं।

इन दृश्यों ने पहली बार इस बात पर हुई बहसों में यह मुद्दा बनाया कि आतंकवाद का भी धर्म होता है। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग कहते रहे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। खबरें आती रहीं कि वे 'नाम धर्म' पूछ रहे हैं... कलमा पढ़ने को कह रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों ने यही कहा कि नाम और धर्म पूछे गए, इसका अभी कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि खबरों में भी यह दिखाया गया कि जिसके पति को उसके सामने गोली मारी गई, उसने नाम पूछने और गोली मार देने की बात कही थी। यह पूछा जाने लगा कि कब तक आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई से बचा जाएगा।

ऐसे ही एक बात पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने 'दो राष्ट्र' सिद्धांत के आधार पर बने पाकिस्तान को लेकर कही थी, जिस पर कई चैनलों में गरमागरम बहसें उठी थीं। इनमें भी कई छुटभैये इस सबके लिए हिंदुत्व को जिम्मेदार ठहराते रहे। एक तो यह उकसाते भी तक दिखे कि जवाब में पाक को 'न्यूक' क्यों नहीं कर देते... जिसका सही जवाब एक आहत कश्मीरी ने ही दिया कि ये यही करते हैं... पहले कहेंगे कि पाक को 'न्यूक' कर दो, फिर कहेंगे कि पाक भी 'न्यूक' कर सकता है, इसलिए चुप रहो। 'गरमी' बढ़ते-बढ़ते जनसंहार में बदल गई तो भी 'कलीमावादी' प्रवक्ता हिंसा की ऊपरी निंदा करते हुए सवाल करते रहे कि इसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है... खुफिया एजंसियां क्या कर रही थी... फौज क्या कर रही थी... आदि।

एक एंकर ने याद दिलाया कि कश्मीर के शासक दल के एक नेता एक दिन पहले कहे थे कि यह पर्यटक कश्मीरी संस्कृति पर हमला है। सवाल है कि क्या इस तरह बच गई कश्मीरी संस्कृति... बाजार बंद... कोई पर्यटक नहीं... कोई ग्राहक नहीं..! एक चर्चक 'एक मुसलिम भी मारा गया' कहकर इस हमले में अलग तर्क देता दिखा।

ऐसे लोगों को देखकर एक चर्चक ने कहा कि जब तक ऐसे तत्त्व हैं, तब आप आतंकवाद को लेकर आप सख्त संदेश नहीं दे सकते। बहरहाल, इस 'जिहादी हत्याकांड' के 'सीधे प्रसारण' ने ऐसा वातावरण बनाया कि सारे 'किंतु परंतु' वाले शांत हो गए! यह हमला जानबूझ कर ऐसे समय पर किया गया, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे। हमला इतना अचानक हुआ कि प्रधानमंत्री को सऊदी दौरा बीच में छोड़ कर आना पड़ा और बिहार की मधुबनी में मनाए जाते 'पंचायत दिवस' की रैली में हिंदी में बोलते-बोलते प्रधानमंत्री ने दुनिया को अंग्रेजी में संबोधित किया कि यह भारत की आत्मा पर आघात है। धरती के कोने तक खोजकर आतंकियों को ऐसा सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी न की होगी। 140 करोड़ लोग भारत के साथ हैं..!

> **अ**गले रोज रक्षामंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों को स्थित से अवगत कराया और इस बार सभी ने एक स्वर में कहा कि वे सरकार के हर कदम के साथ हैं। इस गाढ़े वक्त में भारत को अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इटली का भी समर्थन मिला।

इसके साथ ही, सुरक्षा विशेषज्ञों की बैठक कर सरकार ने 'सिंधु जल संधि' को 'निलंबित' कर दिया और 'अटारी बाघा बार्डर' को बंद करने का एलान भी किया। इसके बाद फिर अपने और पाक दूतावास कर्मियों की संख्या को भी कम करके बता दिया कि भारत इसे यों ही नहीं जाने देगा। ऐसे ताबड़तोड़ फैसलों से कई 'किंतु परंतु' करने वालों को जवाब मिला। इसी बीच कई चैनलों पर अगली 'सर्जिकल स्ट्राइक' की मांग उठने लगी। हर चैनल चीखता दिखा कि बदला लो... बदला लो..!

हमले की खबर के तुरंत बाद गृहमंत्री ने कश्मीर जाकर सारी स्थिति का जायजा लिया और आहत लोगों और उनके परिजनों को सहायता का आश्वासन दिया और आतंकियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का वचन दिया। अगले रोज रक्षामंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों को स्थिति से अवगत कराया और इस बार सभी ने एक स्वर में कहा कि वे सरकार के हर कदम के साथ हैं। इस गाढ़े वक्त में भारत को अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस इटली का भी समर्थन मिला। जाहिर है, हर भारतवासी के भीतर गुस्सा पैदा हुआ और हर चैनल कहता दिखा कि बदला लो... बदला लो!

मुख्यमंत्री ने फिर चेताया, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी में जवाब देंगे

● पहलगाम में हुए कायराना हमले की सीएम योगी ने निंदा की

● नाव पर बैठकर देखा शारदा नदी के चैनलाइजेशन का कार्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ लखीमपुर खीरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हुए यूपीवासियों की ओर से संवेदना व श्रद्धांजलि व्यक्त की। सीएम ने कहा कि सभ्य समाज में आतंकवाद-अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। भारत सरकार का सेवा, सुरक्षा व सुशासन का मॉडल विकास, गरीब कल्याण और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 'जिस भाषा में समझेगा, उस भाषा में जवाब देने के लिए' नया भारत तैयार है। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़ने वाले को पीएम मोदी के नेतृत्व में छोड़ेगा भी नहीं। जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत ही यूपी को माफिया, अराजकता, दंगा मुक्त किया और देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में लाकर खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शारदा नदी के चैनलाइजेशन के बारे में जानकारी ली। फिर यहां से नाव पर सवार हुए और वहां के कार्यों का निरीक्षण किया।मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान, आवास व ट्रैक्टर की चाबी आदि प्रदान की। बाढ़ नियंत्रण की सकारात्मक पहल के लिए बिजवा व पलिया ब्लॉक के किसानों ने मंच पर आकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जलशक्ति विभाग बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए शारदा नदी को चैनलाइज करने जा रहा है। इससे किसान का खेत भी बचेगा और बाढ़ से बस्ती भी बचेगी। सात किमी. लंबा चैनल बनाने का कार्य हो रहा है। सीएम ने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आना था, लेकिन मैंने कहा कि पहले काम शुरू करो। अब यह कार्य तेजी से बढ़ रहा है। योगी ने कहा कि सरकार जो पैसा खर्च करती है, वह मुख्यमंत्री-मंत्री का नहीं, बल्कि यह जनता के टैक्स का पैसा है। इसका सदुपयोग होना चाहिए। पहले प्रस्ताव आया था कि 180 करोड़ से तटबंध बनाया जाए। इससे किसानों की जमीन भी जाती। मैंने पूछा कि शारदा नदी में तीन-सवा तीन लाख क्यूसेक पानी आएगा तो मिट्टी का तटबंध कैसे इसे रोक पाएगा। यह समस्या का समाधान नहीं है, नदी को चैनलाइज कीजिये, ड्रेजर मंगाइये और नदी को एक साथ चलने का रास्ता दीजिये, तब बाढ़ की समस्या का समाधान होगा।

सीएम की किसानों से अपील, भूसा बैंक बनाइए

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार आया था तो खेतों में गेहूं व गन्ना की फसल थी। अब किसानों ने समय पर उसे समेट लिया है। सीएम ने अपील की कि फसल कट गई है तो आग न लगाइए, बल्कि भूसा बैंक बनाइए, गोमाता का आशीर्वाद बना रहेगा। भूसा में हरा चारा और चोकर मिलाकर खिलाएंगे तो गोवंश के दूध से आप व आपके बच्चे मजबूत होंगे। इससे दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए सीमाओं की रक्षा करने में सफल हो जाएंगे।

सीएम ने दुधवा टाइगर रिजर्व का किया निरीक्षण

विदेशी पर्यटकों से किया संवाद, शिशु हथिनी का नाम रखा भवानी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ लखीमपुर खीरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दुधवा टाइगर रिजर्व का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया। थारू समाज की महिलाओं के कार्यों को जाना। विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने यहां विदेशी पर्यटकों से भी संवाद साधा।

मुख्यमंत्री ने दुधवा टाइगर रिजर्व का निरीक्षण किया। सबसे पहले थारू समाज की महिलाओं ने सीएम का स्वागत किया। यहां उन्होंने नाबार्ड द्वारा केले के लगाए गए उत्पादों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने यहां महिलाओं को प्रशस्ति पत्र भी दिया। मानव वन्य जीव संघर्ष को न्यूनतम करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (वलड वाइल्डलाइफ फंड फॉर नेचर), ट्रैक्युलाइज्ड गन, ट्रेल कैमरा, ड्रोन, आरआरटी (रैपिड रिस्पांस टीम) प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने यहां डॉक्टरों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने दुधवा टाइगर रिजर्व में विदेशी पर्यटकों से भी बातचीत की। उन्होंने यहा की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। विदेशी पर्यटकों ने यहां की व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई। सीएम ने वन विभाग के अधिकारियों को सभी का ध्यान रखने और सभी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सलूकापुर हाथी कैंप का भी अवलोकन किया। यहां उन्होंने शिशु हथिनी का नामकरण किया। सीएम ने उसे भवानी नाम दिया।

मुख्यमंत्री आज करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण, परखेंगे तैयारी

लखनऊ। सीएम योगी रविवार 27 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। पहले यह निरीक्षण 28 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन अब यह रविवार 27 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री तीन ज़िलों (हरदोई, शाहजहांपुर और हापुड़) में एक्सप्रेस निर्माण की जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पर सीएम योगी का विशेष फोकस है और उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द यह परियोजना पूर्ण हो, ताकि व्यापक पैमाने पर प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का भ्रमण करेंगे।

रिटायर जज विनोद कुमार सिंह बने सहकारी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष

● सहकारिता विभाग के पूर्व विशेष सचिव अच्छेलाल सिंह सदस्य नियुक्त

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

विनोद सिंह

अच्छेलाल

सरकार ने उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण के रिक्त चल रहे अध्यक्ष और सदस्य पदों पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां कर दी हैं। अवकाश प्राप्त जिला जज विनोद कुमार सिंह को न्यायाधिकरण का अध्यक्ष तथा अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी अच्छेलाल सिंह यादव को सदस्य नियुक्त किया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव सहकारिता सौरभ बाबू द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि कुछ समय से न्यायाधिकरण में अध्यक्ष व सदस्य के पद रिक्त चल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बहराइच निवासी विनोद कुमार सिंह को अध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गाजीपुर निवासी एवं पूर्व में सहकारिता विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्य कर चुके अच्छेलाल सिंह यादव को सदस्य नियुक्त किया गया है। सहकारिता मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए दोनों नवनियुक्त अधिकारियों को शुभकामनाएं दीं और विश्वास व्यक्त किया कि इनके नेतृत्व में सहकारी न्यायाधिकरण अधिक कुशलता से कार्य करेगा और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि विनोद कुमार सिंह को न्यायिक मामलों का गहन अनुभव है, वहीं अच्छेलाल सिंह यादव ने अपने कार्यकाल में सहकारिता विभाग में अनेक सुधारात्मक पहल कर सराहनीय योगदान दिया है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी: केशव मौर्य

● लविवि के मालवीय सभागार में नूतन पुरातन शैक्षिक परिवार ने आयोजित की गोष्ठी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि एक राष्ट्र- एक चुनाव से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। एक राष्ट्र - एक चुनाव से आर्थिक बचत, प्रशासनिक दक्षता व राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले चुनाव के कारण प्रशासनिक कार्यों में व्यवधान और नीतिगत निर्णय में देरी होती है। एक साथ चुनाव करने से यह समस्या दूर होगी। चुनाव में होने वाले खर्च में कमी आएगी ,जिससे जो खर्च बचत आएगी, वह अन्य विकास कार्यों में लगाई जा सकेगी। श्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में विश्वविद्यालय नूतन पुरातन शैक्षिक परिवार द्वारा आयोजित एक राष्ट्र-एक चुनाव विषय संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र-एक चुनाव से होने वाले फायदों की चर्चा गांवों में सबके बीच करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव होने से सारा सरकारी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और आचार संहिता लग जाने से विकास कार्यों की गति धीमी पड़ जाती है। शिक्षक चुनाव प्रक्रिया में लग जाते हैं जिससे पढ़ाई में भी अवरोध आता है कर्मचारी लग, जाते हैं तो सरकारी कार्यों में भी गति धीमी हो जाती है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के लिए आवश्यक है, उसे करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने व 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प संकल्प लिया है। भारत इस दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की विश्व समुदाय में प्रतिष्ठा बढ़ी है। एक राष्ट्र-एक चुनाव यह जन चर्चा का विषय बनना चाहिए लोगों को इस बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। अब देश के समय और संसाधनों को बचाने तथा जनता की भलाई के लिए एक राष्ट्र-एक चुनाव करना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

10 जून तक पूरी की जाएं बाढ़ से बचाव की सभी तैयारियां: योगी

लखनऊ/ लखीमपुर खीरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दुधवा टाइगर रिजर्व में समीक्षा बैठक की। उन्होंने यहां वन विभाग व पर्यटन विभाग के प्रजेंटेशन को देखा। फिर जनपद के विकास कार्यों को लेकर जिलाधिकारी से जानकारी ली। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधवा टाइगर रिजर्व के पार्क में मौलिश्री का पौधा रोपा, फिर यहां लगे स्टॉल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री का थारू महिलाओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में स्थानीय, वन व पर्यटन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से बचाव को लेकर चलाई जा रही तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि 10 से 12 जून तक इससे जुड़ी परियोजनाएं पूरी कर ली जाएं। साथ ही पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि जनपद के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों के समन्वय से योजनाएं तैयार कराई जाएं।

मुख्यमंत्री ने जनपद के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर भी जानकारी ली। सीएम ने वन विभाग के प्रजेंटेशन को देखने के बाद कहा कि पर्यटन विकास को बढ़ाने का निर्देश दिया और दुधवा में आने वाले पर्यटकों की वर्षवार संख्या पूछी। मुख्यमंत्री ने पर्यटन के अधिकारियों का भी प्रेजेंटेशन देखा और कनेक्टिविटी, होटल, गाइड के रूप में स्थानीय लोगों को जोड़ने की बात कही।

यूपी में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फैम ट्रिप आयोजित

लखनऊ। पर्यटन स्थल दुनियाभर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग द्वारा ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष फैमिलियराइजेशन ट्रिप (फैम ट्रिप) का आयोजन किया गया। फैम ट्रिप के तहत प्रतिभागियों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया गया, जिसमें उन्हें राज्य की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्प, स्थानीय खानपान और लोककला की झलक देखने को मिली। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन संभावनाओं को उजागर करना एवं स्थानीय समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। फैम ट्रिप में शामिल सदस्यों को चार दिवसीय यात्रा (आज से 29 अप्रैल, 2025 तक) के पहले दिन मथुरा जनपद के जैत गांव ले जाया गया। प्रतिभागियों ने गांव में सक्रिय स्वयं सहायता समूह, स्थानीय संस्कृति और हस्तशिल्प आदि को करीब से देखा। सदस्यों ने मिट्टी के बर्तन बनाने, पारंपरिक खिलौनों की रचना, लड्डू गोपाल की पोशाक तैयार करने और तुलसी माला बनाने की प्रक्रिया को करीब से अनुभव किया। फैमिलियराइजेशन ट्रिप (फैम ट्रिप) के दूसरे दिन दल के सदस्यों को मथुरा से आगरा के समीप स्थित कछपुरा गांव की यात्रा कराई जाएगी। इसी तरह, फैम ट्रिप के तीसरे दिन आगंतुक मैनपुरी जनपद के भावंत और सहन गांव की यात्रा करेंगे। भावंत गांव में जखदर महादेव मंदिर का दर्शन करेंगे और स्थानीय होमस्टे का अनुभव लेंगे। सिंघाड़े की खेती भी देखेंगे। आगंतुक भावंत गांव में अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाने, तरकशी कला का अनुभव और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेंगे। सहन गांव में स्थानीय हस्तशिल्प को देखने के बाद बुलंदशहर के सिकरपुर गांव के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। सिकरपुर में 'बगान ऑर्चर्ड रिट्रीट' का आनंद लेंगे। यह एक शांत, हरियाली से भरपूर और शुद्ध वातावरण में समय बिताने के लिए बेहतरीन स्थल है। तत्पश्चात, दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस प्रकार की यात्राएं प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक होंगी।

एक माह में सभी विधानसभाओं में 'आप' खड़ा करेगी संगठन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

'**यूपी** की बात, कार्यकर्ताओं के साथ' सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने पहुंचे प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित सभी कार्यकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का शिकार हुए मृतकों को दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दिया। संजय सिंह और अन्य नेताओं ने महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। संजय सिंह ने कहा कि आने वाले 1 माह के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी सभी विधानसभाओं में अपना मजबूत संगठन खड़ा करेगी उसके बाद 2 माह के अंदर प्रदेश के सभी ब्लाक और गांव स्तर पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एक मजबूत संगठन खड़ा करेगी! उन्होंने कहा कि आगमी 3 और 4 मई को प्रयागराज में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है जिसमें सभी आठ प्रान्त के अध्यक्ष उनके महासचिव, सभी जिलों के जिला प्रभारी जिलाध्यक्ष जिला महासचिव और प्रदेश के सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रकोष्ठ महासचिव इस दो दिवसीय शिविर का हिस्सा होंगे जहाँ पर सभी पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जायेगा।

आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए सरकार: अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए, पूरा देश सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार ठोस कदम उठाएगी। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले की घटना बेहद दुखद और निन्दनीय है। हम सभी लोग उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, हरियाणा और देश के अन्य राज्यों के शहीद परिवारों के साथ है।

अखिलेश यादव ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दल इस हमले के खिलाफ सरकार के साथ खड़े है। सरकार ने पाकिस्तान को जवाब देने और आतंकवादियों के खिलाफ जो फैसले लिए है, सभी सरकार के साथ है। पूरा देश चाहता है कि भविष्य में पहलगाम जैसी घटना न हो। सरकार को हर तरह से समर्थन है। उम्मीद है कि भविष्य में इंटेलिजेंस फेल नहीं होगा। सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी। इस घटना को लेकर सभी लोग कह रहे है कि सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर थी। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं था। अखिलेश यादव ने कहा कि देश का हर नागरिक बड़े, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग इस घटना से चिन्तित है। जम्मू-कश्मीर को लेकर भाजपा सरकार ने सभी फैसले अपनी मनमर्जी से लिए है।

सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी लेकिन उसके बाद भी घटना हो जाना दुखद है। भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। हमें उम्मीद है कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार ने जो आश्वासन दिया है, उस पर अमल करेगी।

नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर पेश करेगा इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025

लखनऊ। योगी सरकार एक बार फिर देश-दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश की ताकत, संभावनाओं और उपलब्धियों को पेश करने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर के बीच तीसरे ग्रैंड मेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 2025 का आयोजन करने जा रही है। इस मेगा इवेंट की कमान प्रदेश के 35 विभागों के नोडल अधिकारी संभालेंगे, जबकि 50,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में 12 प्रमुख श्रेणियों के तहत 48 स्टेकहोल्डर्स अपनी-अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे। इसका उद्देश्य प्रदेश को व्यापार, निवेश, उद्यमिता और सांस्कृतिक विरासत के ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करना है।

ट्रेड शो के जरिये प्रदेश की बहुआयामी क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में ट्रेड शो को भव्य आयोजित कराने के लिए शो में भाग लेने वाले विभागों और उनके नोडल अधिकारियों की सूची तैयार कर ली गयी है। इनमें कुल 35 विभागों के मिशन डायरेक्टर, विशेष सचिव, निदेशक और आयुक्त स्तर के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जो यूपीआईटीएस- 25 के सफल आयोजन की जिम्मेदारी संभालेंगे।

वीभत्स घटना अंजाम देने वाले आतंवादियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई: अजय राय

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● पहलगाम घटना में शहीद हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रार्थना सभा

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में शहीदों की आत्मा की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि एवं सर्वधर्म पाठ प्रार्थना सभा का आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा का संचलन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेवादल के मुख्य संगठक डॉ. प्रमोद कुमार पाण्डेय ने किया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में उपस्थिति सभी धर्म गुरूओं ने आतंकी हमले में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए अपने-अपने रीति रिवाजों से शांति पाठ कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की एवं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस नृशंस नरसंहार से पूरा देश स्तब्ध है एवं इस वीभत्स घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और इसके लिए कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। राय ने कहा कि हम कांग्रेस के अनुयाई हैं और राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम देश को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने की सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले में जो हमारे नागरिक शहीद हुए हैं कांग्रेस पार्टी उनके परिजनों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री राजबहादुर सिंह, पूर्व विधायक सतीश अजमानी, निवर्तमान कोषाध्यक्ष शिव पांडे, निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव त्यागी, डॉ. शहजाद आलम, डॉ जीयाराम वर्मा, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

वक्फ बिल को लेकर विपक्ष भ्रांतिया फैला रहा: संजय राय

● ओवैसी के पास वक्फ की करीब 10000 करोड़ की संपत्ति है: भाजपा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री अवध क्षेत्र प्रभारी संजय राय ने शनिवार को हलवासीया कोर्ट हजरतगंज में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस व सपा समेत पूरे विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग, अंजनी श्रीवास्तव, अशोक तिवारी, सौरभ वाल्मीकि समेत कई नेता मौजूद थे। इस मौके पर संजय राय ने कहा कि वल्फ बिल को लेकर विपक्ष भ्रांतिया फैला रहा है। विपक्ष के झूठ और भ्रमजाल को दूर करने के लिए वक्फ सुधार जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमे हमको बताना है कि किस तरह पूर्व में वक्फ द्वारा पसमांदा मुसलमानों, पिछडे वर्ग के साथ हिन्दू, सिख, ईसाई समाज के धार्मिक स्थलों, जमीनों पर अवैध कब्जा था। विधेयक से बौखलाकर विपक्ष वक्फ जमीनों पर कब्जा बनाये रखाने के लिये तरह-तरह के हथकडे अपना रहा है। सपा और कांग्रेस के घिनौने कृत्य को उजागर करने एवं अल्पसंख्यकों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए वक्फ सुधार जन जागरण अभियान प्रदेश स्तर पर चलाना है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत टाउन हॉल कार्यक्रम किए जाएंगे जिसमें प्रभावशाली मुस्लिम गुरुओं प्रमुखों से संपर्क संवाद व महिला मोर्चा द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रभावी महिलाओं से संपर्क करके वक्फ संशोधन की उपयोगिता को बताना है। संजय राय ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वक्फ में ऐसे संशोधन किए जिसमें पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। 2013 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने उसमें यह पावर दिया कि कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर कह दे कि मै इस फला जमीन पर मैने नमाज पढ़ा है यह फला जमीन वक़्फ़ की है चाहे उसके पास कोई कागज ना हो तो वह जमीन वक़्फ़ की मान ली जाती थी। सामान्य रूप से रेवेन्यू का कोई भी विषय या विवाद आता है, तो रेवेन्यू का जो अधिकारी होता है वह होता है उप जिला अधिकारी, उप जिलाधिकारी उसके बाद जिलाधिकारी उसके बाद कमिश्नर फिर रिवेन्यू बोर्ड होता है साथ ही तमाम जमीन और प्रॉपर्टी के मामले में सिविल कोर्ट भी है ,हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वक्फ में भारत की कोई भी कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती है। डीएम कमिश्नर सुनवाई नहीं कर सकते हैं और इसके कारण पूरे देश में वक्फ का एक आतंक खड़ा हो गया था।

उस आतंक को रोकने के लिए कानून बनाया गया लेकिन जो देश में वक्फ की संपत्तियां इकट्ठा हो रही थी या देश में जो वक्फ की संपत्तियां हैं वह संपत्तियां साढ़े सैंतीस लाख हैं अगर उसमें सही आमदनियां देखा जाए उन संपत्तियों का सही से प्रबंध किया जाए तो साल में 1 लाख करोड़ की आमदनी होगी। लेकिन सारी संपत्तियां भू माफियाओं के पास है उसमें केवल मुसलमान नहीं है उसमें कांग्रेस के हिंदू नेता भी हैं।

प्रदेश की हर निराश्रित महिला पेंशन की लाभार्थी का कराया जाएगा सत्यापन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश सरकार निराश्रित महिला पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों का सघन सत्यापन कराएगी। प्रमुख सचिव महिला कल्याण लीना जौहरी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके सत्यापन का काम 25 मई तक हर हाल में पूरा किए जाने के लिए कहा गया है। सत्यापन के दौरान मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। वहीं, पात्र लाभार्थियों को समय-समय पर भुगतान की जाने वाली धनराशि के संबंध में एसएमएस के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी। प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभान्वित महिलाओं का आधार प्रमाणीकरण भी अनिवार्य किया गया है। सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र महिलाओं को ही मिले। सत्यापन कार्य तीन चरणों में संपन्न होगा, जिसमे पहले चरण में लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य 10 मई तक पूरा किया जाना है। दूसरे चरण में 15 मई तक हस्ताक्षरित सूची सहित रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। इसके तीसरे और अंतिम चरण में 25 मई तक मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया जिलाधिकारी की देख रेख में होगी। जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सत्यापन पूरी गंभीरता और गहनता से किया जाए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण
भलाई करना मानव का सबसे शानदार कर्तव्य है

पाकिस्तान का पागलपन

आतंक का समर्थक कोई देश कितना निर्लज्ज हो सकता है, यह पहलगाम के भीषण आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के सैन्य अफसरों, नौकरशाहों और नेताओं की प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है। पहले तो पाकिस्तान आतंकी घटनाओं में अपना हाथ मिलने पर तरह-तरह की सफाई देता था, खुद को आतंकवाद से पीड़ित होने की बात करता था और आतंकी देश की अपनी छवि सुधारने का दिखावा करता था, लेकिन अब तो वह पूरी बेशर्मी पर उतर आया है। इसका पता वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान से मिलता है कि हम 30 वर्षों से आतंकी तैयार करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने यह गंदा काम अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के कहने पर किया, लेकिन क्या इन देशों ने जिहादी आतंक की फैक्ट्रियां तैयार करने के लिए उसे बंधक बना लिया था? सब जानते हैं कि वह डालरों के लालच में और इस्लामी जगत का अगुआ बनने के लिए यह सब कर रहा था।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से भी गंदा काम लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक ने तब किया, जब पहलगाम हमले को लेकर वहां रह रहे भारतीय अपना रोष प्रकट कर रहे थे। इस राजनयिक ने अपने उच्चायोग की बालकानी पर आकर भारतीयों का गला काटने की धमकी दी। गनीमत है कि उसने अपने हाथ में चाकू नहीं थामा। उसने इस्लामिक स्टेट के खूंखार जिहादियों जैसा इशारा कर पाकिस्तान को तो शर्मसार किया ही, यह भी बताया कि वहां के शासन के उच्चस्तर पर कैसी घृणित मानसिकता वाले लोग प्रवेश कर गए हैं। इस पर हैरानी नहीं कि भारतीयों का गला रेतने का इशारा करने वाला राजनयिक मूलतः पाकिस्तान का कर्नल है, जो लंदन में रक्षा सलाहकार के रूप में तैनात है। पाकिस्तान को तो उसकी इस हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, लेकिन ब्रिटेन को इस पर सोचना चाहिए कि क्या वह अपनी धरती पर ऐसे राजनयिक को सहन कर सकता है? इस राजनयिक की हरकत से यह और अच्छे से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तानी सेना किस तरह किसी जिहादी संगठन में तब्दील हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ही हैं, जो जिहादी मौलाना की तरह नफरत भरे भाषण करते हैं। एक ऐसा ही भाषण उन्होंने पहलगाम हमले के सप्ताह भर पहले ही दिया था। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनके जवाब में उसकी ओर से जैसे बयान आए, वे भी यही बताते हैं कि वह भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। कोई परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है तो कोई सिंधु जल समझौता रोकने के फैसले को युद्ध की घोषणा जैसा बता रहा है।

राजधानी का विस्तार

झारखंड की राजधानी रांची में जनसंख्या और नागरिक सुविधाओं का दबाव है। अलग राज्य गठन के साथ ही ग्रेटर रांची के निर्माण की मांग होती रही है। गौर करने की बात यह भी है कि एक ही साथ अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को ग्रेटर रायपुर के तौर पर एक विकसित और सुव्यवस्थित संरचना मिले दस साल से उपर हो चुके हैं। लेकिन अपने-अपने राज्य को अभी भी राजधानी क्षेत्र के विस्तार की प्रतीक्षा है। अब स्मार्ट सिटी कारपोरेशन की तरफ से रामगढ़ के उपायुक्त को पत्र लिखकर 600 एकड़ जमीन की पहचान करने को कहा गया है। बता दें कि रांची से बोकारो के बीच छह लेन हाईवे भी निर्माण के अंतिम चरण में है। इसके अलावा इस क्षेत्र में धनबाद से लेकर हजारीबाग, कोडरमा और चतरा जैसे जिले हैं जहां पावर प्लांट समेत कई उद्योगों की श्रृंखला बन रही है। पतरातू में एनटीपीसी के प्लांट से उत्पादन होने ही वाला है। ऐसे में राजधानी का विस्तार इस क्षेत्र में होने से विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। इस क्षेत्र में सड़क से लेकर बिजली और दूसरी आधारभूत संरचनाओं की स्थिति पहले से बेहतर है। विस्तृत राजधानी क्षेत्र का अगर निर्माण होता है तो शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं समेत जीवनशैली के कई क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल होंगी। इस पहल का स्वागत होना चाहिए।

स्मार्ट सिटी ने झारखंड की राजधानी के विस्तार के लिए रामगढ़ में जमीन चिह्नित करने का सुझाव दिया, बढ़ेंगी विकास की संभावनाएं

न भूलें और न ही माफ करें

संजय गुप्त

पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के जनरलों, नौकरशाहों और नेताओं की प्रतिक्रिया बहुत ही भोंडी, आतंक का महिमामंडन करने और उसके साथ बेशर्मी से खुलकर खड़े होने वाली है

पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकियों की ओर से जिस तरह पर्यटकों से उनका मजहब पूछकर हत्या की गई, वह मानवता को कलंकित करने वाली ऐसी बर्बर घटना है, जिसकी मिसाल मुश्किल से मिलती है। जिहादी आतंकियों ने पहले भी तमाम घटनाओं को अंजाम दिया है, पर भारत में यह पहली बार है, जब लोगों का मजहब पता कर हत्या की गई हो। साफ है आतंकी मजहबी उन्माद से प्रेरित थे। आतंकियों की ओर से इस तरह हत्या करने का एक मकसद भारत में हिंदू-मुस्लिम खाई पैदा करना भी था। यह अच्छा है कि उनके और पाकिस्तान के इस मकसद को पूरा न होने देने के लिए भारत के लोगों ने कमर कस ली है। मुस्लिम समाज ने पहलगाम की घटना का जिस तरह विरोध किया, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और कहा कि इस घटना ने इस्लाम को बदनाम किया है, वह स्वागतयोग्य है। देश में आगे भी सद्भाव बना रहे, यह देखना सभी समुदायों की जिम्मेदारी है।

पहलगाम की घटना उन चुनिंदा आतंकी घटनाओं जैसी है, जिसने दुनिया का आतंक के प्रति सोच बदला। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने स्थानीय आतंकियों से मिलकर इस घटना को अंजाम इसलिए भी दिया, ताकि यह दिखा सकें कि कश्मीर का माहौल बदला नहीं और वहां शांति नहीं लौट रही है। पाकिस्तान को कश्मीर में सामान्य होती स्थितियां रास नहीं आईं और उसने पहलगाम हमले की साजिश रची। पाकिस्तान से आतंकी कश्मीर में घुसने की कोशिश करते ही रहते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं और कुछ कश्मीर के आतंकियों से मिलकर आतंक को बढ़ावा देते हैं। यह सिलसिला इसलिए रुक नहीं रहा, क्योंकि कश्मीर में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो जिहादी मानसिकता से ग्रस्त हैं और इस मुगालते में हैं कि वे पाकिस्तान की मदद से आतंक के सहारे कश्मीर को मजहब के नाम पर आजाद करा लेंगे। इसीलिए वे आतंक की राह पर चलते रहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान उन्हें उकसाता ही नहीं है, हथियार और प्रशिक्षण देने के साथ हर तरह की मदद भी देता है। इन मुट्ठी भर लोगों की पहचान तब संभव है, जब कश्मीर की जनता उनके खिलाफ खुलकर खड़ी हो। पहलगाम की घटना के बाद अनेक लोग खड़े हुए, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि पर्यटकों पर कहर बरपाने वाले आतंकी छिपने में सफल रहे। आखिर किसी ने तो उनकी मदद की होगी।

कश्मीर में स्थितियां सामान्य हो रही हैं, यह संदेश भारत सरकार लगातार देश-दुनिया को दे रही थी। इसके लिए वहां जी-20 सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम और विधानसभा चुनाव कराए गए, पर कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं था। वहां आतंकियों और उनके समर्थकों की गतिविधियां जारी थीं। इसी कारण वहां आतंकी घटनाएं हो रही थीं, जिनमें सेना को भी निशाना बनाया जा रहा था। इन घटनाओं की तह तक जाने की जरूरत थी। पहलगाम की घटना इस ओर संकेत करती है कि कश्मीर में कुछ ऐसे आतंकी तत्व भी शांति के पक्ष में होने का दिखावा करने लगे थे, जिन्हें आर्थिक लाभ के चलते पर्यटकों के आने से तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वे भारत से बैर करना और आतंकियों का साथ देना नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे सभी तत्वों की पहचान और धरपकड़ पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना आवश्यक था। आतंकी घटनाओं में कमी के बाद भी आतंक के प्रत्येक समर्थक की चुन-चुन कर कमर तोड़ी जानी चाहिए थी, ताकि वे पाकिस्तानी आतंकियों से मिलकर कोई कारनामा न कर पाते।

पहलगाम की घटना के बाद इस प्रश्न का जवाब भी मिलना चाहिए कि आखिर पहलगाम में जहां पर रोज दो-ढाई हजार पर्यटक पहुंच रहे थे, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? पहलगाम के पहले कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकी घटनाएं हुईं, उनके लिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। उड़ी में हमले के बाद सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इसके बाद पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान ने भारत की इन सैन्य कार्रवाइयों से सबक नहीं सीखा। वह सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर के नेतृत्व में फिर से पुरानी राह पर आ गया।

भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के साथ अन्य फैसले लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। भारत के फैसले पर पाकिस्तान ने कहा है कि इस समझौते से पीछे हटने का मतलब युद्ध के एलान जैसा है। फिलहाल जो मौजूदा ढांचा है, उसमें पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोकना तत्काल संभव नहीं, लेकिन भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है और तैयारी भी कर रहा है। पाकिस्तान जब तक सुधरने का नाम नहीं लेता, भारत को उस पर दबाव बनाए रखना होगा। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि आगे हालात जैसे भी हों, उसे भारत से पहले जितना पानी नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान ने उस शिमला समझौते को भी रद करने की धमकी दी है, जिसका कभी उसने सम्मान किया ही नहीं। वह इस समझौते के खिलाफ जाकर कश्मीर मसले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहा, नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता रहा और आतंकियों की घुसपैठ कराता रहा। शिमला समझौते के बाद भी कारगिल में घुसपैठ हुई और न जाने कितने आतंकी हमले। यदि पाकिस्तान शिमला समझौता रद करता है तो भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को नियंत्रण रेखा से पीछे धकेलकर पुरानी अंतरराष्ट्रीय सीमा तक खदेड़ सकती है। ध्यान रहे कि भारत की संसद का यह प्रस्ताव है कि गुलाम कश्मीर को वापस लिया जाएगा।

पहलगाम की घटना इतनी भयानक है कि इसका प्रतिकार होना तय है। यह वक्त बताएगा कि यह सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में सामने आएगा या पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाली किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई के रूप में या अन्य किसी रूप में, पर पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, उसे न तो भूला जा सकता है, न ही पाकिस्तान को माफ किया जा सकता है। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के जनरलों, नौकरशाहों और नेताओं की प्रतिक्रिया बहुत ही भोंडी, उकसावे, आतंक का महिमामंडन करने और उसके साथ बेशर्मी से खुलकर खड़े होने वाली है।

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

एक जैसे भूकंप और ट्रंप

हास्य-व्यंग्य

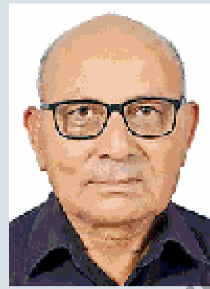

सूर्यकुमार पांडेय

अब तो ज्योतिषी भी कहने लगे हैं कि न तो ट्रंप का कुछ ठिकाना है, न भूकंप का। दोनों की ही भविष्यवाणी करना असंभव सा है

आज बहुत दिनों बाद मेरे कवि मित्र लतीफा लखनवी नमूदार हुए। वह जबसे 'अमेरिका रिटर्न' हुए हैं, 'ट्रंप' का तुक 'भूकंप' से मिलाते घूम रहे हैं। यूं भी आजकल इन दोनों से दुनिया में खलबली मची हुई है। वह उधर मुंह खोलते हैं, इधर भूकंप आने लगता है। मैंने उनसे पूछा, 'आप तो अमेरिका से लौटे हैं। अब तक तो आयात-निर्यात का अर्थ भी बखूबी समझ ही चुके होंगे। भैया बताओ, यह टैरिफ क्या बला है?'' लतीफा ने हंसते हुए कहा, ''दद्दू, आपको सच्ची बात बताता हूं। ट्रंप की जबान कमजोर है। वास्तव में वह 'टैरिफ' नहीं, 'तारीफ' बोलते हैं। वह जितना भी हो पा रहा है, टैरिफ, मेरा मतलब है, तारीफ झोंके पड़े हैं। तारीफ वह चीज है, जिसके दम पर दुकानदार ग्राहक को कैसा भी माल टिका देता है। ट्रंप भी इसी कोशिश में हैं। इसीलिए वह तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। सबको तारीफ बांट रहे हैं, पर अचरज है कि वह किसी और यहां तक कि उनके दोस्तों को भी रास नहीं आ रही है। इससे वह कंफ्यूज हैं और दोस्त-दुश्मन भी। वह कभी खूब तारीफ बांटते हैं और कभी उसमें कटौती करते हैं। इससे लोग चक्कर में पड़ जाते हैं और उनके चक्कर में शेयर बाजार घनचक्कर बन जाता है। आप बाजार और व्यापार के चक्कर में पड़ेंगे, तो शेयर मार्केट की मानिंद कभी ऊपर और कभी नीचे गोते ही लगाते रह जाएंगे। अभी शनि वक्री है। आप अपनी कुंडली की राशि की अंतर्दशा और जेब की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित कीजिए।''

मैंने कहा, ''वैसे तो अब तक कुल एक दर्जन राशियां ही हैं। हर कोई इन्हीं में से एक होता है, मगर मेरी जन्म की राशि कौन-सी है, यह आज तक साबित नहीं हो सका। हिंदी जन्मतिथि और समयानुसार मैं मीन राशि का हूं। मेरी मीन मेंटालिटी को देखकर इस पर एकबारगी विश्वास भी किया जा सकता है। मगर चूंकि मेरा घरेलू नाम 'स' से आरंभ होता है और मेरी लोकप्रियता भी इसी नाम से है, इसलिए कुछ पंडितों के विचार से मैं कुंभ राशि का हूं। मेरी मटके जैसी तोंद से भी इसकी सेंट-परसेंट तस्दीक होती है। तीसरी और हाईस्कूल सर्टिफिकेट वाली जन्मतिथि के अनुसार मेरी राशि लिब्रा यानी तुला है। अंग्रेजी गणना को देखने पर मैं धनु राशि का कहा जाऊंगा। भारी भ्रम है।''

लतीफा ने कहा, ''दद्दू, संशय विनाश का कारक है। आप तो उन ज्योतिषियों से मिलिए, जो ट्रंप से लेकर भूकंप की भविष्यवाणी करते हैं।'' मैंने कहा, ''भैया, वह भी कर के देख लिया है। ऐसे ज्योतिषी कहते हैं कि अब न तो ट्रंप का कुछ ठिकाना है, न भूकंप का और न आप का। कुछ बताना असंभव है। इस पर अपनी इस प्राब्लम को लेकर मैं एक प्रोफेशनल ज्योतिषी से मिला। उसने मेरी जन्मराशि में पांचवां आयाम जोड़ते हुए विचारा कि मुझे शर्तिया कन्या राशि का होना चाहिए। उसने अपने लैपटाप पर मुझे दिखलाया कि देखिए, एक घड़ी का डिफरेंस होने पर किस तरह ग्रह-नक्षत्र बदल जाया करते हैं और उसी के अनुसार जन्मराशि निर्धारित होती है।'' अब मैं पांच राशियों का स्वामी हूं। हर रोज सुबह उठकर पांच राशियों का भविष्यफल एक साथ बांचता हूं। उस रोज शाम तक जिस राशि का फलित सटीक बैठता है, मैं यह मान लेता हूं कि वही मेरी जन्म की सच्ची राशि है। फिर एक नई सुबह होती है। मेरी यह धारणा चेंज हो जाती है। तब मैं किसी और राशि का होता हूं। इस तरह मेरी जिंदगी में राशि का निर्धारण मेरे बर्थ टाइम से न होकर अखबार में प्रकाशित भविष्यफल से हो रहा है।'' लतीफा लखनवी ने ठहाका लगाया और कहा, ''दद्दू, लौट कर मिलूंगा। अभी अमेरिका की एक और ट्रिप पर निकलना है और वहां ट्रंप के साथ भूकंप को भी समझना है।'' फिर आकर आपको भी समझूंगा।

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

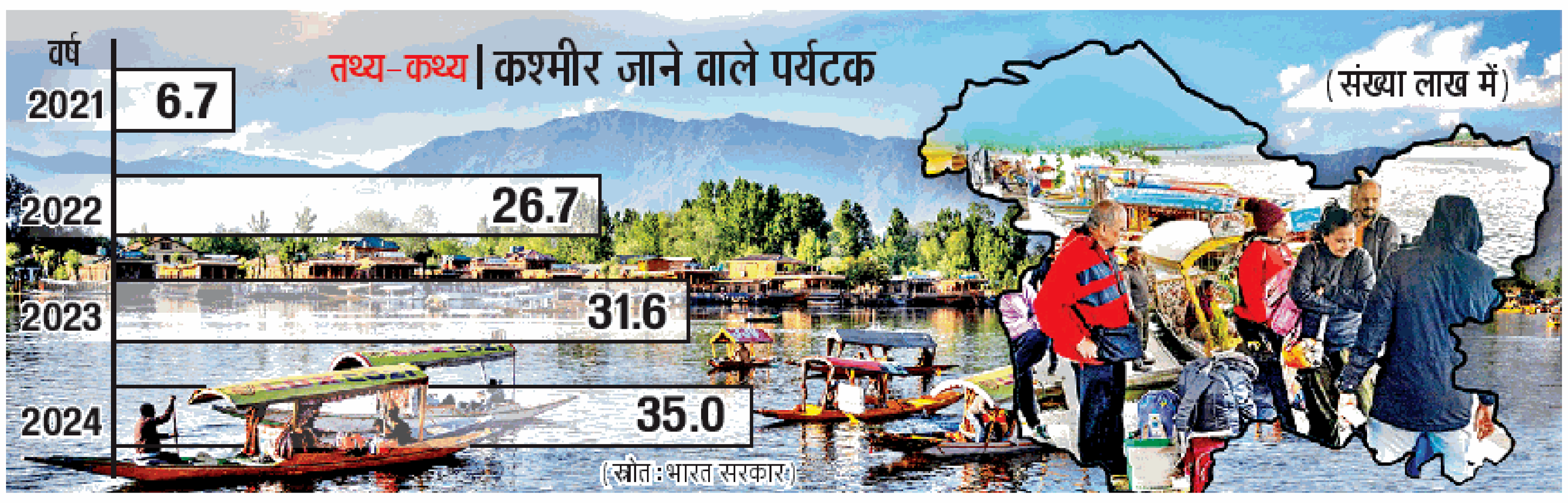

ऊर्जा

सत्य दर्शन

अद्वैत वेदांत दर्शन जगत को मिथ्या और ब्रह्म को सत्य मानता है। संसार और जीवात्मा भी ब्रह्म के ही भाग हैं। ब्रह्म परम सत्य है, जो सभी का स्रोत और आधार है। भ्रम संसार को एक अलग वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करता है। ब्रह्म के सत्य होने का अर्थ है कि जो भी है जड़ या चेतन, सब उस एक परमसत्ता से ही अभिव्यक्त हुए हैं। अंत में उसी में ही विलीन होंगे। संपूर्ण साकार जगत उसकी ही अभिव्यक्ति है, पर जगत मिथ्या है यानी जगत जैसा दिखता है वह वास्तविकता में है नहीं। यहां जगत को 'असत्य' नहीं कहा गया है, परंतु 'मिथ्या' कहा गया है। असत्य वह है जो कभी था ही नहीं, पर मिथ्या वह है जो सिर्फ आंखों से दिख रहा है, लेकिन उसका मूल रूप कुछ और ही है।

सत्य के अनुभव भी सबके अलग-अलग होते हैं। इसलिए सत्य भी तीन प्रकार से प्रकट होता है- प्रतिभासिक सत्य, व्यावहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। प्रतिभासिक सत्य, जो व्यक्ति के निजी अनुभव का परिणाम होता है। जैसे स्वप्न में देखी गई घटना हर व्यक्ति का निजी अनुभव है, जो किसी और ने नहीं देखा, पर स्वप्न टूटने पर समझ आ जाता है कि स्वप्न में देखी गई घटना एक मिथ्या अनुभव है। यहां व्यक्ति कहता है, 'जगत है, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं'। व्यावहारिक सत्य में एक ही घटना का सबका अलग या एक समान अनुभव हो सकता है, पर घटना घटी है यह अनुभव तो सब करते हैं। यहां व्यक्ति कहता है, 'जगत है इसलिए मैं अनुभव कर रहा हूं', परंतु ये दोनों ही प्रकार के सत्य मिथ्या होते हैं, क्योंकि दोनों ही देश, काल एवं परिस्थिति के सापेक्ष हैं। अतः सत्य वही एक पारमार्थिक सत्य होता है जिस पर जगत निर्भर है, जो देश, काल एवं परिस्थिति की परिधि के नियंत्रण से परे है और जो सभी कालों में शाश्वत तथा सर्वव्यापी है। वेदांत हमें उस पारमार्थिक सत्य से एकाकार करने का ही मार्ग है।

आदित्य नारायण अवस्थी

पृथ्वी की जल भंडारण क्षमता में आ रही कमी

मुकुल व्यास

मिट्टी, झीलों, नदियों और बर्फ में संग्रहीत पानी की भरपाई उस तरह नहीं हो पा रही है जैसी कि पहले हुआ करती थी

पृथ्वी की भूमि पर जल भंडारण करने की क्षमता कमजोर हो रही है। मिट्टी, झीलों, नदियों और बर्फ में संग्रहीत पानी की भरपाई उस तरह नहीं हो पा रही है जैसी कि पहले हुआ करती थी। विज्ञानियों ने एक नए अध्ययन में कहा है कि भूमि-आधारित जल भंडारण में भारी कमी का सीधा संबंध हमारे ग्रह की बढ़ती गर्मी से है। अध्ययन के निष्कर्ष कृषि भूमि की उत्पादकता के बारे में चिंता पैदा करते हैं और हमारे वैश्विक जल चक्र के लिए बड़े बदलावों का संकेत देते हैं। पृथ्वी का भूमि जल भंडारण प्रकृति के ताजे पानी के बचत खाते की तरह है। इसमें मिट्टी की नमी, बर्फ के ढेरों, ग्लेशियरों, आर्द्रभूमि, झीलों और भूमिगत जलाशयों में संग्रहीत पानी शामिल है। नदियां लगातार पानी को बहाती हैं, लेकिन ये जल स्रोत जलाशयों की तरह काम करते हैं। ये पानी को तब तक अपने स्थान पर रोके रखते हैं जब तक कि वह वाष्पित न हो जाए, पौधों द्वारा अवशोषित न हो जाए या जमीन की गहराई में रिस न जाए। जल चक्र सब कुछ गतिशील रखता है, लेकिन भूमि आधारित भंडारण कम वर्षा या सूखे के दौरान आपूर्ति को संतुलित करने में मदद करता है। पिछले कुछ वर्षों से मनुष्य की गतिविधियां उस संतुलन को बिगाड़ रही हैं। हम प्रकृति की जल भरपाई क्षमता की तुलना में भूजल को तेजी से बाहर निकाल रहे हैं, विकास के लिए आर्द्रभूमि को सूखा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से ग्लेशियरों को सिकोड़ रहे हैं।

इस बदलाव का कुछ हिस्सा बढ़ते वैश्विक तापमान से जुड़ा है। अतिरिक्त गर्मी मिट्टी की नमी को कम करती है। साथ ही फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में गर्मी को जकड़ती रहती हैं, जिससे सूखापन बढ़ता है। ग्रीनहाउस गैसें भविष्य में भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती रहेंगी। भूमि जल की कमी से महासागरों के पैटर्न में भी बदलाव हो रहा है। भूमि पर कम पानी का मतलब है समुद्र में अधिक पानी। यह अतिरिक्त महासागरीय जल समुद्र के स्तर को लगातार ऊपर की ओर उठाता है। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के समक्ष बाढ़ का खतरा रहता है। जल के जमाव के स्थान में परिवर्तन से पृथ्वी पर द्रव्यमान का वितरण भी भिन्न होता है। इस छोटे से बदलाव का वैश्विक महासागरीय धाराओं पर प्रभाव पड़ता है।

जलवायु रिकार्ड औद्योगिक क्रांति के समय से पृथ्वी के धीरे-धीरे गर्म होने की ओर इशारा करते हैं, लेकिन हाल में अधिक तेज गर्मी भूमि जल की कमी की प्रवृत्ति को बढ़ा रही है और तटीय आबादी की सुरक्षा के बारे में सवाल उठाती है। इस बीच विशेषज्ञों ने पृथ्वी के घूमने में थोड़ी सी अस्थिरता का पता लगाया है। भूमि जल में कमी इस अस्थिरता को बढ़ाती है। जल भंडारण में सुधार के लिए जल प्रबंधन और कार्बन नीतियों को बदलना पड़ेगा।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

हम सब सक्रिय हैं

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर इन दिनों विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय मुख्य रूप से सक्रिय हैं। इन मंत्रालयों के मंत्री ही सुर्खियों में छाए हुए हैं। ऐसे में अन्य मंत्रालय भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सक्रिय दिखने के प्रयास में पीछे नहीं रहना चाहते, ताकि लोगों को उनकी भी सक्रियता नजर आए। एक केंद्रीय मंत्री ने तो कुछ नहीं सुझा तो एक्स प्लेटफार्म पर पाकिस्तान को लेकर वर्षों पुराने अपने एक इंटरव्यू को ही पोस्ट कर दिया, ताकि पाकिस्तान के मामले में उनकी भी चर्चा हो। इसी तरह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पाकिस्तान के खिलाफ व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश में जुट गया है कि कैसे पाकिस्तान जाने वाले सामान को रोका जा सके। जाहिर तौर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी पाकिस्तान पर प्रहारों की पहल में पीछे नहीं रहना चाहता है।

भूल सुधार में भी भूल

झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री से गलती हो गई। उन्होंने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के लिए केंद्र या जम्मू-कश्मीर सरकार को नहीं, बल्कि हिमाचल सरकार को जिम्मेदार बता दिया। वहां के सीएम से इस्तीफा मांग लिया। वीडियो वायरल हुआ तो मंत्री को गलती का अहसास हुआ। तो मंत्री ने गलती को सुधारने के लिए सोचा। मीडिया को बुलाया और कहा कि उस दिन की भूल को सुधारना चाहता हूं। सुधारा भी, लेकिन इसमें भी मंत्री फेल हो गए और नई गलती कर बैठे। अबकी बार उन्हें जम्मू-कश्मीर तो याद रहा, लेकिन वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बदले महबूबा मुफ्ती से इस्तीफा मांग लिया। मीडिया फिर हैरान कि महबूबा क्यों इस्तीफा दें, वह तो विपक्ष की नेता भी नहीं। खैर मीडिया को मंत्री से खबर चाहिए थी, जो मिल गई थी। सुना है कि मंत्री अब तीसरी बार भूल सुधार का प्रयास कर रहे हैं।

राजरंग

तो नड्डा ही रहेंगे अध्यक्ष

मई के पहले हफ्ते में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया फिलहाल टल गई है। पहलगाम हमले के बाद भाजपा के बाकी बचे प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव रुक गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अभी पांच राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी है। साफ है कि तब तक जेपी नड्डा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। नड्डा का तीन साल का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही पूरा हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए 30 जून, 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। उसके बाद से अब लगभग एक साल होने वाला है, पर नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जेपी नड्डा की अध्यक्षीय पारी अभी जारी रहेगी।

वाह रे संवाद

अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बूथ स्तर तक अपना मजबूत ढांचा बनाने के लिए जिला संगठन में व्यापक बदलाव से लेकर कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की जोर-शोर से एक बार फिर घोषणा की। ऐसी पहल की उम्मीद से पार्टी के जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक रूप से आस जगती है, पर दिलचस्प यह है कि एक ओर जुड़ाव और संवाद बढ़ाने की घोषणा की जाती है तो दूसरी तरफ ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं का पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से मिलने-जुलने का मौका बिरले ही मिलता है। ऐसे में जमीन से जुड़े कांग्रेसी अपने क्षेत्र-प्रदेश में पार्टी की मजबूती के लिए शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिख कर कई अहम सुझाव देते हैं, मगर उनके पत्रों संज्ञान तक नहीं लिया जाता। अधिवेशन के चंद दिन बाद ही चार दशक से अधिक से कांग्रेस का झंडा उठा रहे बिहार के एक वरिष्ठ कांग्रेसी से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में अपने इस दर्द को साझा करते मिले। उनमें से एक ने तो कहा कि हिंदी में पत्र लिखने के बाद वह अपने जानकारों से उसका अंग्रेजी में अनुवाद करा कर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को कई बार भेजे, मगर आज तक उनका जवाब नहीं आया। ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने की घोषणा जमीन पर कितनी उतर पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।